3 राजधानी
अफगानी मांग रहे सभी देशों से शरण

6 अभिमत
शिक्षा के अधिकार पर जोर

11 विदेश
अफगानिस्तान को मदद देगा चीन

12 विविध
सफलता के लिए क्रैश कोर्स

RNI NO.DELHIN/2012/48369
वर्ष 9 अंक 284
नई दिल्ली, मंगलवार, 24 अगस्त, 2021
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
नगर संस्करण

नई दिल्ली, लखनऊ, रायपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com

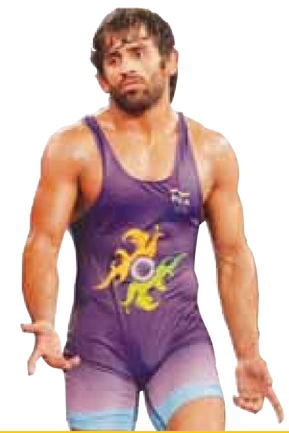

घुटने में चोट के कारण बजरंग विश्व चैंपियनशिप से बाहर
स्पोर्ट्स-10

रेल, हाइवे, ऊर्जा क्षेत्र की संपत्तियां बेचेगी सरकार

● अगले चार साल में विनिवेश से जुटाए जाएंगे 6 लाख करोड़ रुपए

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को छह लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय मौद्रिकरण योजना (एनएमपी) की घोषणा की। इसके तहत यात्री ट्रेन, रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डे, सड़कें और स्टेडियम का मौद्रिकरण शामिल हैं। इन बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निजी कंपनियों को शामिल करते हुए संसाधन जुटाए जाएंगे और संपत्तियों का विकास किया जाएगा। निजी निवेश हासिल करने के लिए चेन्नई, भोपाल, वाराणसी एंव वडोदरा सहित भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) के करीब 25 हवाई अड्डे, 40 रेलवे स्टेशनों, 15 रेलवे स्टेडियम और कई रेलवे कॉलोनी की पहचान की गई है। इन्हें निजी क्षेत्र के निवेश से विकसित किया जाएगा।

योजना के तहत, निजी कंपनियां इन्विट मार्ग का इस्तेमाल करके एक निश्चित मुनाफे के लिए परियोजनाओं में निवेश कर सकती हैं। इसके अलावा इन परिसंपत्तियों को सरकारी एजेंसी को वापस करने से पहले एक निश्चित अवधि के लिए परिसंपत्तियों का संचालन और विकास कर सकती हैं। इसके तहत गोदाम और स्टेडियम जैसी कुछ संपत्तियां भी संचालन के लिए लंबी अवधि के पट्टे पर दी जा सकती हैं। सीतारमण ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, संपत्ति मौद्रिकरण पाइपलाइन के जरिए एनआईपी (नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन) को अगले चरण में ले जाया गया है, जहां आप सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर ध्यान देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि संपत्तियों के मौद्रिकरण में जमीन को बेचा नहीं जाएगा। एनएमपी ब्राउनफील्ड (मौजूदा) बुनियादी ढांचा संपत्तियों से संबंधित है जहां निवेश पहले हो चुका है, जहां एक पूर्ण संपत्ति है जो या तो बेकार पड़ी है या जिसमें संभावनाओं का पूरा निवेश नहीं पाया है या जिसका क्षमता के अनुरूप इस्तेमाल नहीं हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा, इसलिए इसमें निजी भागीदारी लाकर, हम इसका बेहतर तरीके से मौद्रिकरण करने में सक्षम होंगे, और इसके माध्यम से हासिल होने वाले संसाधनों का बुनियादी ढांचे में और निवेश करने में सक्षम होंगे। एनएमपी के तहत वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक चार साल की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य संपत्तियों के माध्यम से छह लाख करोड़ रुपए की निवेश संभावनाओं का अनुमान है। उन्होंने कहा, बुनियादी ढांचा एनएमपी में पहले से मौजूद संपत्तियों की बात की जा रही है जिनका बेहतर मौद्रिकरण करने की जरूरत है। संपत्ति का स्वामित्व सरकार के पास बना रहेगा और एक निश्चित समय के बाद उनका नियंत्रण लौटाना अनिवार्य होगा। सीतारमण ने कहा, इसलिए ऐसी कोई अस्पष्टता नहीं रहनी चाहिए कि सरकार कुछ बेच रही है। ऐसा नहीं है। ये मौजूदा संपत्तियां हैं जिनपर सरकार का स्वामित्व बना रहेगा। मौद्रिकरण योजना का आधे से अधिक हिस्सा सड़क और रेलवे क्षेत्र से जुड़ा है। इसके तहत 1.6 लाख करोड़ रुपए का सबसे बड़ा हिस्सा इस समय चालू राष्ट्रीय राजमार्गों और नई सड़कों के 26,700 किलोमीटर के मौद्रिकरण से आएगा। इनमें से कुछ संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इन्विट (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) का रास्ता अपनाएगा। (शेष पेज 9)

नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

पुलिस बल में दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने कहा है कि पुलिस बल में दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं है। यह कहकर अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस में दाढी रखने पर रोक के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने याचिका दाखिल करने वाले सिपाही के खिलाफ जारी निलम्बन आदेश व आरोप पत्र में भी दखल देने से इंकार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने अयोध्या जनपद के खंडासा थाने में तैनात रहे सिपाही मोहम्मद फरमान की दो अलग-अलग याचिकाओं पर एक साथ पारित किया। पहली याचिका में पुलिस महानिदेशक द्वारा 26 अक्टूबर 2020 को जारी सर्कुलर के साथ-साथ याची ने अपने खिलाफ पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अयोध्या द्वारा पारित निलम्बन आदेश को चुनौती दी थी। वहीं दूसरी याचिका में विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही में याची के खिलाफ जारी आरोप पत्र को चुनौती दी गई थी। याची का कहना था कि संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत उसने मुस्लिम सिद्धांतों के आधार पर दाढी रखी हुई है। याचिका का सरकारी वकील ने विरोध किया। उन्होंने दोनों ही याचिकाओं के गुण-दोष पर सवाल उठाए। (शेष पेज 9)

अफगान संकट पर विपक्ष को साथ लेगा केंद्र, 26 को बैठक

● विदेश मंत्री एस. जयशंकर विभिन्न राजनीतिक दलों को देंगे अफगानिस्तान के घटनाक्रम की जानकारी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

भारत इस समय अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने में व्यस्त है। इस बीच, विदेश मंत्री एस जयशंकर 26 अगस्त को विभिन्न राजनीतिक दलों के संसदीय नेताओं के साथ बैठक कर युद्धग्रस्त देश के हालात और घटनाक्रम के बारे में अवगत कराएंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर यह बैठक पूर्वाह्न 11 बजे संसद भवन एनेक्सी में होगी। इस बारे में जोशी ने ट्वीट कर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संबंधित नेताओं को ईमेल के जरिए आमंत्रण भेजे जा रहे हैं और उनसे इस बैठक में शामिल होने का अनुरोध किया गया है।

जयशंकर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को यह जानकारी देने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय से कहा है कि वह विभिन्न पार्टियों के संसदीय दलों के नेताओं को इस संबंध में जानकारी दें। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी आगे की जानकारी देंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि केंद्र सरकार द्वारा अफगानिस्तान संकट पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेंगे। (शेष पेज 9)

तालिबान की अमेरिका को चेतावनी, सेना न हटायी तो भुगतने होंगे परिणाम

लंदन (भाषा)। अफगानिस्तान पर जी7 की आपात बैठक से पहले सोमवार को तालिबान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और ब्रिटेन युद्ध से जर्जर देश से अमेरिका नीत बलों की वापसी की तारीख 31 अगस्त से आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कतर की राजधानी दोहा में स्काई न्यूज से बातचीत में तालिबान के प्रवक्ता डॉक्टर सुहैल शाहीन ने कहा कि महीने के अंत में तय डेडलाइन अंतिम तारीख है और उसे आगे बढ़ाए जाने का मतलब होगा देश में उनका और ज्यादा दिनों तक रुकना। उन्होंने कहा कि यह समय सीमा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने तय की है और अगर ब्रिटेन तथा अमेरिका इसे आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। (शेष पेज 9)

गुरुग्रंथ साहिब की तीन प्रतियां, 75 लोगों को लेकर लौटा भारतीय विमान

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना का एक विमान युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से पवित्र गुरुग्रंथ साहिब की तीन प्रतियों और 75 लोगों को लेकर भारत लौट आया। इनमें 46 अफगान सिख और हिन्दू शामिल हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां से लोगों को बाहर निकालने में भारत सरकार के साथ समन्वय कर रहे लोगों ने सोमवार को उक्त जानकारी दी। लोगों को बाहर निकालने के प्रयासों में विदेश मंत्रालय और भारतीय वायुसेना के साथ सहयोग कर रहे संगठन इंडियन वर्ल्ड फोरम के अध्यक्ष पुनीत सिंह चंडोक ने बताया कि अब भी अफगानिस्तान में करीब 200 अफगान सिख और हिन्दू फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा, इन लोगों ने काबुल के करते पारवान गुरुद्वारे में शरण ली है, (शेष पेज 9)

कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर पंचतत्व में हुआ विलीन

पायनियर समाचार सेवा। अलीगढ़, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर का सोमवार को बुलंदशहर जिले के नरौरा में गंगा नदी के तट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कल्याण सिंह के पुत्र और एटा से भाजपा सांसद राजवीर सिंह ने जय श्री राम और कल्याण सिंह अमर रहे के नारों के बीच मुखाग्नि दी। कल्याण सिंह के पौत्र राज्यमंत्री संदीप सिंह भी मुखाग्नि प्रक्रिया में शामिल हुए।

कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर दोपहर बाद अलीगढ़ के अतरौली स्थित लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह से एक लंबे काफिले के साथ नरौरा पहुंचा। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को अलीगढ़ के अतरौली पहुंचकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शुमार किए जाने वाले कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनके निधन से दबे, कुचले और पिछड़ों ने अपना एक हितचिंतक गंवाया है। नरौरा घाट पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत उत्तराखंड के कई प्रमुख नेताओं ने कल्याण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित कर अंतिम विदाई दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत राज्य के कई प्रमुख नेता शव यात्रा के साथ लगातार बने रहे। (शेष पेज 9)

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को अंतिम विदाई देने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य नेता

सितंबर-अक्टूबर के बीच आ सकती है तीसरी लहर

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

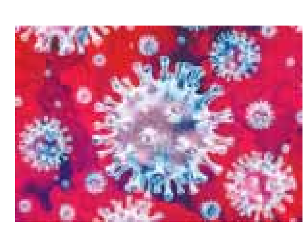

● विशेषज्ञ समिति ने चेताया, बच्चों को भी है बड़ों की तरह खतरा

केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले एक संस्थान की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने आशंका जताई है कि देश में सितंबर और अक्टूबर के बीच कभी भी कोविड-19 की तीसरी लहर आ सकती है। यदि इससे बचना है या इसके प्रभाव को कम करना है तो टीकाकरण की रफ्तार को काफी तेज करना होगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन (एनआईडीएम) की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने यह भी कहा है कि तीसरी लहर में बच्चों को वयस्कों के समान हड्डी जोखिम होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चों के संक्रमित होने की स्थिति में बाल चिकित्सा अस्पताल, डॉक्टर और उपकरण जैसे वेंटिलेटर, एम्बुलेंस आदि की उपलब्धता मांग के अनुरूप नही हो सकती है। प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सिर्फ 7.6 फीसदी (10.4 करोड़) लोगों का ही पूर्ण टीकाकरण किया गया है और अगर वर्तमान टीकाकरण दर में वृद्धि नहीं की गई तो भारत में महामारी की अगली लहर में प्रति दिन छह लाख मामले आ सकते हैं। रिपोर्ट कहती है कि प्रमुख विशेषज्ञों ने बार-बार भारत में कोविड-19 की आसन्न तीसरी लहर की चेतावनी दी है। महामारी विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की है कि जब तक हममें टीकाकरण या संक्रमण के जरिए व्यापक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो जाती, तब तक मामले बढ़ते रहेंगे। (शेष पेज 9)

सिद्धू के सलाहकारों के बयानों से कांग्रेस में बवाल

नई दिल्ली (पीएनएस)। कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के दो सलाहकारों की कथित विवादित टिप्पणियों के कारण पार्टी के भीतर एक नए सिरे से विवाद खड़ा हो गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने पार्टी नेतृत्व से इस पर आत्ममंथन करने का आग्रह किया कि क्या ऐसे लोगों को पार्टी में होना चाहिए, जो जम्मू-कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते और जिनका रुझान पाकिस्तान समर्थक है। दूसरी तरफ, कांग्रेस महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि इन लोगों की नियुक्तियां पार्टी ने नहीं की हैं, लेकिन अगर वो दोषी पाए गए तो उचित कार्रवाई होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री तिवारी ने ट्वीट किया, मैं कांग्रेस महासचिव एवं पंजाब के प्रभारी हरीश रावत से आग्रह करता हूं कि इसको लेकर गंभीरता से आत्ममंथन करें कि जो जम्मू-कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते और जिनका स्पष्ट रूप से पाकिस्तान समर्थक रुझान है, क्या उन्हें कांग्रेस की पंजाब इकाई का हिस्सा होना चाहिए? तिवारी ने यह दावा भी किया कि यह उन सभी लोगों का मजाक है, जिन्होंने भारत के लिए अपना खून बहाया है। (शेष पेज 9)

बिहार समेत देशभर में जाति आधारित जनगणना की मांग

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलने के बाद साउथ ब्लॉक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

जाति आधारित जनगणना के समर्थन में अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य के 10 दलों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उधर समाजवादी पार्टी ने भी जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया है। नीतीश ने बैठक के बाद कहा कि बिहार के सभी दलों ने जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता पर एक स्वर में बात की और जोर देकर कहा कि विभिन्न जातियों संबंधी आंकड़े प्रभावी विकास योजनाएं बनाने में मदद करेंगे क्योंकि उनमें से कई को उनकी वास्तविक जनसंख्या के अनुरूप अब तक लाभ नहीं मिला है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इस तरह की जनगणना राष्ट्रीय हित में है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कदम होगा और समाज के गरीबों एवं सबसे वंचित वर्गों की मदद करेगा। (शेष पेज 9)

बाजार

सेंसेक्स	55,556	↑ 226	
निफ्टी	16,497	↑ 46	
सोना	46,223	↑ 7	/10g
चांदी	60,864	↑ 377	/kg

क्विक न्यूज

आपत्तिजनक नारेबाजी में 20 के खिलाफ मामला दर्ज

खंडवा। मध्यप्रदेश के खंडवा में पुलिस ने ताजिया जुलूस के दौरान एक धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने के आरोप में लगभग 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक ललित गठरे ने बताया, 20 अगस्त को कोतवाली थाना क्षेत्र के तहत मुहर्रम के ताजिया जुलूस के लिए भीड़ जमा हुई थी। जुलूस में कुछ लोगों ने एक धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए। शिकायत के आधार पर कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नारे के बारे मे पूछे जाने पर उन्होने कहा कि ये हिन्दू धर्म के बारे मे थे। वीडियो फुटेज के आधार पर कुछ लोगों की पहचान की गई है। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ भादंवि की सम्बद्ध धाराओं मे मामला दर्ज किया है। उन्होने कहा कि 10-15 लोग इस कृत्य में शामिल थे और इनमें से पांच लोगों की पहचान की गई है।

स्मॉग टॉवर चालू, कनॉट प्लेस को नहीं सताएगा प्रदूषण

● सीएम केजरीवाल ने किया उद्घाटन, ट्रायल सफल होने पर पूरी दिल्ली में लगाने की तैयारी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने की तैयारी जोरों पर है। इस कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में देश के पहले स्मॉग टॉवर चालू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को इसका उद्घाटन किया। अमेरिकी तकनीक से बना यह स्मॉग टॉवर हवा में प्रदूषण की मात्रा को कम करेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई इस तकनीक के नतीजे बेहतर आए तो पूरी दिल्ली में ऐसे और स्मॉग टावर लगाए जाएंगे।

इस अत्याधुनिक एयर प्यूरीफायर अथवा स्मॉग टावर में 40 बड़े बड़े पंखे और 5000 फिल्टर लगे हैं, जो हवा को साफ करेंगे। अमेरिकी तकनीक से बना 24 मीटर ऊंचा यह स्मॉग टावर हवा में प्रदूषण की मात्रा को कम करेगा। यह वातावरण में आसपास के एक किलोमीटर के दायरे की हवा को खींचेगा और फिर उस हवा को स्वच्छ करेगा। इसके बाद इसमें नीचे लगे पंखे उस शुद्ध हवा को नीचे से बाहर छोड़ेंगे। इसकी क्षमता लगभग एक हजार घन मीटर प्रति सेकेंड है। यानी यह स्मॉग टॉवर एक हजार घन मीटर हवा प्रति सेकेंड साफ करके बाहर छोड़ेगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आसपास के एक किलोमीटर के दायरे के अंदर की हवा को यह साफ कर पाएगा।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दावा किया कि दिल्ली में पीएम-10 और पीएम-2.5 वर्ष 2014 से काफी कम हुआ है। राजधानी की हाबो-हवा दुरुस्त करने में आम आदमी पार्टी की सरकार का यह कदम मील का पत्थर साबित होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में दिल्ली ने देश के पहले स्मॉग टावर की शुरुआत की है।

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि आईटी दिल्ली और मुंबई के विशेषज्ञ इसके डाटा का विश्लेषण करेंगे और यह बताएंगे कि यह स्मॉग टावर प्रदूषित हवा को साफ करने में कितना प्रभावी है। अगर यह प्रयोग काफी प्रभावी होता है, तो फिर इस तरह के कई अन्य स्मॉग टावर पूरे दिल्ली में लगाएंगे।

मानसून सीजन खत्म होते ही पूरी क्षमता से करेगा काम

अभी यह स्मॉग टॉवर धीरे-धीरे चलेगा, लेकिन जैसे ही मानसून सीजन खत्म होगा और राजधानी पर प्रदूषण का खतरा मंडराएगा, इसे पूरी क्षमता के साथ चालू कर दिया जाएगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि जब यह आधुनिक एयर प्यूरीफायर अपनी फुल क्षमता से चलेगा तभी इसके सटीक नतीजे सामने आएंगे और हम आगे फैसला लेंगे।

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों ने दो आतंकी किए ढेर

पायनियर समाचार सेवा। श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोमवार को एक त्वरित अभियान में लश्कर-ए-तैयबा के एक छद्म संगठन द रेसिस्टेंस फोर्स (टीआरएफ) के दो शीर्ष कमांडरों को मार गिराया। ए शहर में कई लोगों की हत्या और युवाओं को हथियार उठाने के लिए गुमराह करने में शामिल थे। सबसे लंबे समय तक सक्रिय आतंकवादियों में से एक तथा टीआरएस का प्रमुख अब्बास शेख और उसका सहयोगी (डिप्टी) शाकिब मंजूर शहर के अलोची बाग इलाके में पुलिस के साथ संक्षिप्त मुठभेड़ में मारे गए। कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने संवाददाताओं को बताया, हमें इलाके में उनकी मौजूदगी की जानकारी थी। सादी वर्दी में पुलिस के जवानों ने तत्काल इलाके को घेर लिया और आतंकवादियों को ललकारा, जिन्होंने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। (शेष पेज 9)

देश में सामान्य से कम हो सकती है मानसून की वर्षा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

● दक्षिण-पश्चिम मानसून के अपने पूर्वानुमान को स्काईमेट ने घटाया

मौसम पूर्वानुमान लगाने वाली निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईमेट ने सोमवार को इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून के अपने पूर्वानुमान को घटा दिया है। स्काईमेट का मानना है कि मॉनसून सामान्य से कम रहने की 60 फीसदी संभावना है। जो लंबी अवधि के लिए 94 फीसदी के साथ औसत 880.6 मिमी वर्षा का अनुमान है। जून से सितंबर की अवधि के पूर्वानुमान में चार फीसदी कम या ज्यादा का अंतर संभव है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के अनुसार, भारत के 36 उप-मंडलों में से, अब तक 25 उप-मंडलों में कम वर्षा दर्ज हुई है। भारत में सामान्य बारिश 652.2 मिमी की तुलना में 594.5 मिमी बारिश हुई, जो अभी तक 9 फीसदी कम है। स्काईमेट वेदर के अनुसार भौगोलिक परिस्थितियों विषमताओं के लिहाज से गुजरात, राजस्थान, ओडिशा, केरल और पूर्वोत्तर भारत में कम बारिश होने की संभावना है। वहीं गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में सूखे की संभावना बनी हुई है। जबकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में वर्षा सिंचित क्षेत्रों में बारिश का स्थानीय वितरण पर्याप्त रहा है। वहीं देश के केंद्रीय कृषि उपज वाले भागों के खाद्य उत्पादन पर जोर नहीं दिया जा सकता है और ना इसे कम किया जा सकता है। स्काईमेट के प्रबंध निदेशक जतिन सिंह के अनुसार मानसून में कमजोरी संभवत: हिंद महासागर में आईओडी (दो ध्रुवों) के लंबे समय तक नकारात्मक चरण और जुलाई और अगस्त में विस्तार की स्थिति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। (शेष पेज 9)

पायनियर
नई दिल्ली, मंगलवार, 24 अगस्त, 2021

जेवर एयरपोर्ट की चारदीवारी बनाने का काम शुरू

एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम की बिल्डिंग व एयपोर्ट कार्यालयों का निर्माण भी साथ-साथ होगा

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

जेवर में प्रस्तावित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण स्विस कम्पनी ने शुरू करवा दिया है। साइट पर कम्पनी का अमला पहुंच गया है। कन्टेनर लगाकर अस्थाई दफ्तर और शेड्स बनाए गए हैं। टीम प्रोजेक्ट पर एकसाथ काम शुरू किया जाएगा।

एक तरफ पूरी परियोजना की बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी। दूसरी ओर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बिल्डिंग और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के कार्यालय का निर्माण शुरू किया गया है। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड परियोजना के लिए स्पेशल पर्पज वेहिकल है। जिसमें यमुना अथॉरिटी और स्विस कम्पनी हिस्सेदार हैं।

निर्माण शुरू करने पहुंची श्रमिकों की टीम ने खुद भूमि पूजन किया है। श्रमिकों ने नारियल फ ोड़कर निर्माण की शुरुआत की है। जानकारी मिल रही है कि अब काम शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाद में शिलान्यास करेंगे। अभी प्रधानमंत्री की व्यवस्ता के चलते समय मिल नहीं पा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच कार्यक्रम तय करने के लिए बातचीत चल रही है। जैसे ही प्रधानमंत्री का समय मिलेगा भूमि पूजन कर दिया जाएगा।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण दो समूहों के 6 हिस्सेदार मिलकर कर रहे हैं। इनमें एक सरकारी हिस्सेदारों का समूह है। दूसरा समूह प्राइवेट पार्टनर्स का है।

सरकारी समूह में उत्तर प्रदेश सरकार, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी शामिल हैं। दूसरे समूह में जूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी की भारतीय कम्पनी के साथ अब स्टेट बैंक ऑफइंडिया शामिल हो गया है। सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट के लिए 3725 करोड़ रुपए के वित्तपोषण को स्वीकृति दी है। यह पैसा कर्ज और इक्विटी के रूप में दिया गया है। जेवर एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहीत जमीन के लिए 96 करोड़ रुपये की स्टांप डयूटी लगी है। नियाल के चारों साझीदार यह रकम देंगे। सरकार को छोड़कर तीनों प्राधिकरणों ने अपने.अपने हिस्से का पैसा दे दिया है।

किस गांव के कितने परिवारों को मिले भूखंड

गांव	भूखंडों
1. नगला गणेशी	238
2. नगला छीतर	767
3. नगला फूलखा	175
4. नगला शरीफ	529
5. किशोरपुर	12
6. रोही	1039
7. दयानतपुर खेड़ा	243

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के पहले चरण के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की गई है। सरकार व नोएडा प्राधिकरण 37.5-37.5 प्रतिशत और ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण 12.5-12.5 प्रतिशत देगा। सरकार को छोड़कर अन्य हिस्सेदारों ने अपना-अपना पैसा दे दिया है। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की तिथि अभी तय नहीं है। हालांकि शिलान्यास से पहले काम शुरू हो गया है। इसके आधारशिला की तारीख बाद में तय की जाएगी।

शिलान्यास की तिथि सरकार स्तर पर तय होनी है। अभी इसको लेकर कोई हलचल नहीं है। उम्मीद है कि जल्द ही इसकी तिथि तय हो जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा।

अभी तक नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 5000 हेक्टेयर में बनाया जाना था। इसका क्षेत्रफल बढ़ाकर 5,845 हेक्टेयर कर दिया गया है। अब मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहालिंग हब भी एयरपोर्ट परिसर में ही विकसित किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे ने सेक्टर-30 और सेक्टर.31 की 845 हेक्टेयर जमीन भी एयरपोर्ट में समाहित कर दी है।

ग्रेटर नोएडा के 20 गांवों में बसेंगे आठ नए सेक्टर, खरीदी गई लगभग आधी जमीन

सीईओ ने गांवों में शिविर लगाकर जमीन लेने के दिए निर्देश

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

बीते कुछ वर्षों में औद्योगिक निवेश के लिए ग्रेटर नोएडा की तरफ उद्यमियों का रुझान तेजी से बढ़ा है। देश और विदेशों की कई कंपनियां ग्रेटर नोएडा में जमीन पाने के लिए आतुर हैं। उनकी मांग के अनुरूप जमीन उपलब्ध कराने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भी प्रयासरत है।

प्राधिकरण आठ नए औद्योगिक सेक्टर बसा रहा है। इसके लिए करीब 900 हेक्टेयर जमीन खरीद रहा है। प्राधिकरण अब तक आधी जमीन खरीद चुका है। शेष जमीन के लिए प्राधिकरण ने कोशिश और तेज कर दी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने बताया ने बताया कि शहर की तरफ उद्यमियों का रुझान बढ़ा है।

2021-22 में 1000 वर्ग मीटर से 20 एकड़ तक के 46 भूखंडों का आवंटन किया गया। इससे प्राधिकरण को करीब 268 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। 2000 करोड़ रुपये का निवेश और 8200 लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

कई और बड़ी कंपनियां भी ग्रेटर नोएडा में निवेश के लिए कदम बढ़ा चुकी हैं। उद्योगों के लिए जमीन की मांग को देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण के निर्देश पर आठ नए सेक्टर बसाने पर काम चल रहा है। ये सेक्टर ईकोटेक 7, 8, 9, 12ए, 16, 19, 19, और ईकोटेक 21 हैं।

इन सेक्टरों के लिए प्राधिकरण करीब 900 हेक्टेयर जमीन का इंतजाम में जुटा है। इन सेक्टरों के बसने से उद्यमियों को जमीन मिल सकेगी। इससे करोड़ो रुपये का निवेश और हजारों लोगों को रोजगार मिल मिल सकेगा।

निवेश मित्रा से मिल रहीं 30 सुविधाएं

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण निवेश मित्रा पोर्टल पर उद्योगों से जुड़ी करीब 30 सुविधाएं ऑनलाइन कर चुका है। उनसे जुड़े आवेदनों को ऑनलाइन ही निस्तारित भी कर देता है। इससे उद्यमियों को बहुत सहूलियत मिल जाती है। उनको प्राधिकरण दफ्तर नहीं आना पड़ता।

MOULIN COMMERCIAL LIMITED
CIN : L74899DL1982PLC067811; Ph. No: 9871374285; E-mail: kohli@vinylgroup.com
Regd. Off.: 1, Anand Gram, Aya Nagar, M G Road, New Delhi - 47
Corp. Off.: 11th Floor Vatika Tower B Sector-54, Golf Course Road Gurgaon - 122002

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter ended on 30th June, 2021

(In Lakhs)

Particular	Quarter ended (30.06.2021)	Year ended 31.03.2021	Quarter ended 30.06.2020
	Standalone		
Total Income from Operations (net)	27.95	89.77	22.67
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	8.10	10.39	4.44
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8.10	10.39	4.44
Net Profit/(Loss) for the period	5.70	5.00	2.97
Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]			
Paid-up equity share capital [Face value Rs. 10 per share]	57.30	57.30	57.30
Reserves (excluding revaluation reserves as Shown in the Balance Sheet of previous Year)	179.60	173.90	171.85
Earnings per share - (after extraordinary items) -(of Rs. 10/- each)	0.99	0.87	0.52
Diluted earnings per share- (after exceptional items)- (of Rs. 10/- each)	0.99	0.87	0.52

Notes: The above is an extract of the Standalone unaudited financial results of the Company for the quarter ended 30th June 2021. The detailed Standalone unaudited results for the three months ended on 30th June, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Lising and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone Financial Results for the three months ended on 30th June, 2021 are available on the Stock Exchange website.

For Moulin Commercial Limited
Sd/-
Ashish Gupta
Managing Director
DIN: 00115090

Place: Gurgaon
Date: 23.08.2021

पुलिस कप्तान ने चार थानों का किया औचक निरीक्षण

गाजियाबाद। जिले के नए पुलिस कप्तान पवन कुमार ने जिले के 4 थानों का औचक निरीक्षण किया और पुलिस स्टाफ को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही यदि थाने में आने वाले फरियादियों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न किया जाए। यदि इस प्रकार की कोई शिकायत मिली तो कड़ी कार्रवाई होगी।

जनपद के थाना मधुबन बापूधाम, ट्रॉनिका सिटी ,लोनी, टीला मोड का निरीक्षण किया गया। इस दौरान थाने के विभिन्न रजिस्टर, अभिलेखों, माल खाना, बैरक, भोजनालय आदि का निरीक्षण किया गया। अभिलेखों को सावधानीपूर्वक रखने, वांछित एवं सक्रिय अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने ,थाना परिसर में साफ सफाई और लंबित विवेचनाओं को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश भी दिए गए । इस मौके पर पुलिस कप्तान के साथ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर ईरज राजा भी मौजूद थे।

बाइक बोट घोटाला: 9 आरोपियों पर कोर्ट के आदेश पर एक और केस

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

बाइक बोट फर्जीवाड़े के नौ आरोपियों पर एक और केस दर्ज करने का गौतमबुद्ध नगर जिला अदालत ने आदेश दिया है।

बाइक बोट कंपनी में निवेश करने वाले एक पीड़ित ने संजय भाटी, उसकी पत्नी दीप्ति बहल, बीएन तिवारी, राजेश भारद्वाज, सुनील प्रजापति, सचिन भाटी, पवन भाटी, विजय कसाना, करनपाल नौ नामजद समेत अन्य आरोपियों पर 28 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है।

पीड़ित ने पुलिस के केस न दर्ज करने पर अदलत का दरवाजा खटखटाया था। अधिवक्ता आशुतोष शर्मा ने बताया कि गुरुग्राम निवासी रेलवे से सेवानिवृत पीड़ित निवेशक अमरजीत सिंह धालिवाल ने अदालत में दी गई शिकायत में कहा है कि उन्होंने गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लि. बाइक बोट कंपनी में लगभग दस लाख, उनकी सहकर्मी पूनम भारद्वाज ने लगभग 4.5 लाख रुपये निवेश किए थे।

आरोपियों ने ये रकम किश्तों में लगभग दोगुना कर लौटाने का आश्वासन व झांसा दिया था। लेकिन आरोपियों ने उनकी किश्त रोक दीं थी। किश्त वापस मांगने पर आरोपियों ने अग्रिम तिथि के लगभग 28 लाख से अधिक के चेक दिए थे। ये सभी चेक बैंक में बाउंस हो गए। रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दादरी कोतवाली और गौतमबुद्ध नगर के अधिकारी को भी शिकायत दी थी।

प्रवासी श्रमिकों के लिए रैन बसेरा बनाएगा प्राधिकरण

नोएडा। काम की तलाश में दूसरे जिलों और राज्यों से ग्रेटर नोएडा आने वाले श्रमिक वर्ग के लिए प्राधिकरण बड़ी योजना पर काम कर रहा है। इन सभी के लिए हॉस्टल और स्थाई तौर पर नाइट शेल्टर का प्रबंध किया जा रहा है।

सेक्टर इकोटेक-3 में श्रमिक हॉस्टल बनाए जाएंगे। यहां ठहरने वालों से बहुत कम शुल्क लिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने इस बारे में अफसरों को प्रक्रिया तेजी से पूरा कर निर्माण शुरू करने का आदेश दिया है।

इसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए दो ब्लॉक होंगे। जिसमें एक डाइनिंग एरिया, किचन, केयरटेकर ऑफिस, शौचालय, एक रिकॉर्ड रूम, एक चेक पोस्ट और एक कॉमन स्पेस होगा। पुरुषों के लिए 48 और महिलाओं के लिए 36 बेड होंगे। अभी शुल्क तय होना बाकी है। रैन बसेरा में पुरुषों और महिलाओं के लिए 48.48 बेड होंगे।

दिल्ली-मुंबई फ्रेट कॉरिडोर में भूमि अधिग्रहण में फंसा पेंच

आरओबी का निर्माण कार्य रुका

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

दिल्ली-हावड़ा डेडीकेटेड फ्रे ट कॉरिडोर पर आरओबी के निर्माण में बड़ी बाधा आ रही है।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट से लेकर दनकौर तक इस रूट पर 7 आरओबी बनाए जाने हैं, लेकिन दादरी की ओर रेलवे लाइन के साथ जमीन नहीं मिलने से इस प्रोजेक्ट में अड़चन आ रही है। जिला प्रशासन और राज्य सेतु निगम किसानों से जमीन खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब तक इसमें बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है। दरअसल किसान नए भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजा की मांग पर अड़े हैं। जबकि जिला प्रशासन, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तर्ज पर 3500 रुपये की दर से जमीन खरीदने का मन बना चुका है।

खींचतान की वजह से आरओबी का काम अधर में लटक गया है। सात आरओबी ग्रेनो से सीधे जीटी रोड से कनेक्ट होंगे। 6 लेन का आरओबी पल्ला बोड़ा की गांव के पास बन रहा है। यह सीधे परी चौक और जीटी रोड से कनेक्ट होगा।

एटलस ज्वैलरी इंडिया लिमिटेड ATLAS
सीआईएन : L74140DL1989PLC131289
पंजी. कार्यालय : जेए-710, 7वां तल, डीएलएफ टावर-ए, प्लॉट सं. 10, जासोला जिला, नई दिल्ली-110025
ई-मेल : info@atlasjewelleryindia.com, फोन : 011-40541077/41041149
वेब : www.atlasjewelleryindia.com

31वीं वार्षिक सामान्य बैठक, ई-वोटिंग जानकारी तथा बही बंदी की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि :

1. कम्पनी की 31वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("31वीं एजीएम") बृहस्पतिवार, 16 सितम्बर, 2021 को अप. 02.00 बजे आईएसटी, 31वीं एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण और विशेष व्यवसाय के निष्पादन हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 15 जून, 2020, 28 सितम्बर, 2020, 31 दिसम्बर, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021 ("एमसीए सर्कुलर्स") तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर दिनांकित 12 मई, 2020 तथा 15 जनवरी, 2021 ("सेबी सर्कुलर्स") के अनुपालन में, किसी उभय स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
2. एमसीए सर्कुलर/सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर के निबन्धनों में, 31वीं एजीएम की सूचना तथा वर्ष 2021 हेतु वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं ("वार्षिक रिपोर्ट") उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जा चुकी है, जिनका ई-मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट (पार्टिसिपैंट्स) के पास पंजीकृत है। सदस्यों को 31वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए सर्कुलर/सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर/सर्कुलर्स द्वारा समाप्त कर दी गई है।
3. वे सदस्य जो विच्छेदन तिथि **बृहस्पतिवार, 09 सितम्बर, 2021** को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयरों के धारक हैं, 31वीं एजीएम की सूचना में उल्लेखित साधारण तथा विशेष व्यवसाय के संबंध में अपना वोट सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") के जरिये इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचना दी जाती है कि :
   (i) 31वीं एजीएम की सूचना में उल्लेखित साधारण तथा विशेष व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा ;
   (ii) रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 13 सितम्बर, 2021 को (पूर्वा. 09.00 बजे आईएसटी) आरंभ होगी ;
   (iii) रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 15 सितम्बर, 2021 को (अप. 05.00 बजे आईएसटी) समाप्त होगी ;
   (iv) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अथवा 31वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा वोट डालने के अधिकार निर्धारण हेतु विच्छेदन तिथि बृहस्पतिवार, 09 सितम्बर, 2021 है ;
   (v) कोई व्यक्ति जो 31वीं एजीएम की सूचना भेजी जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और विच्छेदन तिथि बृहस्पतिवार, 09 सितम्बर, 2021 को शेयर धारक है helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि ऐसा व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल में पहले से पंजीकृत है, तब मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है ;
   (vi) सदस्यगण नोट करें –
      क) उपरोक्त तिथि और समय के बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी ;
      ख) सदस्यगण, जो 31वीं एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके हैं, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 31वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं, परंतु उनको 31वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी ;
      ग) 31वीं एजीएम में भाग ले रहा सदस्य, जिसने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, 31वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा वोट डालने का हकदार होगा ; तथा
      घ) कोई व्यक्ति, जिसका नाम विच्छेदन की तिथि को सदस्य पंजिका अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामी पंजिका में दर्ज है, वह रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ प्राप्त करने, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 31वीं एजीएम में भाग लेने तथा 31वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग का हकदार होगा ;
   (vii) एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.atlasjewelleryindia.com, सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com तथा बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।
   (viii) सदस्यगण से अनुरोध है कि एजीएम में भाग लेने एवं ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग करने के साथ संबंधित अपनी पूछताछ/शिकायतें, यदि कोई, helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल लिखें अथवा श्री राकेश दाल्वी (022-23058542/43) से सम्पर्क करें। वे www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स ("एफएक्यू'ज") तथा ई-वोटिंग मैनुअल भी देख सकते हैं।
   (ix) भौतिक रूप में शेयरों के धारक जिन सदस्यों का ई-मेल पता कम्पनी में पंजीबद्ध नहीं है, वे अपना ई-मेल पता एक हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति, नाम, फोलियो नंबर तथा पूरा पता वर्णित करते हुए, पैन कार्ड की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति तथा किसी दस्तावेज (जैसेकि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, निर्वाचन पहचान कार्ड, पासपोर्ट) की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति investor@atlasjewelleryindia.com को भेजकर पंजीबद्ध करवा सकते हैं। डीमैट रूप में शेयरों के धारक सदस्य अपना ई-मेल पता अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट के पास अद्यतन करवा सकते हैं।
4. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 विनियम 42 के अनुसरण में, कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां शुक्रवार, 10 सितम्बर, 2021 से बृहस्पतिवार, 16 सितम्बर, 2021 तक (दोनों तिथियों सहित) एजीएम के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी।

बोर्ड के आदेश द्वारा
वास्ते एटलस ज्वैलरी इंडिया लिमिटेड
हस्ता./-
(चन्दन महापात्रा)
कम्पनी सेक्रेटरी एवं सीएफओ

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 23 अगस्त, 2021

भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया चुनाव में सफलता का मंत्र

गाजियाबाद। स्थानीय जीटी रोड स्थित वेस्ट वीयू बैंकेट हाल में भाजपा की शहर विधान सभा कामकाजी बैठक आयोजित की गई।

आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव तैयारियों के लिए सफलता मंत्र दिए गए। बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, केंद्रीय राज्यमंत्री वीके सिंह, राज्यमंत्री अतुल गर्ग, महानगर प्रभारी महेन्द्र सिंह धनोरिया, प्रवीन पाठक ने दीप प्रज्जलित कर बैठक का शुभारंभ किया। बैठक में मंडल प्रभारी, मंडल महामंत्री, शक्ति केंद्र , सेक्टर संयोजक, वार्ड अध्यक्ष एवं वार्ड सचिव स्तर के पदाधिकारी और कोर कमेटी के कार्यकर्ता मौजूद थे ।

एचयूआईडी कानून के खिलाफ सर्राफा रहा बंद

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

केंद्र सरकार के एचयूआईडी कानून के खिलाफ गाजियाबाद में सर्राफा सर्राफा कारोबार आज पूरी तरह के बंद रहा, जिसके चलते 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार प्रभावित रहा। सर्राफा कारोबारियों ने नवयुग मार्किट में धरना भी दिया।

इस दौरान सर्राफा कारोबारियों ने चेतावनी दी कि यदि यह काला कानून वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। गाजियाबाद सर्राफा एसोसिएशन ने अपनी पूर्व घोषणा के तहत आज सुबह से भी सर्राफा कारोबारियों ने अपने प्रतिष्ठान बन्द रखे। घंटा घर, चौपला मंदिर, डासना गेट, दिल्ली गेट, गांधीनगर, रामनगर, अग्रसेन बाजार, रमते राम रोड, प्रताप विहार, विजय नगर, राज राजेंद्र, नगर लाजपत नगर, इंदिरापुरम, कौशांबी ,वैशाली,वसुंधरा आदि क्षेत्रों में 600 से ज्यादा सर्राफा व्यापार प्रतिष्ठान बंद रहे। इस दौरान गाजियाबाद सर्राफा एसोसिएशन के आह्वान पर तमाम कारोबारी नवयुग मार्केट में एकत्र हुए तथा धरने पर बैठे व्यापारियों ने ज्ञापन भी केंद्र सरकार को भेजा।

ज्वैलर ही नहीं, ग्राहक पर भी निगरानी : गर्ग

महामंत्री गौरव गर्ग ने कहा कि यूनिक एक ऐसी घातक योजना जिसके तहत सरकार सिर्फ ज्वैलर पर ही नही बल्कि हमारे कस्टमर तक की निगरानी चाहती है। यदि कोई कस्टमर हॉलमार्क ज्वैलरी ले रहा है तो सरकार ये समझ सकेगी कि ज्वैलरी किसने खरीदी है यानी अब उसके पास कितना सोना है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य ज्वैलर के साथ साथ हमारे ग्राहक के बारे मे भी जानकारी को जुटाना हम हॉलमार्क के खिलाफ नही है पर सरकार के अफसर कानून की आड मे हमारा उत्पीड़न करेंगे।

संक्षिप्त समाचार

चौधरी राजकुमार पैनल ने जारी किया घोषणा पत्र

नोएडा। नोएडा एम्पलॉयज एसोसिएशन के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। चौधरी राजकुमार पैनल ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में कर्मचारियों से जुड़े 20 मुद्दों को उठाया गया हैए जिनको पूरा कराने का आश्वासन राजकुमार पैनल ने दिया है। इस पैनल को एससी एसटी एसोसिएशन और नोएडा टेक्नीशियन वेलफेयर एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। घोषणा पत्र में मुख्य रूप से कर्मचारियों को आवंटित आवासीय भूखंड सेक्टर-5 को विश्वस्तरीय मूल सुविधाओं से लैस कराना, शासन द्वारा लागू की गई केंद्रीय कार्यनीति के अंतर्गत स्थानांतरण नीति से समूह-ग को अलग कराना, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति कर्मचारियों एवम वर्ष 2014 से नियुक्त मास्टररोल कर्मचारियों को यमुना प्राधिकरण में भूखंड आवंटित करवाया जाना, उधान विभाग के उधान पर्यवेक्षक के पद को पुन: सृजित करवाते हुए उधान चौधरी से पर्यवेक्षक पद पर पदोन्नति कराने जैसी मांगे शामिल हैं।

खेल मैदान पर पर्यावरण प्रेमियों ने किया पौधरोपण

गाजियाबाद। नेहरू युवा केंद्र को हरा भरा बनाने के लिए सोसायटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड बायोडायवर्सिटी नामक संस्था ने बीड़ा उठाया है। इस संस्था ने लगभग 100 पौधे इस मैदान पर रोपत किए है ,ताकि इस मैदान की पुरानी यादों को यादगार बनाया जा सके। इस मैदान पर पिलखन ,जामुन ,अमरुद ,सेमल , सेहजन आदि के पौधे रोपित किए गए हैं। संस्था के अध्यक्ष एवं जाने-माने पर्यावरणविद आकाश वशिष्ठ ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र शहर के मध्य स्थित है। इसके आसपास कोई भी हरित क्षेत्र नहीं है। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यहां पौधरोपण किया जाना बहुत ही लाभदायक है। इस अवसर पर वागीश शर्मा एडवोकेट ,संजीव शर्मा प्रदीप डाहलिया ,राजीव शर्मा एडवोकेट,आयुर्वेदाचार्य डॉ सुधींद्र शर्मा और नेहरू युवा केंद्र के सचिव जगत प्रकाश शर्मा की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय रही।

जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र के मैदान में पौध रोपण करते हुए पर्यावरण प्रेमी

सार्वजनिक सूचना

ICICI Bank

शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तृतीय तल, प्लॉट नंबर 23, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005

निम्नलिखित कर्जदार/रों ने उनके द्वारा बैंक से प्राप्त की गई ऋण सुविधाओं के मूलधन और ब्याज के भुगतान में चूक की है और ये ऋण अनार्जक आस्तियों (एनपीए) के रूप में श्रेणीबद्ध किए गए हैं। उनको, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अधीन एक सूचना उनके अंतिम ज्ञात पतों पर प्रेषित की गई थी, हालांकि यह सुपुर्द नहीं की जा सकी और इसलिए एतद्द्वारा उनको इस सार्वजनिक सूचना द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर का नाम (ऋण खाता संख्या) एवं पता	प्रत्याभूत आस्ति/प्रवर्तित की जाने वाली आस्ति का सम्पत्ति पता	प्रेषित सूचना की तिथि/सूचना की तिथि तक बकाया राशि	एनपीए तिथि
1.	कोन्नेक्शन इंडिया डॉटकॉम प्रा. लि., इसके निदेशकों नितिन काम्बोज एवं अमन साहनी द्वारा प्रतिनिधित्वकृत, प्लॉट नंबर 345, चतुर्थ तल, उद्योग विहार फेज-2, गुरूग्राम, हरियाणा, ऋण खाता सं. - 002105014346 एवं 002160000714 एवं 002160000752	यूनिट नंबर 524, 5वां तल, सिल्वरटन टावर, सेक्टर-50, ग्राम बादशाहपुर, गुरूग्राम-122001	28-06-2021 रू. 71,91,690/- एवं रू. 3,19,927.29/- एवं रू. 63,594.65/-	30-12-2020
2.	सिया ऑटो मार्केटिंग, राम लाल, मनीष कुमार ठाकुर, भागवंती, आई-1278/1, भू तल, मोहम्मद पुर, भीकाजी कामा प्लेस, निकट कम्युनिटी सेंटर, दिल्ली, ऋण खाता सं. - 1819050000328 एवं 181960000003 एवं 181960000001	प्लॉट नंबर 127, ब्लॉक जी, द्वितीय तल, जीवन निकेतन, एलआईसी कालोनी, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110056	03-06-2021 रू. 69,85,799/- एवं रू. 1,74,983/- एवं रू. 1,77,066/-	05-01-2021
3.	सैशा हॉस्पिटैलिटी प्रा. लि., भागवंती और मनीष कुमार ठाकुर, अंजू बाला, भू तल, सी-7, विशाल एन्क्लेव, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली, ऋण खाता सं. - 335951000001 एवं 335960000003	मकान नंबर 423, सेक्टर-6, अर्बन एस्टेट, बहादुरगढ़-124507	03-06-2021 रू. 95,06,767.84/- एवं रू. 2,68,793/-	05-01-2021
4.	मैसर्स शिवम ज्वैलर्स, 1166/310, कूचा महाजन I, चांदनी चौक, दिल्ली, ऋण खाता सं. - 629205027350 एवं 6292060003833	कृष्ण कुमार वर्मा और नर्मदा देवी की आवासीय सम्पत्ति मकान नंबर 65, एसएफ, ब्लॉक एएच, शालीमार बाग, दिल्ली-110088	03-06-2021 रू. 35,87,970/- एवं रू. 64,672.06/-	04-01-2021
5.	बुक्स साइबरटेक प्राइवेट लिमिटेड, शुब्रकान्त शादांगी, सत्यसाई पाणिग्रही, संजुक्ता शादांगी, सुचरिता महापात्रा, स्वागतिका शादांगी, ए-204, सन्नी वैली अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 27, सेक्टर-12, द्वारका, दिल्ली, ऋण खाता सं. - 025005000218 एवं 025060000011	एनए/205, नील चक्र अपार्टमेंट, लाल बहादुर शास्त्री रोड, भुवनेश्वर खोर्दा, भुवनेश्वर-751006	28-06-2021 रू. 30,51,348.13/- एवं रू. 1,30,958.83/-	07-12-2020
6.	मैसर्स वरदान इन्फ्राटेक प्रा. लि., द्वारा निदेशकगण राजीव अरोड़ा तथा शिवाली अरोड़ा, सी-107, शिवालिक, साकेत, नई दिल्ली, ऋण खाता सं. - 164705000318 एवं 164760000003	सम्पत्ति डी-83, सम्पूर्ण एफएफ, रियर साइड एसएफ, सम्पूर्ण टीएफ मय छत, ब्लॉक-डी, मालवीय नगर, नई दिल्ली	26-06-2021 रू. 2,45,47,210/- एवं रू. 4,82,830/-	31-12-2020

सूचना प्रदान करने हेतु वैकल्पिक कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त कर्जदार/रों तथा/अथवा उनके गारंटरों (जैसा लागू है) को बकाया राशि का भुगतान इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आगे वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, के प्रावधानों के अनुसार आगे कदम उठाए जाएंगे।

तिथि : 24-08-2021
स्थान : दिल्ली एनसीआर

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

दो झपटमार गिरफ्तार पांच मोबाइल बरामद

गाजियाबाद। गाजियाबाद पुलिस ने दो अलग-अलग स्थानों से दो शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 5 मोबाइल, तमंचा व स्कूटी बरामद की है।

पुलिस का दावा है कि यह दोनों ही शातिर किस्म के मोबाइल झपट मार हैं। साहिबाबाद थाना प्रभारी नागेंद्र चौबे ने बताया कि सादिक की पुलिया के पास रहने वाले अरमान को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि यह शातिर किस्म का अपराधी है ।

वन विभाग का 'ऑपरेशन नटखट' फेल

शहर में पांच हजार से भी अधिक उत्पाती बंदरों की टोलियां सक्रिय

अशोक निर्वाण। गाजियाबाद

वन विभाग के अड़यिल रवैया के कारण उत्पाती बंदरों को पकड़ने का ऑपरेशन नटखट दम तोड़ चुका है।

शहर में इस समय 5000 से भी अधिक उत्पाती बंदर तांडव मचा रहे हैं जिसके चलते बड़ी संख्या में बूढ़े बच्चे और जवान इन हिंसक बंदरों का शिकार हो रहे हैं, जबकि पिछले डेढ़ वर्षो में आधा दर्जन से भी अधिक लोग अपनी जान गवा चुके हैं। नगर निगम अपने खर्चे पर इन उत्पाती बंदरों को पकड़ने के लिए तैयार है , लेकिन करामाती वन विभाग इस मामले में बंदरों को पकड़ने की कार्यवाही को ठंडे बस्ते में डाल चुका है, नतीजतन शहर के लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। इस संबंध में रिफॉर्मिंग भारत ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी व देश के जानेमाने पर्यावरणविद आकाश वशिष्ठ और नगर निगम में भाजपा के मुख्य सचेतक पार्षद हिमांशु मित्तल ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के कार्यालय को एक कड़ा पत्र भेजकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है।

उत्पाती बंदर न केवल मानव जाति को अपना शिकार बना रहे हैं बल्कि गाजियाबाद की हरियाली को भी उजाड़ रहे हैं। जिसके चलते शहर के तमाम पर्यावरणविद बंदरों की इस हरकत से परेशान है।

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक नरेन्द्र कुमार द्वारा नं. 6, गुलाब भवन के पीछे, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड सी-9 सेक्टर-3, नोएडा-201301 (उ.प्र.) से मुद्रित। सम्पादक: चन्दन मित्रा, स्थानीय सम्पादक: प्रदीप तिवारी। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। पत्रवार्ता ऑफिस- एफ-31, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्धनगर-201301, उत्तर प्रदेश, दूरभाष- 120-4879800-4879900।

अफगानी मांग रहे सभी देशों से शरण

यूएनएचआरसी कार्यालय के बाहर सैकड़ों महिलाओं और बच्चों ने किया प्रदर्शन

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

प्रदर्शन करते बच्चे। फोटो रंजन डिमरी

राजधानी दिल्ली में रह रहे अफगान शरणार्थी दूसरे देशों के दूतावासों के बाहर रोजाना इस उम्मीद में खड़े हो जाते हैं कि शायद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत दूसरे देश उन्हें अपने यहां रिफ्यूजी का दर्जा दे दें।

इनमें से कुछ वो अफगानी महिलाएं भी हैं जिनके पति वहां की फौज में थे लेकिन तालिबान ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसी कड़ी में सोमवार को उन्होंने शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के बाहर सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने रोते हुए बताया कि भारत में कोरोना महामारी ने हालात ठीक नहीं है। वह यहां पिछले 11 सालों से रिफ्यूजी बनकर रह रही हैं लेकिन यहां अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अफगान शरणार्थियों की मांग है कि हम सभी को कनाड़ा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या कहीं ऐसी जगह भेजा जाए, जहां वहे अपना कारोबार और शिक्षा पा सकें। प्रदर्शनकारी एक महिला ने बताया कि कोविड-19 महामारी के समय सभी सरकारें अपने नागरिकों की मदद कर रही थी। भारत सरकार ने भी अपने लोगों की मदद की, लेकिन हमारे पास वैध दस्तावेज नहीं था । इसके चलते उन्हें राशन नहीं दिया गया। हमारी मांग है कि भारत सरकार हमारी मदद करें। हम लोग बहुत गरीब हैं। बड़ी मुश्किल से यहां आए हैं। यहां यूएनएचसीआर के बिना न वे काम कर सकती हैं, न बच्चों को पढ़ा सकती है।

अफगान समुदाय के प्रमुख अहमद जिया गनी ने कहा कि भारत में 21 हजार से अधिक अफगान शरणार्थी हैं। अब अपने वतन लौटने का कोई कारण भी नहीं है। उनके लिए भारत में न तो रोजगार है और न ही सुविधायें।

यहां रहते उन्हें पांच साल हो गये हैं, लेकिन उन्हें रिफ्यूजी कार्ड तक नहीं मिला है। सिर्फ एक कागज दिया है, जिसका कोई मतलब नहीं है। शरणार्थियों की मांग जब तक नहीं मानी जाएगी। तब तक वे यहां से नहीं जाएंगे।

ऑक्सीजन कमी से मौत मामला

कोर्ट ने सीबीआई व सरकार से छह सप्ताह में मांगा जवाब

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अप्रैल में जयपुर गोल्डन अस्पताल में कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी के कारण कोविड-19 के 21 मरीजों की मौत के मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने के अनुरोध वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार को केंद्र और दिल्ली सरकार को छह सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया।

अदालत दिल्ली के अस्पताल में 23 और 24 अप्रैल की मध्यरात्रि को जान गंवाने वाले कुछ मरीजों के परिवारों द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को सरकार के जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने मामले को नौ दिसंबर को के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा, तब तक चीजें साफ हो जाएंगी। हम देखेंगे। आपने मजिस्ट्रेटी अदालत का भी रुख किया है।

दिल्ली सरकार और केंद्र की ओर से पेश क्रमशः वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा और स्थायी वकील किरीटमान सिंह ने याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी।

भलस्वा में कूड़े का बड़ा हिस्सा गिरा, कई घर दबे

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

भलस्वा कूड़ा स्थल के एक हिस्से के ढहने से मलबे से कई झुग्गी व घर दबने से नुकसान पहुंचा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब साढ़े सात बजे भलस्वा कूड़ा स्थल (लैंडफिल) का एक हिस्सा ढह गया।

जानकारी के मुताबिक, इस बड़े हिस्से की चपेट में आकर कई घर मलबे में दब गए हैं, लेकिन इन घरों में रहने वालों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सूचना के बाद स्थानीय थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। फिलहाल इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है।

दिल्ली पुलिस और स्थानीय प्रशासन मिलकर मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। अच्छी बात यह रही है कि इसमें किसी की जान नहीं गई है।

फिलहाल नगर निगम के लोग मलबा हटाने में लगे हुए हैं। सोमवार सुबह भलस्वा डंपिंग साइट का कूड़े के ढेर से बना एक बड़ा भाग आसपास की झुग्गियों पर जा गिरा। अचानक से मलबा गिरने से लोगों के घरों के दरवाजे तक बंद हो गए।

भाजपा के दो पार्षद और कांग्रेस के कई नेता आप में

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

भाजपा के दो वर्तमान पार्षद और कांग्रेस के बड़े नेता पूरी टीम के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। भाजपा पार्षद पूनम पवन सहरावत और सविता नरेश खत्री, कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुरेश कुमार, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप शर्मा सैकड़ों सर्मथकों के साथ आप में शामिल हुए।

आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज, विधायक राजेश, विधायक शरद चौहान, विधायक जय भगवान उपकार और विधायक गिरीश सोनी की मौजूदगी में भाजपा-कांग्रेस के नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले साथी सीएम अरविंद केजरीवाल और क्षेत्र के विधायकों के साथ काम कर अपनी विधानसभा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। दिल्ली सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों और ढांचागत विकास पर बहुत काम कर रही है।

तीन नाबालिगों को देह व्यापार से मुक्त कराया

नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग ने नरेला इलाके में रहने वाली तीन नाबालिग बच्चियों को देह व्यापार और मानव तस्करी के रैकेट से मुक्त करवाया। तीन बच्चियों में से एक ने 181 पर कॉल करके बताया कि हलीमा नाम की महिला जो गांजे का व्यापार करती है उसने उसे काम दिलवाने के बहाने जिस्मफरोशी में झोंक दिया। पीड़ित लड़की ने बताया कि हलीमा इसी तरह गरीब बच्चियों को निशाना बनाती है और उनसे जबरन देह व्यापार करवाती है। दिल्ली महिला आयोग की टीम जब बच्ची से मिलने पहुंची तो वहां टीम ने पाया कि दो और नाबालिग लड़कियां हैं। जिनको हलीमा ने ऐसे ही फंसाया था। तीनों लड़कियों का परिवार बेहद गरीब है।

'सभी धार्मिक संगठनों को ध्वनि मानदंड की दी गई जानकारी'

- बैंक्वेट हॉल में लगाने होंगे आवाज नियंत्रण के उपकरण

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

राष्ट्रीय हरित अधिकरण को दिल्ली कंटोनमेन्ट बोर्ड ने बताया कि उसके क्षेत्र में आने वाले सभी मस्जिदों, मंदिरों, गिरजाघरों के अलावा सभी धार्मिक संस्थानों को ध्वनि मानदंडों के अनुरुप आवाज रखने के बारे में जानकारी दे दी गयी है।

उचित स्थानों और वेबसाइट पर नोटिस लगाकर ध्वनि प्रदूषण के संबंध में विस्तृत जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय निकाय ने कहा संगीत और अन्य उपकरणों के आवाज को सीमा में रखने की अनिवार्यता पर जागरुकता फैलाने को लेकर पिछले छह महीने में विस्तृत अभियान चलाया गया है। अधिकरण को सूचित किया गया कि व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित संगीत और ध्वनि उपकरणों का काम करने वाली सभी दुकानों को चिन्हित करके उनका निरीक्षण कर लिया गया है। सभी बैंक्वेट हॉल्स के लिए डीजे और अन्य ध्वनि उपकरणों में आवाज को नियंत्रित करने वाले उपकरण लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

द्वारका फ्लाईओवर का निर्माण रोकने की याचिका पर जवाब मांगा

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने द्वारका एक्सप्रेस-वे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य रोकने संबंधी दो ग्रुप हाउसिंग सोसायटीऔर कुछ अन्य निवासियों की याचिका पर को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति डी. वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की पीठ ने एनएचएआई और अन्य पक्षों को नोटिस जारी करके उन्हें शुक्रवार तक जवाब देने के निर्देश दिए ।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि एनएचएआई पहले से बनी हुई छोटी सड़क का फिर से निर्माण कर रहा है जो बेहद भीड़-भाड़ वाले आवासीय क्षेत्र से होकर गुजरती है।

'किसान आंदोलन का केंद्र-राज्य हल तलाशें'

- अदालत ने पूछा- सरकार क्या कर रही है, विरोध के कारण यातायात अवरुद्ध नहीं किया जा सकता

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के धरना-प्रदर्शन के कारण सड़क अवरूद्ध होने का समाधान केंद्र और दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को तलाशना चाहिए।

सुनवाई की शुरुआत में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति

ऋषिकेश मुखर्जी की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, मिस्टर मेहता ये क्या हो रहा है। आप समाधान क्यों नहीं खोज सकते? आपको इस समस्या का समाधान तलाशना होगा।

उन्हें विरोध करने का अधिकार है लेकिन निर्धारित स्थानों पर। विरोध के कारण यातायात की आवाजाही बाधित नहीं की जा सकती। पीठ ने कहा कि इससे टोल वसूली पर भी असर पड़ेगा क्योंकि अवरोध के कारण वाहन वहां से नहीं गुजर पाएंगे। मेहता ने पीठ को सूचित किया कि सड़क खुलवाने की मांग करने वाली नोएडा निवासी याचिकाकर्ता मोनिका अग्रवाल कनेक्टिविटी में समस्या के कारण उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वह किसी ग्रामीण इलाके में हैं।

पीठ ने आदेश दिया, समाधान करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों की है। उन्हें एक समाधान खोजने के लिए समन्वय करना होगा ताकि किसी भी विरोध-प्रदर्शन के कारण सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जाए ।

मेहता ने कहा कि अगर अदालत कोई आदेश पारित करने की इच्छुक है तो दो किसान संघों को पक्षकार बनाया जा सकता है और वह उनके नाम दे सकते हैं।

प्रदूषण से लड़ना सरकार की प्राथमिता नहीं : भाजपा

नई दिल्ली। स्मॉग टॉवर को लेकर भाजपा ने दिल्ली सरकार को घेरा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है प्रदूषण से लड़ना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता शुमार नहीं है। पिछले 7 साल से हर साल दीवाली बाद के 3 महीने या मई में घूल उड़ने से दिल्ली वाले प्रदूषण से खासे परेशान होते हैं।

केजरीवाल सरकार कनाट प्लेस में जिस पहले स्मॉग टॉवर लगाने का दावा कर रही है वह भ्रमक है। इससे पहले दिल्ली में 3 स्मॉग टॉवर गत वर्ष से काम कर रहे हैं।

पूर्वी दिल्ली से सांसद व पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर पिछले साल ही लाजपत नगर, गांधी नगर और तीसरा कृष्णा गर में लगवा कर जनता को समर्पित कर चुके हैं।

लेटलतीफ डायल 112 सेवा की 34 गाड़ियों के स्टाफ से जवाब तलब

संजय कुमार मेहरा। गुरुग्राम

किसी भी आपात स्थिति के लिए शुरू की गई डायल 112 सेवा के मौके पर पहुंचने के समय शहरी क्षेत्र में 15 मिनट व ग्रामीण क्षेत्र में 20 मिनट का दिया गया है। अगर गाड़ियां इससे देरी से पहुंचती हैं तो उनसे जवाब मांगा जाएगा। मिलेनियम सिटी में बीते एक सप्ताह में 34 गाड़ियां मौके पर देरी से पहुंचीं। विभाग द्वारा उनके स्टाफ से जवाब-तलब किया गया। साथ ही भविष्य के लिए ऐसी स्थिति नहीं होने के आदेश भी दिए हैं।

हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में पुलिस कंट्रोल रूम के 100 नंबर के स्थान पर अब डायल 112 सेवा शुरू की है। इस नंबर पर हर तरह की आपात स्थिति में संपर्क किया जा सकता है। बीते एक सप्ताह का रिकार्ड देखें तो पता चलता है कि डायल 112 सेवा में लगी 34 गाड़ियां सूचना मिलने के बाद तय समय से देरी से मौके पर पहुंचीं। पिछले सात दिनों में आई 1651 कॉल्स में 26 ऐसी कॉल्स भी थी, जहां ईआरवी को पहुंचने में 20 से 30 मिनट का समय लगा। वहीं 8 ईआरवी कॉलर्स के पास 30 से 40 मिनट में पहुंची। देरी से पहुंचने वाली डायल 112 सेवा में लगी सभी 34 ईआरवी पर तैनात पुलिसकर्मियों से विभागीय कार्रवाई के तहत स्पष्टीकरण मांगा गया। जिला मिरर कंट्रोल रूम के इंचार्ज डीएसपी टेलीकॉम रणबीर देशवाल के मुताबिक पुलिसकर्मियों को ओर से जवाब दिया गया कि बरसात के कारण यातायात बाधित होने से वे मौके पर देरी से पहुंचे।

जिला मिरर कंट्रोल रूम के डीएसपी टेलिकॉम ने दिया नोटिस

कहा, डायल 112 सेवा में देरी किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं

डायल 112 सेवा में लगी गाड़ी।

समय पर पहुंचना ही है इस सेवा की सार्थकता

डीएसपी टेलीकॉम रणबीर देशवाल का कहना है कि सभी गाड़ियों पर तैनात स्टाफ इस बात का विशेष ध्यान रखे कि कॉल आने के बाद जल्द से जल्द मौके पर पहुंचे। डायल 112 सेवा तभी सार्थक होगी, जब हम जनता को त्वरित सेवाएं देंगे। लेटलतीफी किसी भी तरह से असहनीय होगी। उन्होंने कहा कि डायल 112 सेवा को शुरुआत के समय इसके साथ एक नियम यह भी जोड़ा गया है कि त्वरित सेवा में विलंब होने पर संबंधित ईआरवी के स्टाफ से इसका स्पष्टीकरण भी लिया जाता है।

डायल 112 से 15 मिनट में पुलिस आपके पास पहुंचेगी

जिला में मिरर कंट्रोल रूम की कमान संभाल रहे डीएसपी टेलीकॉम रणबीर देशवाल ने बताया कि जिला में डायल 112 सेवा शुरू होने के उपरांत इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल यानि ईआरवी द्वारा लोगों को समय पर पहुंचाई जा रही है। लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास और बढ़ा है, वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली में भी काफी पारदर्शिता आई है। जिला गुरुग्राम में डायल 112 हेल्पलाइन पर कॉल करने वाले व्यक्ति को कम से कम समय में पुलिस मदद पहुंचाई जा रही है, जिसके लिए ईआरवी पर तैनात सभी पुलिस कर्मी सराहना के पात्र है।

एक सप्ताह में 1651 लोगों ने की कॉल

डायल 112 हेल्पलाइन के लिए शहरी क्षेत्र में 15 मिनट व ग्रामीण क्षेत्र में 20 मिनट के अंदर कॉलर तक पहुंचने की समय सीमा तय की गई है, लेकिन ईआरवी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने 80 प्रतिशत कॉलर्स तक मात्र 10 मिनट में पुलिस मदद पहुंचाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। कंट्रोल रूम में 16 अगस्त से 22 अगस्त के बीच जिला गुरुग्राम से 1651 कॉलर्स ने पुलिस सहायता के लिए कॉल किया। इसमे से 1307 कॉलर्स को ईआरवी 112 के तहत 10 मिनट में पुलिस मदद पहुंचाई गई। वहीं 310 कॉलर्स तक पहुंचने में ईआरवी 112 को तय समय सीमा के अंतर्गत 20 मिनट लगे।

पेड़ों को राखियां बांध बेटियां बोलीं...पेड़ों की भी करें रक्षा

पर्यावरण सुधार में परिवार के साथ पहले भी सक्रिय रही हैं ये बेटियां

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

अक्सर बेटियां, बहनें अपने माता-पिता, भाइयों से अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। रक्षाबंधन का पर्व इसी का प्रतीक है कि बहनें अपने भाइयों से अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। रविवार को यहां बेटियों ने अपनी रक्षा के साथ आमजन से उन बेजुबानों की रक्षा की भी मांग की, जिनकी वजह से हम शुद्ध और प्राकृतिक ऑक्सीजन लेते हैं। बेटियों ने पेड़ों को राखी बांधी और उनका जीवन बचाने का संदेश दिया।

गुड़गांव गांव की रहने वाली बेटियों कनिष्का, वंशिका, यशिका सुबह नये कपड़े पहनकर, हाथों में थाली और थाली में रोली व राखी लेकर पहुंचीं सेक्टर-4/7 चौक पर। वहां डिवाइडर के बीचों-बीच लगे पौधे को तीनों बेटियों ने पहले तिलक किया। उसके बाद राखी बांधी। बेटियों की इस सोच की राहगिरों ने तारीफ की। एक पेड़ को राखी का धागा बांधकर बेटियों ने समाज को बड़ा संदेश दिया है। जितने खराब वातावरण में हम सांस ले रहे हैं, वह हमें असमय विनाश की ओर ले जा रहा है। इसके लिए पीछे दोषी कोई और नहीं खुद इंसान ही हैं। हम सब हैं। विकास की आंधी की भेंट लाखों पेड़ चढ़ा दिए गए, जिससे धरती का संतुलन भी बिगड़ा है और पर्यावरण भी। जिन पेड़ों की बदौलत हम प्राकृतिक ऑक्सीजन लेते हैं, वह ऑक्सीजन काफी हद तक हमारी गलतियों से प्रभावित हो चुकी है। इसलिए हमें सिलेंडरों में बंद ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी है। कोरोना में जो हालात खराब हुए, वह हम सबके सामने हैं। बेशक सरकारें कोरोना काल में ऑक्सीजन से एक भी मौत ना होने का दावा करती हों, लेकिन कोरोना काल में जिस तरह से हमारी आंखों के आगे लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ा, वह कैसे छिप सकता है। ऐसी स्थिति भगवान ना करे फिर कभी हो, इसके लिए हमें कनिष्का, वंशिका, यशिका के दिये संदेश को समझना ना होगा। समझकर उसे जीवन में अपनाना होगा। पेड़ों को बचाना होगा। अगर हम अधिक से अधिक पेड़ ना लगा पाए और लगाकर उन्हें बचा ना पाए तो प्राकृतिक ऑक्सीजन के साथ सिलेंडर बंद ऑक्सीजन की कमी से आगे भी ऐसे ही जिंदगी से हारते रहेंगे। पर्यावरण के लिए काम करने वाले युवा राज सैनी बिसरवाल कहते हैं कि बेटियों के इस संदेश को जन-जन तक पहुंचाकर कंक्रीट के जंगलों के बीच पेड़ों के जंगल बनाने की अपील करेंगे।

गुरुग्राम के सेक्टर-4/7 चौक पर पेड़ को राखी बांधती बच्चियां।

रक्षाबंधन के त्योहार पर भाई को राखी बांधती एक बहन।

भाई-बहन का पवित्र त्योहार धूमधाम से मनाया

सोहना। रक्षा बंधन का त्योहार रविवार को धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने भाइयों को राखी बांधते हुए उनकी लंबी उम्र व जीवन में सफल होने की कामना की। भाई-बहन के प्यार का त्योहार रक्षा बंधन शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में धूमधाम से मनाते हुए बहनों ने भाइयों के जीवन में सफलता की कामनाएं की। इसके बाद रक्षाबंधन पर राखी बांधी। वहीं भाइयों ने बहनों के जीवन में अंतिम सास तक दुख की घड़ी में हमेशा ही साथ देने का भरोसा दिया। राखी के अवसर पर वाहनों में भारी भीड़ रही। सोमवार को भी बसों से लेकर ऑटो व अन्य वाहनों में जबरदस्त भीड़ रही। महिलाओं ने भीड़ के चलते बसों में खड़े होकर सफर किया। उमस भरी गर्मी से यात्रियों का वाहनों में पसीना से बुरा हाल रहा। सामान्य स्टैंड पर बसें अपने समय पर नियमित रुप से आती रही। लेकिन तुरन्त बसें भर रही थी और यात्रियों को गर्मी से बुरा हाल देख चालक अधिक देर नहीं लगा रहे थे।

धूमधाम से मनाया भाई-बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन

अपनी बहनों से राखी बंधवाते भाई।

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

भाई-बहन के प्रेम एवं आस्था का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व रविवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह से ही बहनों का अपने भाइयों के घर पहुंचना शुरु हो गया था। बहुत सी बहनें तो बीती रात ही अपने भाइयों के यहां पहुंच गई थी।

दूर-दराज के क्षेत्रों से महिलाओं ने अपने भाइयों के पास कॉरियर व डाक सुविधा के जरिये राखियां भेजी। बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधकर अपनी रक्षा का वचन लिया। शहर के बाजारों व मॉल्स में भी रक्षाबंधन के पर्व पर काफी रौनक देखने को मिली। उधर हलवाइयों की दुकानों पर भी मिष्ठान आदि खरीदने वालों की भीड़ भी रही। रोडवेज बसों का संचालन भी बड़े स्तर पर किया गया।

प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन के पर्व पर 36 घंटे के लिए महिलाओं व उनके 15 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई गई। रोडवेज बसों में सवारियों की इतनी भीड़ रही कि बहुत सी परेशान महिलाओं ने प्राइवेट बसों में सफर करना ही मुनासिब समझा। जिसके पीछे वजह रही कि बच्चों और सामान के साथ उनकी फ्री में सफर करने के चक्कर में परेशानी काफी बढ़ गई थी। ऊपर से रोडवेज की बसों में इतनी भीड़ थी कि बस में चढ़ने वाली महिलाओं को सीटें नहीं मिल रही थी।

बच्चों की उम्र को लेकर विवाद भी हुए

बहुत सी महिलाओं और कंडक्टर के बीच विवाद भी होने की सूचनाएं मिलीं। विवाद इस बात का कि महिलाएं अपने बड़े बच्चों को भी 15 साल से कम का बताकर फ्री सफर करने के चक्कर में थी। कंडक्टर इस बार पर अड़े रहे कि उनकी उम्र अधिक है और महिलाएं कम उम्र पर अड़ी रही। जब उम्र का सबूत मांगा तो महिलाएं कोई सबूत नहीं दिखा पाई। कंडक्टर ने कहा कि मोबाइल में आधार कार्ड होगा। काफी देर तक बहस के बाद आखिरकार कंडक्टर को ही शांत होना पड़ा। नाम न छापने की शर्त पर एक रोडवेज कर्मचारी ने बताया कि इस तरह की कई बसों के स्टाफ की ओर से शिकायतें उनके पास आई। इस त्योहार पर ज्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा। इसलिए ज्यादातर को नि:शुल्क ही सफर करवाया।

दिवेश कपूर बने पंचनद युवा संगठन के जिलाध्यक्ष

फरीदाबाद। पंचनद स्मारक ट्रस्ट ने युवा समाजसेवी दिवेश कपूर को पंचनद युवा संगठन का फरीदाबाद जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है।

इस नियुक्ति पर कपूर ने संगठन का आभार जताते हुए समाज की सेवा में पहले से अधिक योगदान देने की बात कही है। दिवेश कपूर ने बताया कि पंचनद स्मारक ट्रस्ट हरियाणा में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में संलग्न है। इस संस्था ने लोगों को देशभक्ति राष्ट्रभक्ति की ओर उन्मुख किया है। संस्था का उद्देश्य वर्ष 1947 के विभाजन में शहीद हुए 10 लाख शहीदों की याद में पंजाबी धाम बनाना भी है। जिसके लिए सभी प्रयासरत हैं। संगठन ने मुझे जिला फरीदाबाद का अध्यक्ष बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी है।

वन क्षेत्र में पेट्रोप पंप पर लगी अब सीबीआई की भी नजर

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

आमजन के हित का कोई काम हो तो अधिकारियों की खूब मिन्नतें करने के बाद भी वह काम सिरे चढ़ जाए जरूरी नहीं। नियम, कानून गिनाए जाने लगते हैं, लेकिन यहां एक नेता का पेट्रोप पंप लगवाने को अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर काम किया है। इसलिए अब सीबीआई को इस काम को रोकने के लिए पहल करनी पड़ी है। सीबीआई ने हरियाणा के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस पर कार्यवाही करने को कहा है।

गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-1 में वन विभाग के क्षेत्र में नगर निगम गुरुग्राम द्वारा पेट्रोप पंप लगाने को जगह आवंटित की गई। बताया जा रहा है कि यहां पर एक प्रभावशाली नेता का पेट्रोल पंप लगना है। इसलिए ना तो नगर निगम ने इस काम में कोई रोड़ा अटकाया और ना ही इंडियन ऑयल कंपनी की तरफ से। कंपनी की तरफ से ग्रीन बेल्ट में ही पंप आवंटित कर दिया गया। इसका खूब विरोध भी हुआ। यहां तक कि गुरुग्राम की मानव आवाज संस्था इस मामले को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) में भी लेकर गई। एनजीटी ने ग्रीन बेल्ट में पंप लगाने को गलत करार देते हुए गुरुग्राम के उपायुक्त को इस पर रिपोर्ट सौंपने को कहा। वन विभाग की ओर से जिला उपायुक्त को रिपोर्ट बनाकर दी गई कि यह पंप ग्रीन बेल्ट में लगाया जा रहा है, जो कि गलत है। नगर निगम इसके लिए कहीं और जमीन दे। इस रिपोर्ट से साफ हो गया कि यहां नियमों के खिलाफ जाकर पंप लगाने का प्रयास किया जा रहा है। बेशक एनजीटी ने पंप के लगने पर रोक लगा दी हो, लेकिन गुपचुप तरीके से पंप को लगाने का प्रयास अभी भी जारी है। इसे लेकर मानव आवाज संस्था फिर से सक्रिय हुई। संस्था के संयोजक एडवोकेट अभय जैन की ओर से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सीबीआई को तथ्यों के साथ शिकायत भेजी। इसे नियमों की उल्लंघना के साथ भ्रष्टाचार का भी मामला बताया। अब सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने इस पर संज्ञान लिया है। सीबीआई की ओर से पर्यावरण मंत्रालय और इंडियन ऑयल कारपोरेशन के चीफ विजिलेंस अधिकारियों को इस मामले में कार्रवाई करने को कहा है। हरियाणा के मुख्य सचिव को भी कहा गया है कि वन क्षेत्र में ही पेट्रोल पंप लगाने में अधिक दिलचस्पी दिखाई जा रही है। ऐसा क्यों। इस मामले में कार्रवाई करें।

सीबीआई ने हरियाणा के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर कार्रवाई करने को कहा

अभय जैन।

नेता के दबाव में नियम रखे ताक पर: अभय जैन : मानव आवाज संस्था के संयोजक एडवोकेट अभय जैन का कहना है कि प्रभावशाली नेता के प्रभाव के चलते वन विभाग के क्षेत्र में यह पेट्रोल पंप लगाने में अधिकारी जोर लगा रहे हैं। नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। एनजीटी के पूर्व में दिए गए आदेशों को भी दरकिनार किया जा रहा है।

15 मार्च 2019 को नगर निगम ने दी थी अनुमति : गुरुग्राम नगर निगम ने 15 मार्च 2019 को डीएलएफ फेज-1 में वन विभाग के 1500 स्क्वेयर मीटर क्षेत्रफल में पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति दी थी। एनजीटी में इस मामले में एडवोकेट रिषभ जैन एडवोकेट ने मानव आवाज की ओर से पैरवी की। जिस पर एनजीटी ने जिला उपायुक्त को जांच के आदेश देकर रिपोर्ट पेश करने को कहा। बीती 9 फरवरी 2021 को एनजीटी में इस मामले में आदेश पारित किए हैं कि गुरुग्राम नगर निगम ने वन विभाग क्षेत्र में पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति देकर गलत काम किया है।

संक्षिप्त समाचार

फोन लूटकर फरार हुआ युवक बाइक सवार

पलवल। खेत से घर आ रहे युवक से बाइक सवार व्यक्ति फोन को लूटकर फरार हो गया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर नामजद लुटेरे के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी वेदपाल के अनुसार सुजवाड़ी गांव निवासी रोहित ने शिकायत दर्ज कराई है कि में 22 अगस्त को फोन पर बात करता हुआ, अपने खेतों से घर आ रहा था। उसी दौरान चांदहट गांव निवासी अमीत बाइक पर पीछे से आया और हाथ से फोन को लूटकर फरार हो गया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

कई सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की हुई मौत, एक घायल

पलवल। चांदहट थाना क्षेत्र में अलग-अलग जगह हुई सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई। एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए व घायल को उपचार के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने पीड़ित परिजनों की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी वेदपाल के अनुसार नंगला गांव जिला कासगंज (यूपी) हाल निवासी पर्वतीय कालोनी निवासी करिश्मा ने शिकायत दर्ज कराई है कि मेरा भाई आकाश व उसका दोस्त योगेश निवासी इट्ठा गांव जिला कासगंज 21 अगस्त की रात 11 बजे स्कूटी पर सवार होकर गांव के लिए जा रहे थे। जब वह दोनों चांदहट चौक के समीप पहुंचे तो सामने से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से पीड़िता के भाई आकाश की मौत हो गई। पुलिस ने आकाश को शव को पोस्टमार्टम के लिए व घायल योगेश को उपचार के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। इसी प्रकार सिहोल गांव निवासी मानसिंह ने शिकायत दर्ज कराई है कि मेरा बेटा प्रेमसिंह 21 अगस्त की रात 9 बजे अपनी ड्यूटी से बाइक पर सवार होकर घर आ रहा था। जिसको किठवाड़ी गांव के समीप किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही पीड़ित परिवार के साथ मौके पर पहुंचा और घायल अपने पुत्र प्रेमसिंह को उपचार के लिए सिविल अस्पताल लेकर आया। जहां चिकित्सकों ने प्रेमसिंह को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

सीईओ ने शुरू किया फेसबुक पेज और ट्विटर एकाउंट

गुरुग्राम। नागरिकों में निर्वाचन एवं चुनाव प्रक्रिया के संबंध में समय-समय पर जानकारी उपलब्ध कराने व उनमें जागरूकता लाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि सीईओ हरियाणा ने अपना फेसबुक पेज व ट्विटर एकाउंट शुरू किया है। जिला उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. यश गर्ग ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा ने मतदाताओं को जागरुक करने के लिए फेसबुक पेज व ट्विटर एकाउंट की शुरुआत की है। निर्वाचन एवं चुनाव प्रक्रिया के संबंध में समस्त जानकारी समय-समय पर इन सोशल मीडिया हैंडल तथा पते पर उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा फेसबुक व ट्वीटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पेज व अकाउंट खोलने का मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी मतदाताओं को मतदान के लिए जागरुक करने के साथ-साथ निर्वाचन में उनकी सहभागिता को बढ़ाया जा सके। डॉ. गर्ग ने सभी जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी नागरिक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ट्विटर हैंडल व फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें, ताकि निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णयों के विषय में जानकारियां निरंतर प्राप्त होती रहें।

47 टीकाकरण केंद्रों पर लगेंगी कोविशिल्ड की दोनों डोज

गुरुग्राम। जिला गुरुग्राम में टीकाकरण अभियान के तहत मंगलवार को जिला के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में बने 54 टीकाकरण केन्द्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों को कोरोना रोधी टीका लगाया जाएगा। इन केंद्रों में से 47 पर कोविशिल्ड के पहले व दूसरे व पांच केन्द्रों पर कोवैक्सीन की दूसरी डोज के टीके लगाए जाएंगे। वहीं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े नागरिकों के लिए 16 स्कूलों में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिन नागरिकों को कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगवानी है, वह कम्युनिटी सेंटर चौमा, हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, गोविंद मंदिर बादशाहपुर सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिगरा व मानेसर में जाकर डोज लगवा सकते है। यहां संबंधित वैक्सीन के सौ स्लॉट उपलब्ध रहेंगे। शिक्षा, नौकरी के लिए विदेश जाने के लिए चयनित नागरिक सेक्टर-31 पॉलीक्लीनक में जाकर अपना कोविशिल्ड का दूसरा टीका लगवा सकते हैं। इस केंद्र पर वैक्सीन के 50 स्लॉट उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ ही इस स्वास्थ्य केंद्र पर स्पूतनिक वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जाएगी। यहां दूसरी डोज के रूप में 100 स्लॉट उपलब्ध रहेंगे। इसके अतिरिक्त जिन नागरिकों को कोविशिल्ड का पहला या दूसरा टीका लगवाना है। वह अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी कोरोनारोधी वैक्सीन लगवा सकता है। मंगलवार को सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन की पहली डोज के रूप में 200 व दूसरी डोज के रूप में सौ स्लॉट उपलब्ध रहेंगे।

तीन महीने से लापता युवती को पुलिस ने खोजा

फरीदाबाद। पुलिस के पास प्रतिदिन किसी न किसी के गुमशुदा होने की सूचनाएं प्राप्त होती है। इसी तरह से 12 मई के दिन थाना पल्ला में एक व्यक्ति ने आकर यह सूचना दी कि उनकी पुत्री घर से बिना बताये कहीं चली गई है। लड़की के पिता की शिकायत पर थाना पल्ला में मुकदमा दर्ज करके लड़की की जांच शुरू की गई। थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित कर लड़की को ढूँढने का प्रयास शुरू किया गया। पुलिस टीम के सदस्यों ने गुप्त सूत्रों व तकनीकी के आधार पर कड़ी मशक्कत करते हुए लड़की को फरीदाबाद एरिया से बरामद कर लिया है। परिजनों के सामने पुलिस ने उससे बिना बताये घर से जाने का कारण जानना चाहा तो लड़की ने बताया कि उसके अभिभावक उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं। इसी बात से वह नाराज होकर घर से चली गई थी।

एक चोर गिरफ्तार होने से सुलझे दो मामले

फरीदाबाद। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह के दिशा निर्देश पर कार्य करते हुए क्राइम ब्रांच सेक्टर 85 की टीम ने चोरी के दो मामलों में एक आरोपी को काबू किया है। गिरफ्तार आरोपी विकास जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है फिलहाल आरोपी फरीदाबाद के खेड़ी गांव में रह रहा है। प्रभारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 85 ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने इसी वर्ष अगस्त माह में थाना सेक्टर 31 एरिया और थाना भूपानी एरिया में दो चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। आरोपी के खिलाफ इन दोनों मामले संबंधित थाना में दर्ज हैं।

फार्म हाउस मालिकों को अदालत से मिला स्टे

पायनियर समाचार सेवा। सोहना

रायसीना से लगती अरावली अंसल में बने फार्म मालिकों ने वन विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिसों से लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सिविल कोर्ट ने चार फार्म हाउस मालिकों समेत अंसल अरावली रिट्रीट से जुड़े 165 सोसायटी सदस्यों की याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है।

वन विभाग ने रायसीना से लगती अरावली पहाड़ी में बनें फार्म हाउसों से लेकर शहरी क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर करीब 500 लोगों को नोटिस जारी किए है। यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी द्वारा दिए गए आदेशों की पालना करते हुए वन विभाग ने वितरण किए है। जिनका उद्देश्य 7 दिन के अंदर अवैध कब्जों को कब्जाई हुई जमीन को छोड़ना और अवैध निर्माण को हटाना है। इस कार्यवाही पर बीते सोमवार को सिविल कोर्ट सोहना द्वारा वन विभाग को एक बड़ा झटका दिया गया है। जैसे-जैसे वन विभाग द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं। नोटिसों के खिलाफ आम आदमी व फार्म हाउस मालिकों ने कोर्ट में जाना शुरू कर दिया है। जिसकी सुनवाई सिविल कोर्ट द्वारा की जा रही है।

सिविल कोर्ट ने 13 अगस्त को दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए तोड़फोड़ की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जबकि वन विभाग द्वारा नोटिस देने के बाद वन भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए तोड़फोड़ की कार्यवाही की जानी थी। इस बारे में जब वन राजिक अधिकारी सोहना अनिल कुमार ने बताया कि दो मामलों में उन्हें 12 अगस्त को 2021 को सम्मन प्राप्त हुए थे। जिसके पश्चात वे 13 अगस्त 2021 को कोर्ट में जाकर केस में हाजिर हुए। सिविल कोर्ट को इन केसों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बारे में अवगत कराया था।

उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि एनजीटी व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में ही नोटिस दिए गए हैं। वन विभाग द्वारा 8 फार्म हाउसों मालिकों की मौजूदगी में राजस्व विभाग द्वारा पैमाइश की गई थी। दो फार्म हाउस मालिक सुमन अरोड़ा व सुधीर अग्रवाल द्वारा अवैध रूप से वनभूमि पर फार्महाउस बनाया जाना साबित हो चुका है। मामले की अगली सुनवाई दिनांक 27 अगस्त को होगी। रेंज अधिकारी ने बताया कि इस मामले में उन्होंने उच्चाधिकारियों को सिविल कोर्ट सोहना द्वारा लगायी गई रोक के बारे में सूचित कर दिया है। इस स्टे ऑर्डर पर उनके विभाग द्वारा अपील दायर करने का काम किया जा रहा है।

वन विभाग स्टे ऑर्डर पर अपील दायर करने की कर रहा तैयारी

जिला टीबी फोरम और इंटरडिपार्टमेंटल कमेटी की बैठक में किए टीबी चैम्पियन सम्मानित

गुरुग्राम में जिला टीबी फोरम एवं इंटरडिपार्टमेंटल कमेटी की बैठक में टीबी चैंपियन को सम्मानित करते उपायुक्त।

गुरुग्राम। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में उपायुक्त डा. यश गर्ग की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागों व हितधारकों की बैठक आयोजित की गई।

उपायुक्त डा. यश गर्ग ने बैठक में टीबी उन्मूलन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों तथा हितधारकों को बेहतर तालमेल स्थापित करते हुए काम करने के लिए कहा। बैठक में जिन अधिकारियों की अनुपस्थिति रही, उन्हें उपायुक्त ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि गुरुग्राम एक बड़ा जिला है, ऐसे में जरूरी है कि टीबी उन्मूलन के लिए बेहतर कार्ययोजना बनाते हुए आपसी सहयोग से काम किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2025 तक हर हाल में देश को टीबी की बीमारी से मुक्त करवाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए जरूरी है कि समय रहते टीबी के मरीजों की पहचान कर उनका इलाज शुरू किया जाए।

घाटी में उतर रही कार में लगी आग, चालक बाल-बाल बचा

पायनियर समाचार सेवा। सोहना

तावडू जाने वाले मार्ग की घाटी में सड़क किनारे लावारिश खड़ी कार रविवार को जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया गया। 12 घंटा बीत जाने के बाद कार मालिक की पहचान हो गई। जिसने सिटी थाना में आकर अपनी कार में लगी आग की आप बीती बता दी।

रविवार की सुबह 5 बजे सोहना से तावडू जाने वाले मार्ग की घाटी में सड़क किनारे खड़ी कार आग में जल रही है। कार में आग को लगता देख राहगीर ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच अग्निशमन की गाड़ी को बुलाया। दमकल की गाड़ी से जब तक आग पर काबू किया जाता। तब तक कार 100 फीसदी जलकर राख हो चुकी थी। आग में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई थी। सिटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि रविवार की देर शाम कार मालिक की पहचान हो गई। कार मालिक मनीष मूलरुप से सदर थाना का गांव सरमथला का रहने वाला था। वह अब बल्लभगढ़ में रह रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि मनीष राजस्थान के शहर भिवाड़ी से आ रहा था। घाटी के मोड़ पर गाय सामने आ गई। जिसे बचाने के दौरान कार का संतुलन बिगड़ गया और वह सामने दीवार से जा टकराई। दीवार से टकराने के बाद कार में आग लग गई। लेकिन पांच बजे वह आग की चपेट में आई कार को छोड़ अपने घर चला गया।

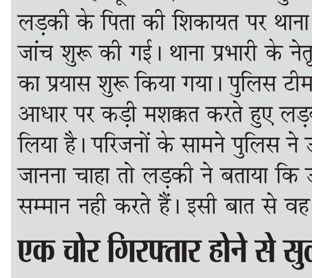
सोहना घाटी में आग झुलसी कार सड़क किनारे खड़ी हुई।

15 साल पहले इस स्थान से गिरा था टैंकर

करीब 15 वर्ष पहले अज्ञात चालक डीजल से भरे टैंकर को इस स्थान पर खडकर पहाड़ी से नीचे गिराने के बाद फरार हो गया था। इस टैंकर की कैबिन पहाड़ी पर खड़े पेड़ से रुक कई थी, लेकिन टैंकर आबादी क्षेत्र में मकान के परिसर में आकर गिरा था। जहां के नीचे आने से गाय व बच्चों की मौत हो गई थी।

गुड न्यूज : अब ईएसआई-8 में होगा वायरल लोड टेस्ट

कविता। फरीदाबाद

एचआईवी ग्रस्त मरीजों को अब वायरल लोड की जांच करवाने के लिए रोहतक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। क्योंकि अब वायरल लोड की जांच सेक्टर-आठ स्थित ईएसआई अस्पताल में मौजूद एआरटी सेंटर में शुरू हो चुकी है। जिसके लिए जिले में मरीजों को किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा। वहीं यह जांच प्रदेशभर में शुरू होगी।

यह जानकारी सेक्टर- आठ स्थित ईएसआई अस्पताल में मौजूद एआरटी सेंटर के इंचार्ज एवं हरियाणा ईएसआई डाक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. अखिल महाजन ने दी। उन्होंने बताया कि यह जांच बाहर से महंगे दाम पर होती है और यदि सरकारी अस्पताल में करवाने के लिए केवल रोहतक ही मरीजों को भेजा जाता है, लेकिन अब मरीजों की परेशानी खत्म हो गई है।

ये है वायरल जांच

डॉ. महाजन ने बताया कि जब किसी व्यक्ति को एड्स होता है तो एचआईवी के वायरस सीधे सीडी 4 कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। वायरल लोड टेस्ट रक्त में ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियेंसी वायरस (एचआईवी) की मात्रा का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी संक्रमण के दौरान हो रहे बदलावों का पता लगाने के लिए इसे किया जाता है।

उन्होंने कहा कि एचआईवी प्रतिरक्षा प्रणाली की कुछ विशेष कोशिकाओं, सीडी 4, को लक्ष्य बनाकर उन्हें नष्ट करता है। सीडी4 बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं जैसे वैक्टीरिया और वायरस से लड़ता है, जो संक्रमण होने के खतरे को अत्याधिक बढ़ा देते है और व्यक्ति बार-बार बीमार पड़ने लगता है। प्रतिरक्षा प्रणाली की शक्ति का पता लगाने के लिए इस जांच के साथ सीडी 4 जांच करवाने को कहा जा सकता है। सीडी 4 काउंट का कम होना मरीज के कमजोर इम्यून सिस्टम को दर्शाता है। जिससे मरीज किसी अन्य संक्रमण की चपेट में बहुत जल्दी आ सकते हैं।

हो जाएगा सरल

डॉ. अखिल महाजन ने बताया कि मरीजों के लिए वायरल लोड जांच बाहर से 10 हजार रुपये में की जाती है। वहीं उन्होंने बताया कि सीडी4 जांच प्रदेश में केवल रोहतक में ही फ्री की जाती है, लेकिन वहां जाकर जांच करवाने के बाद रिपोर्ट आने में काफी समय लग जाता था। ऐसे में मरीजों को कई दिनों बाद रिपोर्ट मिलती थी, लेकिन अब यहां जांच शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि 26 अगस्त को मुम्बई की लैब से पहली बार विशेषज्ञ आ रहे हैं। जो इसकी जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने सारी तैयारियां स्वयं की है। ताकि यहां से सैम्पल मुम्बई भेजे जाए और जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द मरीजों को जिले में ही उपलब्ध हो सके।

आज शुरू होगी दो दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल

फरीदाबाद। 24 अगस्त से दो दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल शुरू करेंगे 25 अगस्त तक रहेगी जारी नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने हरियाणा सरकार पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों की न्याय उचित मांगों को अनदेखा अनसुना कर रही है। वहीं 25 अप्रैल व 17 अगस्त 2020 को समझौतों में मानी गई मांगों को भी पूरा नहीं कर रही है। सरकार के इस नकारात्मक रवैया से रुष्ट कर्मचारी राज्यव्यापी आंदोलन करने के लिए मजबूर है। शास्त्री ने कहा कि क्रमिक भूख हड़ताल की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।

नगर निगम : 200 करोड़ के घोटाले की स्पेशल ऑडिट का आदेश

परिवहन मंत्री बोले घोटाले की जांच स्टेट विजिलेंस ब्यूरो कर रहा है

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

राज्य सरकार ने आखिरकार विधानसभा में यह घोषणा कर दी है कि फरीदाबाद नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए निगम में स्पेशल आडिट कराया जाएगा। मानसून सत्र में सोमवार कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा द्वारा प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि फरीदाबाद नगर निगम में बिना काम ठेकेदार सतबीर सिंह को किए गए भुगतान घोटाले की जांच स्टेट विजिलेंस ब्यूरो कर रहा है। इसकी जांच रिपोर्ट के बाद आरोपित अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा के कथन को आगे बढ़ाते हुए भाजपा विधायक नरेंद्र गुप्ता ने सदन में मौजूद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मांग की कि नगर निगमों में हुए भ्रष्टाचार के साथ गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) की जांच भी कराई जाए। इससे नगर निगम, ठेकेदार और उनको माल आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अदा किए गए जीएसटी के आंकड़ों के आधार पर जांच में आसानी रहेगी।

बता दें, सात जुलाई 2020 को फरीदाबाद नगर निगम के पार्षद महेंद्र सिंह, सुरेंद्र अग्रवाल, दीपक यादव, दीपक चौधरी ने लेखा विभाग से मिली जानकारी के आधार पर निगमायुक्त को पत्र लिखकर बताया कि जिन कार्यों की एवज में निगम ठेकेदार को भुगतान कर चुका है, वे कार्य उनके वार्ड में हुए ही नहीं हैं। निगमायुक्त ने पार्षदों की इस शिकायत पर नौ जुलाई 2020 को जांच के लिए फरीदाबाद नगर निगम के संयुक्त आयुक्त, मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी की कमेटी गठित कर दी। बाद में पार्षदों की मांग पर इस कमेटी में उप महापौर और पार्षद अजय बैसला को भी शामिल कर लिया गया। मुख्य अभियंता ने 18 नवंबर 2020 को इसकी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसमें 23,79,72,990 रुपये की नगर निगम को वित्तीय हानि हुई। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निगमायुक्त ने जेई दीपक कुमार को निलंबित कर दिया और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी राजन तेवतिया, बपंकज, तसलीम और प्रदीप की सेवाएं समाप्त कर दी। निगमायुक्त ने कमेटी की रिपोर्ट पर राज्य सरकार से मुख्य अभियंता डीआर भास्कर, लेखाधिकारी विशाल कौशिक सहित ठेकेदारों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने की सिफारिश की। निगमायुक्त ने 19 मार्च 2021 को एफआइआर के लिए सरकार से सिफारिश की मगर सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया।

विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि स्पेशल आडिट कराने की घोषणा सरकार पहले भी कर चुकी है। विधानसभा में मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि बिना काम भुगतान घोटाले के अलावा अन्य भ्रष्टाचार के मामलों को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। नगर निगम के आयुक्त द्वारा घोटाले में लिप्त तीन अधिकारियों पर एफआइआर दर्ज कराने की संस्तुति की गई है मगर अभी तक सरकार ने तक सुनवाई नहीं की है।

कोरोना : एक पॉजिटिव से एक्टिव केस 12

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

जिले में कोरोना वायरस का पॉजिटिव एक मामला सोमवार को सामने आया हैं। जबकि एक अच्छी खबर यह भी है कि कोविड संक्रमण के दो मरीज ठीक हो कर अपने घर में भी लौट गए हैं। वहीं सोमवार को जिले में रिकवरी रेट भी 99.27 प्रतिशत पर पहुंच गया है।

वहीं जिले में फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 12 है। जिसमें तीन पॉजिटिव मरीज विभिन्न अस्पतालों में दाखिल हैं। वहीं होम आईसोलेशन पर जिले में नौ लोगों को रखा गया हैं। जिला में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए टेस्टिंग और वैक्शीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। जिले में पिछले 24 घंटे में 1271 लोगों के टेस्ट किए गए।

ये हैं आंकड़े

अब तक कुल जांच	: 1058611
अब तक पॉजिटिव	: 99820
अब तक नेगेटिव	: 958070
रिपोर्ट आनी शेष	: 74
ऑक्सीजन पर है	: 01
अब तक मौत	: 716
अब तक ठीक	: 99092

मंच ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का किया स्वागत

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने उच्चतम न्यायालय के एक फैसले, कानून इजाजत दे रहा है, सिर्फ इसीलिए किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते का स्वागत करते हुए कहा है कि पुलिस अधिकारी सीपीआरसी की धारा 170 का दुरुपयोग न करें और इस धारा को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई स्पष्ट राय व फैसले का सम्मान करें।

मंच के प्रदेश अध्यक्ष व वरिष्ठ एडवोकेट ओपी शर्मा ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि किसी मामले में आरोपी की गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब मामला गंभीर अपराध से जुड़ा हो या आरोपी के गवाह को प्रभावित करने या फिर आरोपी के भागने का अंदेशा हो। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि सिर्फ इसलिए कि कानून में गिरफ्तारी का प्रावधान है आरोपी को गिरफ्तार करना जरूरी नहीं है। गिरफ्तारी की शक्ति होना और गिरफ्तारी की अनिवार्यता का जस्टिफिकेशन होना अलग बातें हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अगर रूटीन प्रक्रिया में आरोपियों की गिरफ्तारी की जाने लगी तो इससे मान प्रतिष्ठा वाले लोगों की मान प्रतिष्ठा की जो हानि होगी उसका आकलन मुश्किल है। मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा व ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन आईपा के जिला अध्यक्ष एडवोकेट बी एस विरदी ने उच्चतम न्यायालय के गुरुवार को दिए गए फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल की अगुवाई वाली बेंच ने 83 प्राइवेट लोगों द्वारा मांगी गई अग्रिम जमानत की सुनवाई के दौरान कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने यह मत दिया है सीआरपीसी की धारा 170 के तहत चार्ज शीट के समय आरोपियों की कस्टडी जरूरी है इस पर बेंच ने कहा है ऑफिसर इंचार्ज पर सीपीआरसी की धारा 170 यह दायित्व नहीं डालता कि चार्जशीट के वक्त आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। धारा में कस्टडी शब्द का इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब ये नहीं है की पुलिस कस्टडी या ज्युडीशियल कस्टडी। इसका मतलब है कोर्ट के सामने पेशी।

सरकारी स्कूलों के छात्रों के खाते में बिना देरी आएगी भत्ता राशि : डीसी

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिलने वाले सरकारी भत्ते बिना देरी के सीधी आनलाइन खाते में आएंगे। उपायुक्त जितेन्द्र यादव ने बताया कि पोर्टल पर विद्यार्थियों के खाता नंबर गलत हैं जो कि अभी विद्यार्थियों के जो खाते पीएफएमएस पोर्टल पर दर्शाए गए हैं उनमें से अधिकतर के अकाउंट नंबर भी ठीक नहीं हैं।

बैंक मर्ज होने के कारण आईएफएससी कोड बदलने से भी दिक्कत आ रही है। इससे भी इन बच्चों के खाते में समय पर सरकारी भत्ते नहीं आ पा रहे हैं। उपायुक्त ने बताया कि अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड में से अगर एक भी संख्या गलत होगी तो मिसमैच का मैसेज आएगा। जिससे विद्यार्थी खाते में पैसे आने से वंचित हो रहे है। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के बैंक खातों के अकाउंट वेरिफिकेशन पोर्टल बनाया है। उन्होंने बताया कि पीएफएमएस डाटा यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पर जो डाटा है, वह दुरुस्त नहीं है। जिसके चलते विभाग ने नया पोर्टल बनाया है। इस पर जो डाटा अपलोड होगा वह पहले अपडेट किया जाएगा।

खण्ड शिक्षा अधिकारी बलबीर कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की हिदायतों के अनुसार स्टूडेंट अकाउंट पोर्टल शिक्षा विभाग ने बनाया है। इस पर सभी विद्यार्थियों के अपडेट अकाउंट अपलोड किए जाएंगे। इसके बाद सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सरकार की तरफ से दिए जाने वाले भत्ते बिना देरी के खाते में आएंगे। खण्ड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सरकार की ओर से भत्ता व प्रोत्साहन राशि में कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी श्रेणी के छात्रों के लिए निशुल्क वर्दी योजना है। इसके साथ ही पहली से पांचवीं तक के 800 रुपये प्रति विद्यार्थी दिए जाते हैं। छठी से आठवीं तक के एक हजार रुपए प्रति विद्यार्थी नॉन एससी छात्र को मुफ्त स्कूल बैग मिलते हैं। पहली से पांचवी तक के 120 रुपये प्रति विद्यार्थी दिए जाते हैं। छठी से आठवीं तक के 150 रुपये प्रति विद्यार्थी नॉन एससी छात्र को मुफ्त लेखन सामग्री दी जाती है। उन्होंने आगे बताया कि पहली से पांचवीं तक के 100 रुपये प्रति विद्यार्थी सरकार द्वारा दिए जाते है। उन्होंने बताया कि इससे ऊपर की क्लास में भी छात्रवृत्ति आती है। पोर्टल अपडेट होने से पात्र विद्यार्थियों को सरकार की ओर से भेजी गई राशि समय से खाते में मिल जाएगी। नए पोर्टल पर अपडेट नंबर अपलोड होंगे। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग ने जो नया पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल पर अध्यापक बच्चों के सही खाते नंबर सही आईएफएससी कोड के साथ अपलोड करेंगे, इस प्रकार के आदेश मुख्यालय से आए हैं।

नगर निकाय चुनाव के देवेन्द्र चौधरी हुए प्रभारी नियुक्त

फरीदाबाद। वरिष्ठ उपमहापौर देवेन्द्र चौधरी को नगर निकाय चुनाव के लिए पलवल व गुरुग्राम का प्रभारी नियुक्त होने पर भाजपा युवा मोर्चा के खेड़ी मंडल महामंत्री अरविन्द चंदीला ने उनके कार्यालय पर उन्हें मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। उपमहापौर मनमोहन गर्ग, पार्षद अजय बैसला, चेयरमैन विनोद चौधरी, वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश तोमर, पार्षद मनोज नासवा एवं अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता और युवा साथी मौजूद रहे। अरविन्द चंदीला ने कहा कि देवेन्द्र चौधरी के उचित मागदर्शन में पार्टी पलवल और गुरुग्राम के निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि देवेन्द्र चौधरी की सूझबूझ से विरोधी पाटियों के मनसूबे फेल होंगे और दोनों जगह भाजपा का परचम लहराएगा।

बीमारियों की रोकथाम में जनता का सहयोग अपेक्षित : डीसी

कहा, बचाव के लिए प्रत्येक नागरिक बरतें सावधानियां

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

उपायुक्त जितेंद्र यादव ने कहा कि गर्मी व बरसात के मौसम में अनेकों जानलेवा बीमारियां फैलने की आंशका बनी रहती है और इन बीमारियों को शुरू से ही पनपने से रोकने के लिए सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है ताकि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रह सके।

उपायुक्त ने जिला के लोगों से अपील की है कि हमेशा स्वच्छ पानी का सेवन करें। खाना खाने से पहले व बाद में और शौच जाने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। पीने के पानी के स्रोतों के पास शौच न करें। सडे-गले, कटे हुए फल व बासी खाद्य पदार्थों को न तो खरीदें तथा न ही प्रयोग में लाएं। उपायुक्त जितेंद्र यादव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जानलेवा बीमारियों की रोकथाम के लिए भरपूर कोशिश करता है फिर भी जनता के सहयोग के बिना यह कार्य सम्भव नहीं है। उन्होंने जिला की जनता से अपील की है कि वे इन बीमारियों से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर बताए गई बातों पर अमल अवश्य करें और जानलेवा बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग को अपना पूर्ण सहयोग दें। उन्होंने बताया कि नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 से बचने के लिए सभी फेस मास्क अवश्य पहनें। सभी छह फुट की सामाजिक दूरी बनाए रखें। अपने हाथों को बार-बार साबुन से अच्छी तरह धोएं। उपायुक्त ने कहा कि खाने व पीने की चीजों को हमेशा ढक कर रखें। घरों में पानी की टंकियों की सफाई समय-समय पर अवश्य करें। उल्टी, दस्त लगने पर ओआरएस घोल व नमक का घोल पर्याप्त मात्रा में लें तथा नजदीकी सरकारी हस्पताल में जाकर अपनी जांच एवं इलाज करवाएं। उन्होंने बताया कि बुखार होने पर खून की जांच करवाएं।

उपायुक्त ने कहा कि घरों के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें तथा नालियों को साफ रखें तथा गड्ढों को मिट्टी से भर दें। इसके साथ-साथ पानी की टंकियां व कूलर आदि सप्ताह में एक बार अवश्य खाली करके सुखा लें या कूलर के पानी में एक चम्मच पेट्रोल या डीजल तेल डालें। घर के आसपास व छत पर खाली बर्तन, टूटे खिलौने, गमले, खाली व बेकार बोतले, बेकार जूते व टायर आदि में बरसात का पानी खड़ा न होने दें। छत की टंकी अच्छी तरह बंद रखें और नलों का टपकना रोकें।

महिलाओं को पुरस्कृत करने के लिए आवेदन आमंत्रित

फरीदाबाद। उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को पुरस्कृत करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं । उन्होंने बताया कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने बहादुरी और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया हो। इसके साथ ही पिछले पांच वर्षों से महिलाओं के कल्याण के लिए काम करके अच्छा प्रदर्शन कर रही हो। उन्होंने बताया कि इन आवेदनों के लिए हरियाणा में पैदा हुई महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिता शर्मा ने बताया कि इसके लिए आगामी 8 मार्च 2022 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सम्मानित होने वाली महिलाओं द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हर साल महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सम्मानित किया जाता है।

छह सितंबर तक बढ़ाया गया रियायतों के साथ लॉकडाउन

पिछले आदेश अनुसार रियायतें लगातार रहेंगी जारी

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र यादव ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नाम से लॉकडाउन को छह सितंबर सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया है। नए आदेश के अनुसार पिछले आदेशों में दी गई रियायतें लगातार जारी रहेंगी।

जिलाधीश द्वारा जारी किए आदेश में कहा गया है कि नो मास्क-नो सर्विस के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्हीं लोगों को पब्लिक व प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में अनुमति दी जाएगी जो मास्क लगाएंगे। इसी प्रकार से सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों से केवल वे ही लोग सेवाएं अथवा सामान प्राप्त कर सकेंगे, जिनके मुंह पर मास्क लगा होगा। परीक्षण, ट्रैकिंग, उपचार, टीकाकरण व कोविड-19 व्यवहार की रणनीति पर विशेष फोकस रहेगा।

जिलाधीश जितेंद्र यादव द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार रेस्टोरेंट्स, बार्स, मॉल सहित रेस्त्रां को 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की है, लेकिन आवश्यक सामाजिक दूरी के सिद्धांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना होगा। जिम और स्पा को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है। वहां भी महामारी से बचाव के सभी नियम का पालन करना होगा। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउसिज, रेस्टोरेंट्स और बार्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है। यहां भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की शर्तें जारी रहेगी। गोल्फ कोर्स में खेलने के लिए भीड़ न होने देने का प्रबंधन करना होगा।

संक्षिप्त समाचार

जिले में 12921 लोगों को लगा टीका

फरीदाबाद। जिले में सोमवार को 12921 लोगों ने कोरोना से बचाव का टीका लगवाया। जिसमें 11 हेल्थ केयर वर्कर, 211 फ्रंट लाइन वर्करों ने टीका लगवाया। वहीं 18 प्लस आयुवर्ग में 9842 लोगों को टीका लगा। वहीं 45 प्लस आयुवर्ग में 2857 लोगों को टीका लगाया गया। हालांकि जिले में मौजूद सरकारी टीकाकरण केन्द्रों पर डोज की संख्या साफ दर्शाई गई थी। इसके बावजूद लोगों की भीड़ केन्द्रों के बाहर नजर आई। बीके अस्पताल में टीकाकरण केन्द्रों पर भीड़ लगी हुई थी। जिसमें पहले लोगों को कोरोना जांच के लिए घंटों लम्बी लाइन में लगना पड़ा। जिसके बाद उन्हें वैक्सीन की लम्बी लाइनों में घंटों खड़े रहना पड़ा। फिर उन्हें वैक्सीन की डोज लगाई गई।

केन्द्रीय पॉलीक्लीनिक में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित

फरीदाबाद। एनएच-चार स्थित ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक फरीदाबाद में हरित पॉली क्लीनिक अभियान के तहत 100 पौधे लगाए गए। इस मौके पर ईसीएचएस के अफसर इंचार्ज कर्नल मुनीश शर्मा, सुनील सब्बरवाल, मेजर अशोक, डॉ. अनिता, डॉ. मून, डॉ. नीरू, सूबेदार मेजर मेघराज, सूबेदार मेजर रमेशचंद, सूबेदार नेहरू, सूबेदार लख्मी, सूबेदार बलराम सिंह, सारर्जेन्ट रॉय, हवलदार धर्म सिंह डागर (आर.डब्ल्यूए झाड़सेंतली) आदि लोगों ने पौधे लगाए। उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कर्नल मुनीश शर्मा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्मदिवस व परिवार में खुशी के मौके पर पौधे अवश्य लगवाने चाहिए। फिर कम से कम दो वर्ष तक उनका बच्चों की तरह पालन-पोषण करना चाहिए, ताकि वह आम जन को ऑक्सीजन देने का कार्य करें।

अधिवक्ता परिषद द्वारा स्टडी सर्कल कार्यशाला का आयोजन

फरीदाबाद। सेक्टर 12 न्यायालय परिसर स्थित जिला बार रूम में अधिवक्ता परिषद जिला फरीदाबाद द्वारा स्टडी सर्कल (ट्रेनिंग प्रोग्राम) आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजसेवी एवं पूर्व सैन्य अधिकारी सत्येंद्र दुग्गल ने की एवं मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संपर्क प्रमुख गंगा शंकर मिश्रा रहे एवं इस कार्यक्रम में अधिवक्ता परिषद के जिला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता प्रशिक्षक थे। गंगा शंकर मिश्रा ने कहा कि अधिवक्ता परिषद राष्ट्रीय वादियों का एक केंद्र है अधिवक्ता परिषद अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए कार्यरत है अधिवक्ता परिषद ने न्याय के क्षेत्र में बड़े-बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं एवं वंचित एवं पीड़ित वर्ग की रक्षार्थ अधिवक्ता परिषद सदैव प्रयासरत है। युवा अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए रविंद्र गुप्ता ने कहा अधिवक्ता वर्ग अपने सुख सुविधाओं की चिंता ना करते हुए अपने वादी एवं प्रतिवादी गण को न्याय दिलाने के लिए अपना उच्चतर प्रयास करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में एसिड पीड़ित कानून एवं अधिकार पुनर्वास एवं मुआवजा पर विशेष प्रशिक्षण दिया एवं क्रिमिनल मैनुअल की किताबें एवं स्टेशनरी पैड आदि वितरित किए गए। कार्यक्रम में अधिवक्ता परिषद के गोपाल दत्त शर्मा, आत्मप्रकाश सेतिया, पुरुषोत्तम भारद्वाज, कृपाराम, मुकेश वर्मा, योगेश दत्त शर्मा, मनीष वर्मा, विकास शर्मा, मनीष राघव, राजेंद्र प्रसाद गौतम, महेंद्र सिंह बघेल, रामवीर सिंह तंवर, नेहा गौतम, मधुबाला, संतोष रानी आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।

मीडिया कोआर्डिनेटर ने पैरालंपिक खिलाड़ी को दी शुभकामनाएं

फरीदाबाद। 24 अगस्त से होने वाले टोक्यो पैरालिंपिक खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी रामसिंह भाटी सोमवार शाम 6 बजे जापान रवाना हो गए। उनकी रवानगी से पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया कोआर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ ने रंजीत सिंह भाटी को को फूलों का गुलदस्ता देकर टोक्यो पैरालिंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने के लिए शुभकामनाएं दी। बता दें आदर्श नगर, बल्लभगढ़ निवासी युवा पैरा खिलाड़ी रंजीत सिंह भाटी का चयन टोक्यो पैरालिंपिक के लिए हुआ है। रंजीत भाला फेंक प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। रंजीत ने दिल्ली में हुए पैरालिंपिक ट्रायल में 44.50 मीटर भाला फेंककर टोक्यो पैरालंपिक का टिकट प्राप्त किया है। रंजीत सिंह भाटी से मिलने पहुंचे मुकेश वशिष्ठ ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच के कारण आज प्रदेश खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। बेहतरीन खेल नीति के कारण खिलाड़ियों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में इसबार 54 सदस्यीय भारतीय दल जा रहा है। जिसमें हरियाणा से 19 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 28 जुलाई को मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए पैरलिंपिक खेलों के लिए विकटरी पंच दिया था। मुख्यमंत्री का अटूट विश्वास है कि पैरालंपिक खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करके भारत की झोली मेडलों से भर देंगे और हरियाणा का दुनिया में नाम रोशन करेंगे। वशिष्ठ ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा सभी खिलाड़ियों को खेल नीति के मुताबिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसलिए पैरालिंपिक की तैयारी के लिए पहले ही खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपये एडवांस राशि दी गई। रंजीत सिंह भाटी ने बताया कि उनका सपना है कि वे भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर वापस आए। पैरालिंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के लिए उन्होंने खूब कड़ी मेहनत की है। हरियाणा सरकार से उन्हें लगातार सहयोग मिला है। मौके पर कोच कृष्ण कुमार पालीवाल भी मौजूद थे।

बैठक में अधिकारियों के रवैये पर जताया रोष

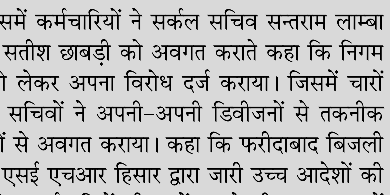

फरीदाबाद। स्विचिंग सिस्टम 11 केवी पावर हाउस हार्डवेयर पर हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन की एक आवश्यक बैठक हुई। जिसमें कर्मचारियों ने सर्कल सचिव सन्तराम लाम्बा व प्रदेश चीफ एडवाइजर सतीश छाबड़ी को अवगत कराते कहा कि निगम अधिकारियों के रविये को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। जिसमें चारों यूनिटों से आये प्रधान व सचिवों ने अपनी-अपनी डिवीजनों से तकनीक कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया। कहा कि फरीदाबाद बिजली निगम के अधिकारियों ने एसई एचआर हिसार द्वारा जारी उच्च आदेशों की अवेहलना करते हुए तकनीक कर्मचारियों फील्ड में लगाने की बजाय दफ्तरों में बैठा रखा है। सभी सचिवों ने एकमत होकर यह बात रखी कि आज बिजली को सुचारू रूप से चलाना हमारी पहली प्राथमिकता है। लेकिन फरीदाबाद सर्कल में काफी तकनीक कर्मचारी जोकि अधिकारियों के लिये दलाली करने का काम करते हैं और वह फील्ड के स्थान पर एसी कार्यालयों में बैठ कर कुर्सी तोड़ रहे हैं। जबकि बात करें सुविधाओं की तो वह दफ्तरों में बैठे हुए निगम से वर्दी, रेनकोट, वाशिंग एलाउंस आदि तकनीकी सुविधाओं के लाभ भरपूर उठा रहे हैं। निगम मैनेजमेन्ट को चाहिए कि ऐसे कर्मचारी जो अभी भी निगम द्वारा क्लेरिकल की सीट पर बैठ कर तकनीकी एलाउंस ले रहे हों। उन्हें तत्परता के साथ तुरन्त प्रभाव से वापिस लिए जाएं और अभी तक की सभी रिकवरियां की जायें। जिससे निगम को लाखों रुपये का राजस्व प्राप्त व बर्बाद होता है। साथ ही फील्ड में जो तकनीकी कर्मचारी स्टाफ के अभाव में निर्बाध बिजली आपूर्ति करने में कई कई घंटों का समय लगते है। जिससे उपभोक्ताओं को भारी असुविधाओं का सामना निगम की ओर से झेलना पड़ता है।

पायनियर
नई दिल्ली, मंगलवार, 24 अगस्त, 2021

सही रास्ता

कोविड से मुकाबला

नए मामले घटने तथा ठीक होने की दर बढ़ने से स्पष्ट है कि हम कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में सही रास्ते पर हैं। लंबे समय बाद कोविड के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में रोज आने वाले नए कोरोनावायरस मामलों की संख्या घट कर 36,571 हो गई है। कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर भी बढ़ कर 97.53 प्रतिशत हो गई है। इनमें से अधिकांश मामले केरल से हैं जहां रोज लगभग 21,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं और इसी कारण कुल दैनिक मामलों की संख्या बढ़ कर 36,000 से अधिक हो रही है। हालांकि, 19 अगस्त को ठीक होने वाले मामलों की संख्या भी 36,000 से अधिक थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, कुल सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या अब घट कर 3,63,605 हो गई है जो 105 दिन में सबसे कम है। वास्तव में यह कुछ राहत की बात है, पर इसके कारण हमें सावधानी में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तीसरी लहर शुरू होने की संभावित तारीख जल्द ही आने वाली है और इससे पूरा परिदृश्य एकदम से बदल सकता है। इसके बावजूद इस बात की संभावना है कि तीसरी लहर दूसरी लहर जितनी भयानक नहीं होगी और ऐसा विश्वास करने के उपयुक्त कारण भी मौजूद हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन-डब्लूएचओ के आंकड़ों के अनुसार, अब तक कोरोनावायरस से 3.23 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से अधिकांश ठीक हो गए हैं और उनमें एंटीबाडी बन चुकी हैं। अब सिद्धान्त के अनुसार ये लोग वायरस संक्रमण के प्रसार में बाधा की तरह काम कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि अब बाकी जनता के लिए हर्ड इम्युनिटी अपनी भूमिका अदा कर रही है।

इसके साथ ही अब तक हमारी लगभग आधी जनसंख्या, यानी 57 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। इससे भी कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार पर रोक लगती है। इसके साथ ही अस्पतालों में आक्सीजन तथा अन्य सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है। कोविड-19 के कारण हमारा काफी नुकसान हो चुका है और अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें तथा फिर से जीवन्तता पैदा करें। कुल मिला कर कहें तो आखिरकार कितनों दिन तक हम अपनी जिन्दगी पर विराम लगा सकते हैं? इसका यह अर्थ भी है कि आखिरकार देश कितने दिनों तक लाकडाउन के कारण विकलांगता की स्थिति में रह सकता है? शिक्षा, खेल, बिजनेस, मनोरंजन और यात्रा तथा अतिथि सत्कार उद्योग को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। कोरोनावायरस वैश्विक महामारी के कारण होने वाला आर्थिक व मनोवैज्ञानिक नुकसान बहुत बड़ा है। हमें इन स्थितियों से लड़ने के रास्ते खोजने होंगे। लाकडाउन को लंबा घसीटना इसका कोई रास्ता नहीं हो सकता है। हमें नए तरीके से सोच कर अपने जीवन को पुन: ऊर्जान्वित करना होगा। इस दिशा में यात्रा के लिए कोराना पासपोर्ट की योजना एक अच्छा विचार है। दो या तीन पालियों में स्कूल खोलने से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। हमें ओलम्पिक में पदक पाने और शानदार प्रदर्शन करने वाले अपने एथलीटों पर बहुत गर्व है, लेकिन खेल सुविधायें अभी खोली नहीं गई हैं। इसके कारण अनेक युवाओं का खेल कॅरियर शुरू होने के पहले ही मुरझा सकता है। इसी तरह मनोरंजन उद्योग को भी खोलने की आवश्यकता है ताकि इस उद्योग तथा स्वयं हमारे ऊपर हावी तनाव को घटाया जा सके।

शिक्षा के अधिकार पर जोर

सभी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षा संस्थान स्थापित करने और उनको संचालित करने का अधिकार होगा।

देवेंद्र सिंह असवाल
(लेखक भारत सरकार के पूर्व अपर सचिव हैं)

दु:ख की बात है कि जब संसद जागरूक करने वाली बहसों व चर्चा का मंच नहीं रह जाता है तब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग-एनसीपीसीआर की इस संस्तुति ने नई बहस को जन्म दिया है कि अल्पसंख्यक-संचालित स्कूलों को शिक्षा अधिकार कानून-आरटीई तथा सर्वशिक्षा अभियान-एसएसए की निगरानी में लाया जाना चाहिए। एनसीपीसीआर ने ऐसे स्कूलों में अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के आरक्षण की पैरवी भी की है। रिपोर्ट के अनुसार 93वें संविधान संशोधन के बाद अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने वाले स्कूलों की संख्या 2005-2009 में यह सार्टीफिकेट मांगने वाले कुल स्कूलों की तुलना में 85 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई है। इसकी दूसरी लहर 2010-2014 में आई। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमति एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम भारत सरकार में फैसला दिया कि अल्पसंख्यक स्कूलों पर आरटीई कानून लागू नहीं होता है। एनसीपीसीआर ने संस्तुति की है कि सभी अल्पसंख्यक स्कूलों तथा मदरसों को आरटीई कानून तथा एसएसए के अंतर्गत लाया जाना चाहिए तथा उसने इन स्कूलों में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए आरक्षण की संस्तुति भी की है। रिपोर्ट में संकेत किया गया है कि आरटीई कानून का क्रियान्वयन रोकने के लिए अनेक स्कूलों का पंजीकरण अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में कराया गया है। ऐसे में सवाल केवल यह है कि क्या अल्पसंख्यक संचालित शिक्षा संस्थानों को आरटीई कानून के दायरे में लाने से अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार प्रभावित होंगे? क्या अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30 के संरक्षण में ऐसे शिक्षा संस्थान चलाने की अनुमति दी जा सकती है जो शिक्षा के बच्चों के मूलाधिकार को संरक्षण देने वाले अनुच्छेद 21ए का उल्लंघन करते हों? एक और प्राविधान चिन्ता का विषय है कि प्रमति फैसले के बाद अल्पसंख्यक स्कूलों को आरटीई एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया है।

सभी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षा संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29 एक प्राविधान के माध्यम से अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण देता है कि भारत के क्षेत्र में रहने तथा विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति वाले नागरिकों के किसी समूह को उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने व संचालित करने के अधिकार की गारंटी करता है। लेकिन संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शामिल अनुच्छेद 21ए निर्धारित करता है कि राज्य 6-14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इस संविधान ने अनुच्छेद 45 में भी परिवर्तन किया है जिसके अनुसार अब, 'राज्य को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों को प्रारम्भिक देखभाल तथा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।' इसके साथ ही अनुच्छेद 51ए की धारा के माता-पिता या संरक्षक पर जिम्मेदारी डालती है कि वे 'अपने बच्चे या संरक्षित को 6-14 साल की आयु तक शिक्षा दिलाएंगे।' 93वें संशोधन ने अनुच्छेद 15 में धारा 5 जोड़ी है जिससे राज्य को कानून द्वारा किसी सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूह या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को विशेष प्राविधान के माध्यम से निजी शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश की अनुमति देता है, चाहे उनको राज्य द्वारा सहायता मिलती हो या नहीं। अनुच्छेद 30 की धारा 1 के अंतर्गत आने वाले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इन संवैधानिक प्राविधानों को प्रभावी बनाने के लिए संसद ने आरटीई कानून लागू किया है।

अनुच्छेद 30 में अभिव्यक्त 'अल्पसंख्यक' को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कानून, 1992 की धारा 2सी के अनुसार मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन व अग्निपूजक पारसी अल्पसंख्यक समुदायों में आते हैं। सवाल यह है कि क्या आरटीई कानून व एसएसए के दायरे में स्कूलों को लाने से इन समुदायों के सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों को नुकसान होगा। शिक्षा के समवर्ती सूची में शामिल होने के कारण यह कानून उपयुक्त सरकारों व स्थानीय अधिकारियों पर जिम्मेदारी डालता है कि वे 6-14 साल के सभी बच्चों का प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए प्रवेश, हाजिरी व जारी रहना सुनिश्चित करें।

यह कानून सभी निजी स्कूलों को अपनी 25 प्रतिशत सीटें कमजोर तबके के बच्चों के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य बनाता है जिनकी फीस प्रतिपूर्ति राज्य द्वारा की जाएगी। 2002-2003 में शुरू एसएसए का लक्ष्य सबको शिक्षा है। यह समयबद्ध तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण की प्राप्ति का प्रमुख कार्यक्रम है।

प्रमति फैसले में इस बात पर गौर नहीं किया गया है कि कमजोर तबके के 25 प्रतिशत बच्चों का प्रवेश कोटा तय करने के साथ आरटीई कानून में ढांचागत मानकों, शिक्षक-छात्र अनुपात, स्क्रीनिंग टेस्ट व कैपिटेशन फीस पर प्रतिबंध के साथ ही शारीरिक दंड पर रोक, आदि प्राविधान भी शामिल हैं। इन प्राविधानों से छात्रों तथा अल्पसंख्यक समुदाय, दोनों को लाभ होता है। इस प्रकार सभी नियामक उपाय अल्पसंख्यक संस्थानों का चरित्र नहीं नष्ट करते हैं और इनको न्यायपालिका ने उचित माना है। अहमदाबाद के सेंट जेवियर कालेज मामले में मुख्य न्यायाधीश रे ने कहा था, 'यह अधिकार अल्पसंख्यक संस्थानों को दायित्व व कर्तव्य सौंपता है कि वे अपने छात्रों को सबसे अच्छा दें। नियामक उपायों के रूप में लागू संतुलन व नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति हो तथा उनकी सेवाशर्तें बेहतर हों।' जस्टिस खन्ना के अनुसार, 'संस्थान के हित में नियमन जरूरी हैं। उनको इस तरह बनाया गया है कि वे प्रभावी ढंग से शिक्षा देने का माध्यम बनें तथा नियमन शिक्षण, अनुशासन, स्वास्थ्य, सफाई, नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था, आदि के हित में बनाए गए हैं और असंदिग्ध रूप से उनको लागू किया जाना चाहिए।' जस्टिस खन्ना ने यह चेतावनी भी दी थी कि 'अल्पसंख्यक संस्थानों को शैक्षिक संस्थानों के उत्कृष्ट मानकों से नीचे गिरने की अनुमति प्रबंधन के विशिष्ट अधिकारों के बहाने नहीं दी जा सकती है। इसलिए दोनों उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होगा कि संस्थान में उत्कृष्ट मानक सुनिश्चित किए जाएं तथा शैक्षिक संस्थान बनाने व उनको संचालित करने के अल्पसंख्यक अधिकारों को संरक्षण दिया जाए।' ये टिप्पणियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसके मुहम्मद रफीक बनाम प्रबंधन समिति के जनवरी, 2020 में दिए फैसले की संगति में हैं जिसमें पश्चिम बंगाल मदरसा सर्विस कमीशन एक्ट, 2008 को उचित ठहराया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य को देश के हित में एक नियामक व्यवस्था शुरू करने का अधिकार है ताकि अल्पसंख्यक संस्थानों को सुयोग्य शिक्षक मिलें और वह शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करें। सर्वोच्च न्यायालय के अनेक फैसलों को देखते हुए अल्पसंख्यक संस्थान राज्यों द्वारा लागू विनियमनों की अनदेखी या उनका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं जिनका उद्देश्य सभी बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। बच्चों का संबंध राज्य से है और राज्य की यह प्रमुख संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह सभी बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करे, भले ही उनका धर्म, जेंडर या समुदाय कोई भी क्यों न हो।

आरटीई कानून अल्पसंख्यक-संचालित संस्थानों को अपना प्रबंधन चुनने, शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति, शिक्षा के आवश्यक मानक तय करने, योग्य छात्रों की भर्ती करने, तार्किक फीस संरचना बनाने तथा अपनी संपत्तियों व संस्थानों का लाभ देश के कानूनों के अंतर्गत उठाने से नहीं रोकता है। संविधान के प्राविधानों को सद्भावनापूर्वक लागू करना चाहिए। समुदाय या जेंडर की बाधायें विधायन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को विफल नहीं कर सकती हैं। समय आ गया है कि हम प्रमति निर्णय की समीक्षा करें।

मजबूत होकर उभरा किसान आंदोलन

इंद्र शेखर सिंह
(लेखक भारतीय राष्ट्रीय बीज संघ के पूर्व निदेशक हैं)

यह एक बार फिर शांत और शांतिपूर्ण है जब आप टॉल्स्टॉय मार्ग को इंपीरियल होटल से जंतर मंतर की ओर चलते हुए ले जाते हैं। कम खाकी शर्ट क्षेत्र में गश्त करते हैं। अब कोई सांप्रदायिक नारेबाजी या विरोध नहीं। लेकिन एक तरफ लगे दर्जनों पीले पुलिस बैरिकेड्स ने कुछ कहानी बयां की, यहां कुछ हुआ।

22 जुलाई से 9 अगस्त तक किसान क्रांति के नेताओं ने जंतर मंतर पर किसान संसद (किसान संसद) का आयोजन किया था। यह भारतीय संसद के मानसून सत्र के समानांतर चला। हर दिन, 200 किसान प्रतिनिधियों ने कृषि कानूनों और कानूनी अधिकार के रूप में एमएसपी, स्वामीनाथन रिपोर्ट जैसे अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और यहां तक कि मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया।

लेकिन इस प्रतीकात्मक संसद ने क्या हासिल किया? सबसे पहली बात संसद के साथ किसान क्रांति ने दिल्ली के दिल में प्रवेश कर लिया है। और इसने देश को दिखाया कि किसान संसद भी चला सकते हैं। किसानों के खेमे से आवाज़ें अब दिल्ली के भीतर गरजने लगीं और भारतीय लोकतंत्र की पतवार पलटने लगी। अब क्या किसानों को बालाजी श्रीवास्तव (दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त) के मोदी को विदाई उपहार या उनके नेताओं की चतुर राजनीति के रूप में पुलिस की अनुमति मिली है, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार बैकफुट पर थी।

कोई इसका अनुमान क्यों लगाएगा? सुरक्षा उपाय पहला संकेतक थे। प्रत्येक किसान प्रतिनिधि के लिए पांच सुरक्षाकर्मी थे। मीडिया को अक्सर अलग-थलग कर दिया जाता था, स्वतंत्र पत्रकारों ने प्रवेश से इनकार कर दिया था, और एक दिन कई लोगों को फिर से प्रवेश करने से रोक दिया गया था, सभी को अनौपचारिक रूप से किया गया था।

तूफानी मानसून सत्र से शुरू होकर कुछ चीजें किसानों के पक्ष में भी गईं। पेगासस ने सदन को हिला दिया था और फिर भी सरकार जासूसी या कृषि कानूनों पर चर्चा करने के मूड में नहीं थी। संसद में जहां करोड़ों की बर्बादी हुई, वहीं किसान संसद में प्रतिदिन वाद-विवाद और चर्चा होती थी। इन सेशन में नए चेहरों ने हिस्सा लिया। देविंदर शर्मा और रंजीत सिंह घुमन जैसे प्रसिद्ध कृषि विशेषज्ञों ने भी हाथ बढ़ाया। पूर्व नौकरशाहों, गायकों और एक अभिनेत्री ने भी कार्यवाही में भाग लिया।

किसान संसद राजनीतिक कार्रवाइयों के लिए पिघलने वाला बर्तन और नया गठबंधन बनने में सफल रही। जब प्रतिनिधियों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, तो राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के 60 से अधिक सांसद क्रांति को मौन समर्थन देते हुए, आगंतुक दीर्घा में बैठ गए। इस घटना ने राजनीतिक फ्रिंज समूहों को भी एक नया मंच दिया है, और हम में से कई लोगों को जेपी आंदोलन के दिनों की याद दिला दी गई थी।

राजनीतिक फ्रिंज समूहों की बात करें तो किसान संसद ने महिलाओं के मुद्दों को एक मंच दिया। दो दिनों के लिए, यह एक सर्व-महिला संबंध में बदल गया। इन दिनों आवश्यक वस्तु अधिनियम, महिला आरक्षण और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की गई। किसान नेताओं ने महिलाओं को विशेष महत्व दिया और उनका समर्थन हासिल करने में सफल रहे हैं। किसान संसद ने मोदी सरकार के खिलाफ एक महान जनसंपर्क अभियान होने के अलावा अपने स्वयं के कैडर को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन या युद्ध का सबसे कठिन हिस्सा दुर्घटना है। किसान संसद ने स्थानीय ऑनलाइन मीडिया की मदद से मनोबल ऊंचा रखा। जंतर मंतर किसानों को एक नई उम्मीद देता है। किसानों की सफलता से चिंतित, असामाजिक तत्वों ने बेवजह पुलिस घेरा चकमा दिया और साम्प्रदायिक नारे लगाते हुए 8 अगस्त को क्षेत्र में प्रवेश किया। यह किसानों के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में लग सकता है, लेकिन इसने उनका मनोबल गिराने के बजाय, मोदी सरकार के लिए उनके बीच और अधिक अविश्वास फैलाया। इसने कोविड और पुलिस की मंशा पर भी दोगुनेपन को भी उजागर किया है। यहां तक कि वीएम सिंह के नेतृत्व में बिखरा गुट भी फिर से नकारात्मक प्रभाव डालने में विफल रहा। किसान संसद का संदेश अलग-अलग समूहों की बैठकों में भी गूंजता रहा।

शिविरों और भीतरी इलाकों में समग्र प्रेरणा को मजबूत किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि किसानों ने विशुद्ध राजनीतिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। उचित मूल्य और कृषि मुद्दों के बारे में जमीनी स्तर पर आंदोलन से, क्रांति एक नवोदित राजनीतिक आंदोलन के रूप में विकसित हुई है। इसने किसानों को संसदीय सत्र और लोकतंत्र का स्वाद भी दिया है। देश भर में भेजा गया मौन संदेश यह है कि किसानों को संसद में प्रवेश करने के लिए तैयार होने की जरूरत है।

1990 के दशक के अंत के दौरान, वीपी सिंह ने स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की थी: ''जब तक किसान राजनीतिक वर्ग नहीं बन जाते, तब तक उनकी कोई नहीं सुनेगा। उन्हें खुद राजनीति में आना चाहिए।'' आज किसान संसद एक कदम है। किसान क्रांति ने देश भर के किसानों को एक राजनीतिक वर्ग के रूप में संगठित करना शुरू कर दिया है और इस प्रक्रिया में हरित राजनीति की आधारशिला भी रखी है। स्वाभाविक रूप से पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आंदोलन मजबूत है लेकिन अन्य राज्यों को सूची में जोड़ा जा रहा है। किसान नेताओं के अन्यथा कहने के बावजूद, मिशन यूपी अत्यधिक राजनीतिक है। इसकी शुरुआत 5 सितंबर को एक विशाल किसान रैली से होती है।

नेताओं ने खुद खुलासा किया है कि सभी 18 उप-क्षेत्रों में भाजपा विरोधी लहर को मजबूत करने के लिए अभियान शुरू होगा। किसान नेताओं ने पहले पश्चिम बंगाल की यात्रा की और राज्य में ममता की जीत में सहायता की। यूपी होगी अंतिम परीक्षा, सफल होने पर, किसान क्रांति का भारतीय राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। भाजपा की जीत हो या हार, किसान संसद और क्रांति ने भारत में किसान आंदोलन और कृषि राजनीति के लिए एक नए युग की शुरुआत की।

आप की बात

रक्षा क्षेत्र में नवाचार

अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्कृष्टता हेतु नवाचार के अंतर्गत डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का पांचवां संस्करण लांच किया है। यह बहुत अच्छी बात है। इसके अंतर्गत सेवाओं और रक्षा लोक क्षेत्र के उपक्रमों का अनावरण किया गया जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं 5 प्रतिशत नेटवर्क में नवाचार प्रमुख था। यह रक्षा नवाचार वर्ष 2018 में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी रूप से उन्नत समाधान प्रदान करने हेतु नए उद्यमियों को शामिल कर रक्षा व एयरोस्पेस में नवाचार तथा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने को एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में लांच किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी और सह निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप के साथ जुड़ाव की संस्कृति बनाना है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे देश अपने डिफेंस के मटेरियल खुद ही बनाते हैं जिससे कि वह अपने आप पर ज्यादा आत्मनिर्भर हैं एवं उनकी तरक्की भी लगातार अग्रसर है। जब से आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू हुआ है तब से भारत की आत्मनिर्भरता पर ज्यादा ध्यान दिया है और इसके साथ साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बहुत सारे कदम उठाए गए हैं जिससे कि इस क्षेत्र में नवाचार का दृष्टिकोण बदला है।

– सुदर्शन सोराड़ी, नैनीताल

तीसरी लहर का खतरा

देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और इस बीच तीसरी लहर की आशंका जताई गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने पीएमओ और केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में कहा है कि अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। उस दौरान एक दिन में 5 लाख तक केस सामने आ सकते हैं। हालांकि, इसका असर एक महीन तक ही रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर का बच्चों और बड़ों पर समान रूप से असर होगा। पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना के तीस हजार के लगभग मामले आ रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि विनाशकारी दूसरी लहर अभी तक देश में खत्म नहीं हुई है। ऐसे में अहम बात यह है कि ये चेतावनी तब आई है, जब देश में त्योहारों की शुरूआत हुई है। बीते दिन भारत में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया तो अभी आगे कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्र, दशहरा, दीपावली और क्रिसमस जैसे बड़े पर्व भी आएंगे। यानी एक बार फिर त्योहारों का रंग फीका पड़ सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस स्थिति में देश में मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन के साथ ही दवाओं और मेडिकल उपकरणों की किस तरह व्यवस्था करना होगी।

– **एसआर गौतम,** भोपाल

महबूबा के बोल

कश्मीर में पीडीपी अध्यक्ष मेहबूबा मुफ्ती हमेशा ही जिस तरह भारतीय गणतंत्र का अपमान करती हैं। उन्होंने हमेशा ही कश्मीर में भारतीय सेना की उपस्थिति पर भी आपत्ति उठाई है एवं धारा 370 हटाने का भी विरोध किया। आज जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर हमला और कब्जा किया तो महबूबा तालिबान के कब्जे को सही ठहरा रही हैं। वे कहती हैं कि तालिबान अफगान को नियंत्रित कर रहा है जो जरूरी था तब हमें उनके बुद्धि पर तरस आता है कि दूसरे के मामले में वे इस तरह से गलत- सलत क्यों बोलती है अफगानिस्तान की जनता जानती है कि उनके ऊपर जो क्रूर तालिबान का कब्जा हुआ है वह कितना गलत है। वे कहती हैं कि जैसे अमेरिका आज अफगानिस्तान से भाग खड़ा हुआ एक दिन यही भारत के साथ भी कश्मीर में हो सकता है एवं उसे भी वहां से कश्मीर से भागना पड़ सकता है। तब हम महबूबा मुफ्ती से कहना चाहते हैं कि महबूबा जी आप किशौर अवस्था से लेकर आज तक कश्मीर में रह रही है आज के कश्मीर एवं पहले के कश्मीर में आज काफी बदलाव आ गया है।

– **मनमोहन राजावत,** शाजापुर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

फरमाया

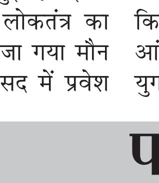

हम त्रिपुरा में जीतने जा रहे हैं। वहां कानून-व्यवस्था जैसी कोई चीज़ नहीं है। हम चाहते हैं कि वहां की जनता को सारे लाभ प्राप्त हों।

– **ममता बनर्जी**
तृणमूल प्रमुख

अशरफ ग़नी का भाग जाना राज्य और राष्ट्र के साथ की गई दगाबाज़ी है। वो अपने साथ 169 मिलियन डॉलर लेकर गए हैं।

– **मोहम्मद ज़हीर अग़बार**
ताजिकिस्तान में अफगान राजदूत

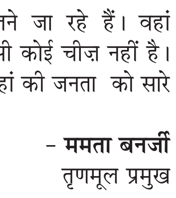

पेगासस मुद्दा तो अब उठा है। हम पिछले पांच वर्षों से कहते आए हैं कि फोन टेप किए जा रहे हैं इसलिए लोग डरे हुए हैं।

– **अशोक गहलोत**
राजस्थान के मुख्यमंत्री

कल्याण सिंह ने पूरी पारदर्शिता, शुचिता के साथ प्रदेश को आगे बढ़ायाः योगी

● शासन की धमक-इकबाल का परिचय देते हुए सनातन आस्था को प्रस्तुत कियाः सीएम

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हर राम भक्त एक प्रखर राष्ट्रभक्त और राम भक्त के भौतिक अवसान पर शोकाकुल है। उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह आज हमारे बीच में नहीं है। आज उनका पार्थिव शरीर उनकी कर्मभूमि एवं जन्मभूमि रही अलीगढ़ में आया है। उनके समर्थकों अनुयायियों का अपने दिवंगत नेता के प्रति 6 दशकों से जो लगाव है उसका एक दर्शन यहां पर हम सभी को देखने को मिल रहा है। जनपद में कल्याण सिंह का लगभग 9 दशक का संबंध रहा है। सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अलीगढ़ में लगभग 7 दशक व्यतीत किये। उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो कभी जाति के नाम पर, क्षेत्र, मत और मजहब के नाम पर माफिया और अपराधियों द्वारा जकड़ ली गई थी। यूपी की राजनीति आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। कभी सेकुलरिज्म के नाम पर, भारत की सनातन आस्था के नाम पर, सत्ताधारी दलों ने अपना एकमात्र एजेंडा बना लिया था। कल्याण सिंह को जब अवसर मिला तो शासन की धमक और इकबाल का परिचय देते हुए उन्होंने सनातन आस्था को मजबूती के साथ प्रस्तुत किया। उनको यह कहने में जरा भी हिचक नहीं हुई कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए वह सत्ता को एक बार नहीं बार बार ठोकर मार सकते हैं। 6 दिसम्बर को विवादित ढाँचा गिरने के बाद वर्ष 2016-2017 के कार्यकाल के दौरान समाज के प्रति एक तबके के लिए जो योजना लागू कीं उन्हें आज भी याद किया जाता है। सीएम ने कहा कि अलीगढ़ का सौभाग्य है आज अलीगढ़ की जनता अपने को गौरवान्वित महसूस कर रही है कि उनके बीच में भारत माता का सपूत जिसने पूरी पारदर्शिता, शुचिता एवं पवित्रता के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाया। आज यहां पर उपस्थित सैकड़ों हजारों लोगों को उनके साथ निकट समय में रहने, बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह प्रखर राष्ट्र भक्त, आस्थावान राम भक्त के रूप में जाने जाते थे। कल्याण सिंह को विकास पुरुष के रूप में, शासकीय दृढ़ता के रूप में सदैव ही याद किया जाएगा। आज जनपद का हर छोटी बड़ी उम्र का व्यक्ति अपने लोकप्रिय, जनप्रिय दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दे रहा है। यह कल्याण सिंह के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों एवं यहां के नागरिकों और निवासियों का सम्मान, स्नेह और प्यार ही है। शासन की दृढ़ता और मजबूती व कल्याण से जोड़ने की बातों पर कल्याण सिंह जी सदैव याद आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल्याण सिंह के साथ भारतीय राजनीति के युग का भौतिक रूप से अवसान हुआ है। ईश्वर कल्याण सिंह के उन सपनों को पूरा करने की ताकत सभी प्रदेश वासियों को प्राप्त करें। उन्होंने कल्याण सिंह के परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि आज उनके समर्थकों शुभचिंतकों की भीड़ उमड़ी हुई है। पूरी विनम्रता के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। यह लोगों की उनके प्रति आस्था को ही प्रदर्शित करता है।

राजनाथ सिंह ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन

लखनऊ। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर पहुंचे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने उनके मुख्यमंत्रित्व काल को याद कर संस्मरण साझा किए। उन्होंने कहा कि वह कल्याण सिंह सरकार में शिक्षामंत्री थे। एक बार नकल विरोधी कानून कैबिनेट के समक्ष पेश किया गया। उस विधेयक को लेकर कैबिनेट के कुछ सदस्यों के विचारों में भिन्नता आई। यह विचार किया गया कि इस विधेयक को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए लेकिन वह जब कल्याण सिंह से मिले तो उन्होंने कैबिनेट की अगली बैठक में इस प्रस्ताव को बीच से निकालकर कहा कि इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। नकल विरोधी कानून जो लागू हुआ, उसमें कल्याण सिंह की बहुत अहम भूमिका रही। राजनाथ ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन में भी उनकी सक्रिय व प्रभावी भूमिका रही। उनके दिल की तमन्ना थी कि धरती पर प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। शिलान्यास हो गया, निर्माण भी शुरू हो गया लेकिन यह विडंबना है कि उस भव्य राम मंदिर में वह रामलला के दर्शन नहीं कर पाए वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता व जन सेवा के पर्याय, अप्रतिम संगठनकर्ता एवं लोकप्रिय जननेता कल्याण सिंह का देहावसान संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके निधन से भारतीय राजनीति में कभी न भरा जा सकने वाला शून्य पैदा हो गया है। मायावती ने भी रविवार की सुबह सात बजे कल्याण सिंह के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, मायावती ने कहा कि भाजपा के कद्दावर नेता एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन की खबर दुखद है। उनके परिवार व समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। कुदरत उन सबको इस दुख को सहने की शक्ति दे। कल्याण सिंह के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के आगमन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

हिन्दुत्व के नायक को पीएम मोदी ने आवास पर पहुंच कर दी श्रद्धांजलि

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

हिंदुत्व के नायक के तौर पर पहचान रखने वाले व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह लखनऊ पहुंचे। कल्याण सिंह का लंबी बीमारी के बाद शनिवार रात लखनऊ के एसजीपीजीआई में निधन हो गया था। दो बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 89 वर्षीय कल्याण सिंह चार जुलाई से ही एसजीपीजीआई में भर्ती थे। रविवार को उनके अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लखनऊ स्थित आवास पहुंचे। इस दौरान उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे। पीएम मोदी ने कल्याण सिंह के पुत्र सांसद राजबीर सिंह, पौत्र राज्यमंत्री संदीप सिंह से मिल कर संवेदनाएं व्यक्त की, इस मौके पर पीएम ने कल्याण सिंह को अपना प्रेरणा स्रोत बताया और कहा कि उन्हें जब भी कोई जिम्मेदारी दी गई उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता से उसे पूरा किया। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान श्रीराम उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दें।

● परिजनों को बंधाया ढाढस

पार्टी के दिग्गज नेता के निधन पर प्रोटोकाल की औपचारिकताएं किनारे कर श्रद्धांजलि देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद शब्दों से कल्याण की क्षमता और स्वीकार्यता के इतिहास का सारांश सुना दिया। उन्हें जनसामान्य के विश्वास का प्रतीक बताते हुए कहा कि जीवनभर जनकल्याण के लिए जीने वाले कल्याण ने अपने माता-पिता से मिले नाम को सार्थक किया। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह लगभग 11 बजे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ माल एवेन्यू स्थित उनके आवास पर पहुंचे। वहां पार्थिव देह पर पुष्पार्चन कर स्वजन को ढाढ़स बंधाया। यहां भावांजलि अर्पित करते हुए कहा कि यह हम सबके लिए शोक की घड़ी है। वह जीवनभर जन कल्याण के लिए जिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने जनकल्याण को ही जीवन का मूलमंत्र बनाया। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ, पूरे परिवार को एक विचार और देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए समर्पित किया। राम मंदिर आंदोलन के इस नायक को याद करते हुए मोदी ने कहा कि कल्याण सिंह भारत के कोने-कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे। एक प्रतिबद्ध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे। जीवन के अधिकतम समय वे जनकल्याण के लिए प्रयत्नरत रहे। उनको जब भी जो दायित्व मिला, चाहे वो विधायक के रूप में, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गवर्नर की जिम्मेदारी हो, हमेशा प्रेरणा का केंद्र बने। जनसामान्य के विश्वास का प्रतीक बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश ने मूल्यवान शख्सियत और सामर्थ्यवान नेता खो दिया। हम उनकी भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनके संकल्पों को लेकर अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। प्रभु राम कल्याण सिंह को अपने चरणों में स्थान दें और प्रभु राम उनके परिवार को दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। देश में भी यहां के मूल्यों, आदर्शों, परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढांढ़स दें।

अंतिम इच्छा को पूरा कर बीजेपी के झंडे में लपेटकर दी गई विदाई

लखनऊ। राममंदिर आंदोलन के बड़े चेहरे और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अंतिम इच्छा को बीजेपी ने पूरा किया। कल्याण सिंह ने इच्छा जताई थी कि जब उनकी मृत्यु हो तो उनका भाजपा के झंडे में लपेटकर विदा किया जाए। रविवार को माल एवन्यू से कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को विधान भवन में रखा गया। यहां पर विपक्षी दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, इसके बाद यहां से उनके शरीर को बीजेपी मुख्यालय ले जाया गया। यहां पर कल्याण सिंह को बीजेपी झंडे में लपेटकर रखा गया और जब यहां से एयरपोर्ट के लिए दोपहर करीब सवा दो बजे कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा निकली तो भी उन्हें बीजेपी के झंडे में ही लपेटकर विदा किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उनकी अंतिम इच्छा को सम्मान देते हुए कार्य पूरा किया। भाजपा कार्यालय पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। भाजपा के नेता व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उनके अंतिम दर्शन के लिए आए। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि उनके जाने से जो शून्य उभरा है उसे भर पाना लगभग असंभव है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, क्षेत्र प्रचारक अनिल जी, प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व डॉ दिनेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री गणों, पार्टी पदाधिकारियों, विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओ एगणमान्य जनों व समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए विधान भवन होते हुए पार्टी मुख्यालय स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में लाया गया। जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, अनुप्रिया पटेल, बीएल वर्मा, कौशल किशोर ने पुष्पांजलि अर्पित कर स्वर्गीय कल्याण सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस दौरान स्वर्गीय कल्याण सिंह के पुत्र व सांसद राजबीर सिंह उनके पौत्र व राज्यमंत्री संदीप सिंह सहित उनके परिजन मौजूद थे। प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, सिद्धार्थ नाथ सिंह, राजेंद्र सिंह मोती सिंह, अनिल राजभर, दारा सिंह चौहान, आशुतोष टंडन गोपाल, रमापति शास्त्री समेत योगी सरकार के अन्य मंत्रियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

कल्याण का जाना एक युग के अंत होने जैसाः स्वतंत्र देव

लखनऊ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पूर्व राज्यपाल एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि रामलला के सच्चे सेवक, पूर्व राज्यपाल एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे अभिवावक कल्याण सिंह जी बाबूजी हमारे बीच नहीं रहे। उनका जाना एक युग के अंत होने जैसा है। बाबू जी जैसा महान व्यक्तित्व का स्वर्गवास, पार्टी ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। वह एक कुशल प्रशासक के साथ-साथ उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के हर हिस्से की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समीकरण की बारीकियों को गहराई से समझने वाले अनुभवी राजनेता भी थे। पार्टी के लिए वह ऐसे महान नेता थे जिन्हें हर वर्ग अपना समझता था और कार्यकर्ता एक अभिभावक के रुप में देखता था। बाबूजी जनसंघ काल से लेकर भाजपा के निर्माण और संगठन को निरंतर ऊंचाई पर ले जाने वाले सर्वमान नेता थे। उन्होंने कहा कि भाजपा को वटवृक्ष बनाने में उनका अमूल्य योगदान रहा। वह आजीवन प्रदेश की सेवा के लिए समर्पित रहे, उनके लिए पूरा प्रदेश ही परिवार था। उनके विचार और समाज के लिए उनके द्वारा किये गए महान कार्य आने वाली अनेकों पीढ़ियों को प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। प्रभु श्रीराम के प्रति उनकी आस्था अटूट रही, उन्होंने मुख्यमंत्री पद को त्याग कर विश्व को आस्था और दृढसंकल्प का एक अविस्मर्णीय उदाहरण दिया था। बाबूजी का आशीर्वाद, स्नेह और मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहा। मुझ जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं को अपनी छाँव में रखने वाले बाबूजी को मैं पुनः शत.शत नमन करता हूं। पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि श्रद्धेय कल्याण सिंह के निधन से देश ने एक राष्ट्रभक्त, कर्तव्यनिष्ठ व धर्मनिष्ठ राजनेता के रूप में विराट व्यक्तित्व को खो दिया है। बाबूजी गांव, गरीब, किसान के मर्म को समझने वाले अंत्योदय के सच्चे उपासक थे। संगठन विस्तार, कार्यकर्ता निर्माण के लिए सतत कार्य करने वाले बाबू जी के जाने से एक-एक कार्यकर्ता आहत है। कल्याण सिंह रामजन्म भूमि आंदोलन के नायक के रुप में सदैव स्मरण में अमिट रहेंगे। सामाजिक समरसता के पक्षधर बाबू जी ने प्रदेश की राजनीति को भय व अपराध से मुक्ति का मंत्र दिया। विभिन्न संवैधानिक पदों पर रहते हुए सुशासन की परिकल्पना को मूर्त रूप देने वाले बाबूजी के जाने से आई रिक्तता की पूर्ति असंभव है। उनके निधन से पूरा भाजपा परिवार शोकाकुल है। विनम्र श्रद्धांजलि।

सड़क से सदन तक सपा ईमानदारी से महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में खड़ी रहीः सपा मुखिया

● पार्टी मुख्यालय में अखिलेश को राखी बांध कर दी गई सफलता की शुभकामनाएं

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समाजवादी पार्टी के मुख्यालय 19 विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ में सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को विभिन्न संगठनों की सैकड़ों महिलाओं ने समाजवादी राखी बांधी। राजपुरोहित पं. हरि प्रसाद मिश्र ने मंत्रोच्चार के साथ रक्षासूत्र बांधा और अखिलेश के यशस्वी होने की कामना की तथा विजयीभव का आशीर्वाद दिया। पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में आयी महिलाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने रक्षाबंधन के पर्व पर 2022 में अखिलेश यादव को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। प्रदेश मुख्यालय के लोहिया सभागार में उपस्थित आधी आबादी ने एक स्वर से समाजवादी सरकार में अखिलेश द्वारा महिला सुरक्षा और सम्मान की दिशा में लिए गये ऐतिहासिक निर्णयों के प्रति आभार प्रकट किया।

अखिलेश यादव ने महिलाओं को रक्षाबंधन पर्व की बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश की तरक्की और खुशहाली की कामना की। उन्होंने बहनों को सुरक्षा एवं सम्मान का भरोसा दिलाया। श्री यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सड़क से सदन तक समाजवादी पार्टी ईमानदारी से उनके अधिकारों के पक्ष में हमेशा खड़ी रही है।

श्री यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि आपसी तालमेल के साथ सभी 2022 में समाजवादी पार्टी की जीत के लिए चुनाव की तैयारी में जुट जायें। भाजपा मतदाताओं को भ्रमित करने की साजिश में लगी है। भाजपा ने जनहित में कोई काम नहीं किया। जनता को फिर धोखा देने की रणनीति बनाने में ही भाजपा संलिप्त है। विकास पर सरकार कोई चर्चा नहीं करती है। भाजपा का एजेण्डा विकास विरोधी है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार में अपहरण, बलात्कार और हत्याओं के कारण महिलाओं का जीना दूभर हो गया है। महिला हिंसा में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। सरेराह बहन-बेटियों के साथ छेड़खानी होती है। रक्षाबंधन के दिन भी विचलित करने वाली दुष्कर्म की कई घटनाएं हुईं। प्रतापगढ़ में किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। शाहजहांपुर, रामपुर, बांदा से कई घटनाएं हुई। मिशन शक्ति तले महिलाएं रौंदी जा रही हैं। खुद मुख्यमंत्री के गोरखपुर जनपद में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है।

यूपी में दूध कारोबार की बदल रही फिजा

● लग रही डेयरी मिल रहा रोजगार

● हर साल नौ लाख मीट्रिक टन की औसत से बढ़ रहा दूध उत्पादन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से सूबे में दूध के कारोबार की फिजा तेजी से बदल रही है। दूध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अब देश में पहले स्थान पर है। और हर वर्ष राज्य में नौ लाख मीट्रिक टन की औसत से दूध उत्पादन बढ़ रहा है। जिसके चलते दूध का कारोबार करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां यूपी में अपनी डेयरी स्थापित करने में रुचि दिखा रहीं हैं। बीते चार वर्षों में 172 करोड़ का निवेश कर अमूल सहित छह निवेशकों ने अपने डेयरी प्लांट स्थापित किए हैं। सात डेयरी प्लांट लगाए जाने की कार्रवाई की जा रही हैं। इसके अलावा 15 निवेशकों ने अपनी यूनिट लगाने के लिए प्रस्ताव दिया। दूध उत्पादन के क्षेत्र में बड़े निवेशकों द्वारा लगाए जा रहे उद्यमों के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिला हैं। अब गांव गांव में गाय तथा भैंस पालकर दूध का कारोबार करने वाले ग्रामीणों की संख्या लगातार बढ़ रही हैं। कुल मिलाकर अब यह दावा किया जा सकता है कि यूपी में दूध का कारोबार ग्रामीणों को रोजगार मुहैया करा रहा है।

सरकार के आंकड़े बताते हैं कि देश में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है। यूपी का भारत में कुल दूध उत्पादन में 17 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा है। प्रदेश सरकार के प्रयासों से दुग्ध उत्पादन में यूपी पूरे देश में अव्वल है। वर्ष 2016-17 में यूपी में 277.697 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन हुआ था, जो 2019-20 में बढ़कर 318.630 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। विगत चार वर्षों में 1242.37 लाख मीट्रिक टन दूध उत्पादन राज्य में हुआ है। दूध उत्पादन में हो रह यह इजाफा सरकार की नीतियों का नतीजा बताया जा रहा। अधिकारियों के अनुसार राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने दुधारू पशुओं के संरक्षण के साथ ग्रीनफील्ड डेयरियों की स्थापना करने की शुरुआत की। गोवंश संरक्षण की सरकारी योजनाओं के चलते राज्य के सभी जिलों में गोवंश संरक्षक केंद्रों की स्थापना के लिए 272 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। बेसहारा और निराश्रित गोवंशीय पशुओं के भरण पोषण का प्रबंध किया गया। इसके साथ ही कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, बरेली, कन्नौज, गोरखपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या और मुरादाबाद में ग्रीन फील्ड डेयरियां स्थापित की जा रही हैं। झांसी, नोएडा, अलीगढ़ और प्रयागराज की चार पुरानी डेयरियों के उच्चीकरण का कार्य भी कराया जा रहा है। सरकार के ऐसे प्रयासों के बीच ही देश के बड़े निवेशकों ने राज्य में अपनी डेयरी यूनिट लगाने की पहल की। देखते ही देखते गाजीपुर में पूर्वांचल अग्रिको, बिजनौर में श्रेष्ठा फूड, मेरठ में देसी डेयरी, गोंडा में न्यू अमित फूड , बुलंदशहर में क्रीमी फूड और लखनऊ में सीपी मिल्क फूड की डेयरी यूनिट लग गई है और अन्य लोगों की डेयरी यूनिट लग रही हैं।

वहीं दूसरी तरफ राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार गोवंश संरक्षण केंद्र एवं गोवंश वन्य बिहार का निर्माण करा रही है। इनमें से 118 केंद्र का निर्माण कार्य पूरा भी हो चुका है। इसके अलावा मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत 66 हजार से अधिक गोवंश, इच्छुक पशु पालकों की सुपुर्दगी में दिए गए हैं। गोवंश पालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने गोकुल पुरस्कार और देशी गोवंश की गाय से सर्वाधिक दूध उत्पादक को नंदबाबा पुरस्कार देने शुरू किया है। गांवों में ग्रामीण दूध कारोबार से जुड़े इसके लिए सरकार प्रदेश में पंजीकृत 12 लाख से अधिक दूध किसानों का क्रेडिट कार्ड दे रही है। सरकार की इस योजना को ग्रामीण हाथो हाथ ले रहें हैं और राज्य में गौवंशीय पशुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। सरकार द्वारा कराई गई 20वीं पशुगणना के अनुसार यूपी में 202.04 लाख गौवंशीय पशु हैं। इन पशुओं के चलते ही यूपी दूध उत्पादन के मामले में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो सरकार भी दूध के कारोबार को बेहतर करने के लिए दुग्ध समितियों के ढ़ांचे को मजबूत करने में जुटी है। यूपी के 75 जिलों में करीब 21,537 दूध समितियां हैं, इसमें लगभग 1279,560 पंजीकृत दूध उत्पादक जुड़े हुए हैं। यह सभी लोग किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ लेने में रुचि ले रहे हैं। किसानों को दूध कारोबार के प्रति प्रोत्साहित करने के साथ ही प्रदेश सरकार पशुओं की नस्ल सुधार के लिए पशुओं का टीकाकरण करा रही है।

सरकार के इन प्रयासों के चलते राज्य के हर गांव में दूध गाय भैस पालकर दूध बेचने वाले ग्रामीणों की संख्या बढ़ रही है और दुधारू पशुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जिसके चलते हर वर्ष नौ लाख मीट्रिक टन के औसत से सूबे में दूध उत्पादन बढ़ रहा है और ग्रामीण इलाकों में अब दूध के कारोबार से लोगों को रोजगार मिल रहा है।

एनएचआरसी ने केंद्र, असम व मिजोरम को नोटिस जारी किया

● सीमा पर हुई झड़प को लेकर की कार्यवाही

भाषा। गुवाहाटी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दो पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा पर जुलाई में हुए जानलेवा संघर्ष को लेकर केन्द्र, असम और मिजोरम को नोटिस जारी किया है। आयोग ने कहा है कि उस दौरान मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ। असम निवासी मोहम्मद इंजमामुल हक की शिकायत पर कार्वाई करते हुए आयोग ने रविवार को केन्द्रीय गृह सचिव और असम तथा मिजोरम के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर अपनी-अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा। सुनवाई के विवरण में कहा गया है , आयोग ने मामले पर विचार किया है। मामले के तथ्य परेशान करने वाले हैं। शिकायत में लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और उसमें सरकारी कर्मचारियों की मौतें तथा घायल होना शामिल है। उसके अनुसार, यह मामला मृतकों और घायलों के मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। आयोग इस तरह के मामलों को बहुत गंभीरता से लेता है। इन परिस्थितियों में, पहले नोटिस भेजें। यह भी कहा गया कि चार सप्ताह के बाद पूर्ण आयोग के समक्ष मामला रखा जाएगा। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर 26 जुलाई को हुए हिंसक संघर्ष में असम पुलिस के कम से कम छह कर्मियों सहित सात लोग मारे गए थे और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मानवाधिकार आयोग ने कहा कि उसे 30 जुलाई को हक की शिकायत मिली जिसमें भीड़ और मिजोरम पुलिस द्वारा असम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों, कछार जिला प्रशासन और अन्य पर हमला किए जाने का आरोप लगाया गया था। आयोग ने कहा, अर्जी देने वाले ने असम-मिजोरम सीमा पर 26.07.2021 को हुई घटना का पूरा ब्योरा दिया है, जहां गोलीबारी से सरकारी कर्मचारियों की मौत हुई, कुछ घायल हुए।

जेएनयू, टीआईएसएस के छात्रों को आतंकी गतिविधि के लिए भर्ती किया: एनआईए

मुंबई। एनआईए ने आरोप लगाया है कि एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में आरोपियों ने दिल्ली के जेएनयू और टीआईएसएस जैसे प्रसिद्ध संस्थानों के छात्रों को आतंकवादी गतिविधि के लिए भर्ती किया था। केंद्रीय एजेंसी ने यहां एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किए गए अपने मसौदा आरोपों में यह दावा किया है। एनआईए ने इस महीने की शुरुआत में 15 आरोपियों को नामजद करते हुए आरोपों का मसौदा पेश किया और दस्तावेज की एक प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गई। मसौदे में दावा किया गया है, साजिश को आगे बढ़ाने के लिए, आरोपी व्यक्तियों, प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी और उसके प्रमुख संगठनों के सक्रिय सदस्य होने के नाते, जेएनयू के साथ-साथ टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों से आतंकवादी गतिविधि के लिए छात्रों की भर्ती की थी।

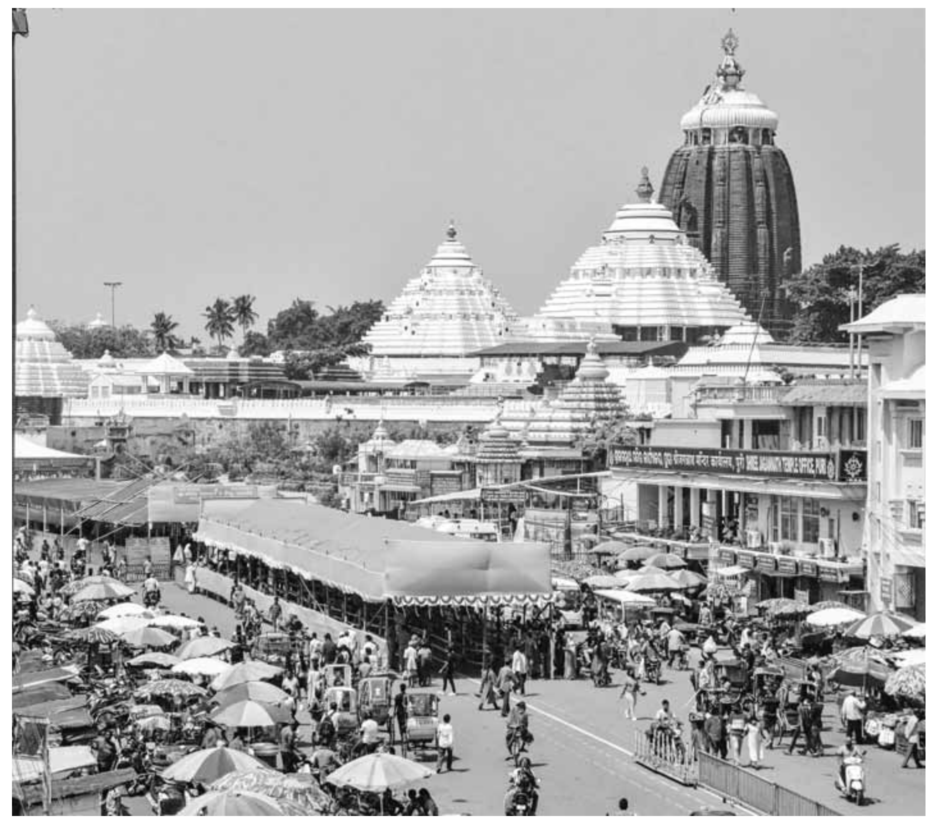

पुरी मेंअधिकारियों द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल के कुछ प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद जगन्नाथ मंदिर को भक्तों के लिए फिर से खोल दिया गया

चार महीने के बाद पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले

पुरी। ओडिशा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ के प्रसिद्ध मंदिर के कपाट सोमवार की सुबह करीब चार महीने के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। अधिकारियों ने बताया कि कोविड-19 महामारी के चलते मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था। इस साल 24 अप्रैल से बंद मंदिर के कपाट सोमवार को आम श्रद्धालुओं के लिए खुलने के बाद देश के अलग-अलग हिस्सो से आए श्रद्धालुओं को भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए कतारों में खड़े देखा गया। अधिकारियो ने बताया कि मंदिर में सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दर्शन करने की अनुमति होगी।

पुलिस ने धार्मिक जुलूस की अनुमति मांग रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया

आगर-मालवा (मप्र)। मध्य प्रदेश के आगर मालवा शहर के पास राजमार्ग को अवरुद्ध कर भगवान शिव का वार्षिक जुलूस निकालने की अनुमति की मांग को लेकर पथराव करने वाले कुछ संगठनो के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने सोमवार को लाठीचार्ज किया। एक अधिकारी ने बताया कि पथराव मे पुलिस के कुछ वाहनो के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए है। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि उन्हे आगर-मालवा शहर मे पारंपरिक बैजनाथ शाही सवारी निकालने की अनुमति दी जाए। स्थानीय प्रशासन ने 16 अगस्त को कोविड-19 के नियमो का पालन करते हुए जुलूस के आयोजन को अनुमति दी थी लेकिन कुछ हिदू संगठन और भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य इससे खुश नही थे और उन्होने सवारी जुलूस आयोजित करने की अनुमति देने की मांग की थी।

को-विन पोर्टल के जरिए डिजिटल प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि कोविड-रोधी टीके के परीक्षण मे हिस्सा लेने वाले लोगो को को-विन पोर्टल के जरिए डिजिटल प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने एक बयान मे कहा कि उसे परीक्षण मे शामिल प्रतिभागियो से को-विन पोर्टल के माध्यम से प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा, एक स्वागत योग्य पहल के तहत अब कोविशील्ड और कौवैक्सिन के नैदानिक परीक्षण मे हिस्सा लेने वालो को डिजिटल कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र को-विन के जरिए जारी किए जाएंगे। राष्ट्र कोविड-19 टीका अनुसंधान एवं उपचार मे उनके योगदान एवं प्रतिबद्धता के लिए आभारी है।

कोविड स्थिति नियंत्रण में है, बंगाल में उपचुनाव की तारीखों की घोषणा करे निर्वाचन आयोग : ममता

भाषा। कोलकाता

बंगाल में पूजा की छुट्टियों के बाद फिर से खुल सकते हैं स्कूल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि अगर राज्य मे कोविड-19 की स्थिति और खराब नही होती है तो पूजा की छुट्टियो के बाद स्कूल फिर से खुल जाएंगे। उन्होने यह भी कहा कि नियमित कक्षाओं के लिए परिसरों को फिर से खोले जाने से पहले शिक्षण संस्थानो मे स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। ममता ने संवाददाताओ से कहा, बंगाल मे स्कूल पूजा (छुट्टियो) के बाद फिर से खुलेंगे, बशर्ते स्थिति अनुकूल हो। अगर तीसरी लहर खतरनाक नही होती है, तो हम स्कूल की इमारतो को संक्रमणमुक्त करेंगे और फिर उन्हें खोला जाएगा। हम स्कूलो को फिर से शुरू करने के लिए उत्सुक है। हम चाहते है छात्र स्कूल जाएं। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि राज्य मे अभी कोरोना की स्थिति नियंत्रण मै है। उन्होने स्पष्ट किया कि यदि मामलो की संख्या बढ़ती है, जैसा महाराष्ट्र और केरल मे हुआ मुझे नही मालूम कि तब क्या निर्णय लिए जाएंगे।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि बंगाल में कोविड-19 की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और निर्वाचन आयोग को राज्य की सात विधानसभा सीटों के लिए लंबित उपचुनाव की तारीखों की तत्काल घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों में कटौती न हो। बनर्जी ने कहा, (चुनाव खत्म हुए) पहले ही चार महीने हो चुके हैं और अब कोविड -19 स्थिति भी पूरी तरह से नियंत्रण में है। लोगों को अपना वोट डालने का अधिकार है ... उन्होंने (ईसीआई) ने राजनीतिक दलों से राय मांगी थी। उन्होंने राज्य सचिवालय में कहा, मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग को तुरंत उपचुनाव की तारीखों की घोषणा करनी चाहिए क्योंकि हमें लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों में कटौती नहीं करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की सात विधानसभा सीटों जंगीपुर, शमशेरगंज, खरधा, भवानीपुर, दीनाहाटा, शांतिपुर और गोशाबा में उपचुनाव होने हैं। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सूत्रों के अनुसार, नंदीग्राम सीट पर भाजपा के शुभेंदू अधिकारी से हारने वाली मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती हैं।

केंद्र की मौद्रीकरण योजना जन-विरोधी, तत्काल वापस लिया जाए: तृणमूल कांग्रेस

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया कि केंद्र की राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना (एनएमपी) साठगांठ वाले पूंजीपतियों द्वारा सरकार का निजीकरण करने का उदाहरण है और इस जन-विरोधी फैसले को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के मुख्य सचेतक सुखेंदु शेखर राय ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले कभी केंद्र सरकार ने इतना असहाय होकर कॉर्पोरेट जगत के सामने समर्पण नहीं किया। भाजपा सरकार कॉर्पोरेट द्वारा, कॉर्पोरेट की और कॉर्पोरेट के लिए है। साठगांठ वाले पूंजीपतियों ने सरकार का पूरी तरह निजीकरण कर दिया है। राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना की आड़ में यह दरअसल एक निजीकरण कार्यक्रम है।

क्विक न्यूज

टीबी रोगियों पर गंभीर कोविड के प्रभाव का अध्ययन करेंगे ब्रिक्स देशों के शोधकर्ता

नई दिल्ली। ब्रिक्स देश तपेदिक (टीबी) के रोगियों पर गंभीर कोविड-19 स्थितियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सोमवार को यह जानकारी दी। सार्स-कोव-2 एनजीएस (नेक्स्ट जेनरेशन सीक्वेंसिंग) -ब्रिक्स कोविड-19 स्वास्थ्य-संबंधी ज्ञान को आगे बढ़ाने व स्वास्थ्य परिणामों में सुधार में योगदान के लिए एक अंत:विषय सहयोग संघ है।

गुजरात में सामने आए कोरोना के 14 नए मामले

अहमदाबाद। गुजरात में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 14 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 8,25,316 हो गई जबकि किसी भी मरीज की मौत नहीं होने से मृतकों की संख्या अभी 10,079 है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिनभर में 25 लोग संक्रमण से उबरे, जिसके साथ ही 8,15,041 मरीज ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 171 मरीज उपचाराधीन हैं। उनके अनुसार सोमवार को वड़ोदरा और सूरत जिलों में चार-चार और अहमदाबाद में तीन नए मामले सामने आए।

भारत और फिलीपीन की नौसेना ने युद्धाभ्यास किया

नई दिल्ली। भारत और फिलीपीन की नौसेना ने सोमवार को पश्चिमी फिलीपीन सागर में युद्धाभ्यास किया जो अहम जलमार्ग में उनके बढ़ते सामरिक सहयोग को प्रतिबंबित करता है। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय नौसेना की ओर से निर्देशित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस रणविजय और निर्देशित मिसाइल पोत आईएनएस कोरा ने हिस्सा लिया जबकि फिलीपीन नौसेना का प्रतिनिधित्व उसके फ्रीगेट बीआरपी एंतोनियो लुना ने किया।

केंद्र कोविड-19 टीकाकरण बढ़ाने का प्रयास कर रहा है : जी किशन रेड्डी

भाषा। हैदराबाद

केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार को कहा कि केंद्र देश में कोविड-19 के विरूद्ध टीकाकरण बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास कर रहा है तथा इसके तहत वह उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य देशों से कच्चे माले की खरीददारी बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए टीकाकरण तथा मास्क लगाने जैसे नियमों के अनुपालन पर जोर देते हुए उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि कुछ लोगों को इस बात से आश्चर्य होता है कि टीके आसानी से उपलब्ध क्यों नहीं हैं। मंत्री ने कहा कि संबंधित कच्चा माल आने के 100 से अधिक दिन बाद कोई भी टीका (उपयोग के लिए) फैक्टरी से तैयार होकर बाहर आता है। उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए कच्चा माल अमेरिका जैसे देशों से प्राप्त किया जाता है तथा वह आसानी से मिलता भी नहीं है क्योंकि कोई भी विदेशी कंपनी अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा किए बगैर तथा अपनी स्थानीय सरकार की अनुमति के बिना निर्यात नहीं कर पाएगी। रेड्डी ने कहा कि लेकिन केंद्र कच्चे माले की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की सरकारों से बातचीत कर रहा है और तथा उत्पादन संयंत्रों में कर्मी तीन पालियों में काम कर रहे है।

कोलकाता की आवासीय सोसाइटियों में दुर्गा पूजा में पुजारियों, ढाकियों के लिए कोविड टीकाकरण अनिवार्य

कोलकाता। कोलकाता में बड़े आवासीय परिसर इस साल दुर्गा पूजा के लिए तैयार हो रहे हैं और ऐसी अनेक सोसाइटियों में अक्टूबर में चार दिन तक चलने वाले इस महोत्सव के लिए पुजारियों, ढाकियों या ढोल वादकों तथा अन्य सभी को टीकाकरण कराना अनिवार्य होगा। हालांकि इस वर्ष महामारी के कारण यह पर्व परंपरागत भव्यता के साथ नहीं मनाया जा सकेगा। शहर की अनेक आवासीय सोसाइटियों ने खूटी पूजा कर भी ली है जिसमें दुर्गा पूजा पंडाल लगाने से पहले एक स्तंभ की पूजा की जाती है। हालांकि उन्हें पूजा संबंधी कुछ योजनाओं को महामारी की तीसरी लहर की आशंका के खतरे को देखते हुए टालना या बदलना पड़ सकता है। सिल्वर स्प्रिंग आवासीय परिसर के सचिव इंद्रनील चौधरी ने कहा, पुजारियों, ढाकियों, पंडाल निर्माताओं, बिजली का काम करने वालों और पंडाल के कामकाज से जुड़े अन्य सभी लोगों को टीके की कम से कम एक खुराक लगाई जाएगी। पूजा पंडालों में बाहरी लोगों का प्रवेश नियंत्रित होगा और उन्हें टीके की कम से कम एक खुराक लेना या कोविड-19 का संक्रमण नहीं होने संबंधी प्रमाणपत्र साथ में रखना अनिवार्य होगा। इस सोसाइटी में रक्षा बंधन के दिन खूटी पूजा संपन्न हो गई है।

PUBLIC NOTICE

Know all men through these present that I, Kapil Dev S/o Late Sh.Kasturi Lal, R/o D-42, South Extension-II, New Delhi, am the attorney of Sh. Vikramjeet Singh S/o Late Major General Ram Singh vide General Power of Attorney dated 29.11.1996 duly registered as document no. 17756 in Addl. Book No. IV, Volume No.856, on pages 178 to 179, on 29.11.1996, in the office of the sub-registrar, New Delhi, am duly authorized to enter into any agreement to sell, receive consideration and execute sale deed in respect of front terrace of property bearing no. D-69, Panchsheel Enclave, New Delhi.
Any person(s) having any objection in respect of the above stated property or part thereof by way of sale/purchase, exchange, mortgage, charge, gift, maintenance, inheritance, possession, lease, tenancy, sub-tenancy, lien, license, hypothecation, transfer of title or beneficial interest under any trust right of prescription or pre-emptioner under any agreement or other disposition or under any decree, order or whatsoever may contact the undersigned within 15 days from the publishing of this notice.
Kapil Dev
D-42, South Extension-II, New Delhi

PUBLIC NOTICE

This is to inform to all concerned publlic at-large that Sh. Devender Kumar, Sh. Subhas Chand, Sh. Jitender Kumar, Sh. Yogender Kumar, Sh. Ashok Kumar all S/o Lt. Sh. Ram Kumar and Smt. Bala Devi alias Raj Bala W/o Lt. Sh. Ram Kumar All R/o Village-Bahlolpur, Noida, U.P. is the original allottee of residential plot No. Ch-63, Block-CH, Sector-145, Noida (area 73.32sq.meters). AND Sh. Subhas Chand, Sh. Jitender Kumar, Sh. Yogender Kumar, Sh. Ashok Kumar all S/o Lt. Sh. Ram Kumar R/o Village-Bahlolpur, Noida U.P. given GPA to in favour of Sh. Devender Kumar S/o Lt. Sh. Ram Kumar R/o Village-Bahlolpur, Noida U.P. which registered in Gautam Buddha Nagar on dated 10/11/2017. The aforesaid property has been sold on the basis of GPA dated 10/11/2017 which was registered at Gautam Budh Nagar in favour of Sh. Devender Kumar S/o Lt. Sh. Ram Kumar R/o Village-Bahlolpur, Noida, U.P. Now the said plot is being transferred in favour of Sh. Mahesh Singh Chauhan S/o Sh. Dev Dutt Singh R/o B-4, Sector-33, Noida, U.P. if anybody has/have any objection may file objection in 30 days from the date of publication of this notice of Residential Plots Department of Noida Authority. Sh. Mahesh Singh Chauhan

इंदौर में भीड़ द्वारा पीटे गए चूड़ी विक्रेता पर नाबालिग छात्रा के लैंगिक उत्पीड़न का मामला दर्ज

इंदौरा, भोपाल। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में फेरी लगाकर चूड़ियां बेच रहे 25 वर्षीय व्यक्ति को भीड़ द्वारा नाम पूछे जाने के बाद पीटे जाने पर मचे बवाल के बीच नया मोड़ आ गया, जब पुलिस ने सोमवार शाम इस शख्स पर 13 वर्षीय स्कूली छात्रा के लैंगिक उत्पीड़न और दस्तावेजों की जालसाजी के आरोपों में मामला दर्ज किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कक्षा छह में पढ़ने वाली छात्रा ने बाणगंगा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि रविवार दोपहर तस्लीम अली (25) अपना नाम गोलू पिता मोहनसिंह बताकर चूड़ियां बेचने उसके घर आया और उसने उसे बहुत सुंदरै बताते हुए बुरी नीयत से उसके शरीर को छुआ। नाबालिग लड़की ने शिकायत में कहा कि अली की इस हरकत को लेकर उसके शोर मचाने पर उसकी मां उसके पास पहुंची, तो चूड़ी विक्रेता उन्हें जान से मारने की कथित धमकी देकर भागने लगा, लेकिन आस-पड़ोस के लोगों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। उन्होंने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि अली द्वारा जल्दबाजी में छोड़ दी गई थैली से दो आधार कार्ड मिले हैं और इनमें से एक में इसके धारक के नाम के रूप में असलीम पिता मोरसि ंहै छपा है, जबकि दूसरे आधार कार्ड में तस्लीम पिता मोहर अली छापा गया है।

भोपाल में भुजरिया उत्सव के अवसर पर महिला श्रद्धालु सिर पर गेहूं के पौधे लिए हुए

संवेदनशील मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार के रवैए पर हतप्रभ: सुप्रीम कोर्ट

भाषा। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह बेटी के कथित यौन शोषण से संबंधित संवेदनशील मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार के रवैए पर हतप्रभ है। न्यायालय ने इस मामले में 636 दिन के विलंब से अपील दायर करने पर सख्त रूख अपनाया और राज्य पर 25 हजार रुपए का जुर्माना किया।

यह मामला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दिसम्बर, 2018 के फैसले के खिलाफ अपील से संबंधित है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने आरोपी पिता को बरी कर दिया था। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने अपील दायर करने में 636 दिन के विलंब का जिक्र करते हुए अपने आदेश में कहा कि इस देरी के लिए राज्य जरा भी शर्मिंदा नहीं है। पीठ ने कहा कि वह इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए समय सीमा के बाद दायर अपील खारिज नहीं करेगी। साथ ही पीठ ने यह विलंब माफ करते हुए राज्य पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और यह राशि चार सप्ताह के भीतर उच्चतम न्यायालय समूह सी (गैर लिपिक) कर्मचारी कल्याण संघ में जमा कराने का आदेश दिया। पीठ ने कहा, लेकिन यह कोई बहाना नहीं है कि इस तरह की अत्यधिक देरी के लिए राज्य के साथ ही और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को जवाबदेह क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने राज्य को जांच करने, जिम्मेदारी तय करने और देरी के लिए संबंधित अधिकारियों से राशि वसूल करने का निर्देश दिया और कहा कि वसूली का प्रमाण पत्र भी उसके समक्ष दायर किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य द्वारा दाखिल याचिका पर पीठ ने नोटिस जारी किया और मामले में बरी किए गए व्यक्ति से जवाब मांगा।

प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू करने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ न्यायालय में अर्जी

नई दिल्ली। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 24 अगस्त से प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू करने के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अर्जी दी गई है। कोविड के कारण अदालत में प्रत्यक्ष सुनवाई मार्च से निलंबित थी। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने 16 अगस्त को अधिसूचना जारी की जिसमें मुकदमों की प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू होने की स्थिति में लागू होने वाले विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए थे। वकीलों की संस्था ऑल इंडिया ज्यूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में अदालत से जारी अधिसूचना रद्द करने का भी अनुरोध किया गया है क्योंकि उसमे कहा गया है कि वर्चुअल सुनवाई की कोई अर्जी अब स्वीकार नहीं की जाएगी।

सांकेतिक कब्जा सूचना

ICICI Bank
शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लि., तृतीय तल, प्लॉट नंबर 23, शाल टावर, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005

जबकि,
अधोहस्ताक्षरी ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवर्णित कर्जदारों को मांग सूचनाएं जारी की थी, जिसमें उनसे सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि का भुगतान, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।
जबकि कर्जदार उपरोक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा निम्नवर्णित तिथियों को प्राप्त कर लिया है।
कर्जदार को विशेष रूप से तथा जन साधारण को एतद्द्वारा उक्त सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की बकाया राशि के प्रभाराधीन होगा।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम/ऋण खाता संख्या	सम्पत्ति का वर्णन/सांकेतिक कब्जा की तिथि	मांग सूचना की तिथि/मांग सूचना में राशि (रू.)	शाखा का नाम
1.	हर्ष कुमार/हरीश कुमार/बालाजी टुअर्स ऐंड पैकिजेज प्रा. लि./हंसू /बीना देवी/ एलबीडीईएल00002009026 एलबीडीईएल00002009029	फ्लैट नंबर 9515, ड्यूपलेक्स प्रथम तल एवं द्वितीय तल ड्यूपलेक्स, ब्लॉक-सी, पाकेट-9, कैटेगिरी-III, वसंत कुंज, दिल्ली-110070/ 18 अगस्त, 2021	16-04-2021 रू. 1,66,07,189/-	दिल्ली/ एनसीआर
2.	विजय कपूर/हर्ष कपूर/अंजू कपूर/निम्बस ऑटोमोटिव प्रा. लि./ एलबीएनओडी00002372355/ एलबीएनओडी00002372358/ एलबीएनओडी00002372359	प्लॉट नंबर 269, ब्लॉक-एम, द्वितीय तल मय छत, ग्रेटर कैलाश-II, दिल्ली/ 18 अगस्त, 2021	26-03-2021 रू. 2,39,06,197/-	दिल्ली/ एनसीआर
3.	नरेश शर्मा/शालिनी शर्मा एलबीडीईएल00003058205	डीडीए एमआईजी फ्लैट नंबर 23, तृतीय तल, ब्लॉक-सी, पाकेट-1, सेक्टर-15, रोहिणी, दिल्ली-110085/ 18 अगस्त, 2021	26-03-2021 रू. 39,21,399/-	दिल्ली/ एनसीआर
4.	कुमारी ब्यूटी सिन्हा/संतोष कुमार वर्मा/ एलबीडीईएल00002449910	फ्लैट नंबर डी-96, तृतीय तल, प्लॉट नंबर 24 दिल्ली सिटीजन सीजीएचएस, सेक्टर-13, रोहिणी, निकट डीसी चौक, दिल्ली-110085/18 अगस्त, 2021	26-03-2021 रू. 68,36,578/-	दिल्ली/ एनसीआर
5.	बिनोदा नंद झा/समोला देवी/कुंदन कुमार झा/ एलबीडीईएल00003789086	डीडीए एसएफएस कैट-III, फ्लैट नंबर 243, द्वितीय तल, सेक्टर-9, पाकेट-1, द्वारका, दिल्ली-110075/ 18 अगस्त, 2021	26-03-2021 रू. 57,93,717/-	दिल्ली/ एनसीआर
6.	कंचन कुमारी/रघुनाथ शर्मा/ एलबीडीईएल00002866980	एलआईजी फ्लैट नंबर 276, तृतीय तल, ब्लॉक-बी 2, पाकेट-सी, नरेला, दिल्ली/18 अगस्त, 2021	19-01-2021 रू. 12,93,262/-	दिल्ली/ एनसीआर
7.	अनंगपाल सिंह आर्य/सविता/ एलबीडीईएल00001816945	एलआईजी फ्लैट नंबर 85-बी, प्रथम तल, ब्लॉक/ पाकेट-डी-2-ए, जनकपुरी, दिल्ली/ 18 अगस्त, 2021	26-03-2021 रू. 18,40,880/-	दिल्ली/ एनसीआर
8.	शैलेन्द कुमार/राखी ध्यानी/ एलबीडीईएल00002427062	प्लॉट नंबर 121, प्रथम तल, छत का अधिकार नहीं, ब्लॉक-सी, पाकेट-5, सेक्टर-11, रोहिणी, दिल्ली/18 अगस्त, 2021	26-03-2021 रू. 35,16,927/-	दिल्ली/ एनसीआर
9.	नरेश शर्मा/शालिनी शर्मा/ एलबीडीईएल00003857631	डीडीए एमआईजी फ्लैट नंबर 23, तृतीय तल, ब्लॉक-सी, पाकेट-1, सेक्टर-15, रोहिणी, दिल्ली-110085/ 18 अगस्त, 2021	26-03-2021 रू. 3,15,984/-	दिल्ली/ एनसीआर
10.	राज कुमार देवल/रचना देवी/ एलबीडीईएल00003674173 एलबीडीईएल00003744522	डीडीए एलआईजी फ्लैट नंबर 5सी, द्वितीय तल, ब्लॉक-एमयू, पीतमपुरा, दिल्ली-110088/ 18 अगस्त, 2021	26-03-2021 रू. 10,15,733/-	दिल्ली/ एनसीआर
11.	नौनिहाल सिंह/अमृता/ एलबीडीईएल00001051203	फ्लैट नंबर ए-21, प्लॉट नंबर -8सी, आईडीसी सीजीएचएस लि., सेक्टर-11, द्वारका, दिल्ली/18 अगस्त, 2021	26-03-2021 रू. 8,86,494/-	दिल्ली/ एनसीआर

उपरोक्त कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उपरोक्त राशि 30 दिन के भीतर चुकता कर दें, अन्यथा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की अवधि व्यतीत होने पर उक्त बंधक रखी सम्पत्तियां प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002, के नियम 8 और 9 के तहत प्रावधानों के अनुसार बेच दी जाएंगी।

तिथि : 24-08-2021
स्थान : दिल्ली/एनसीआर
प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

सेंसेक्स 226 अंक चढ़ा आईटी शेयरों में चमक

भाषा। मुंबई

सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग तथा वित्तीय कंपनियों के शेयरों में जबर्दस्त लिवाली से सोमवार को सेंसेक्स 226 अंक चढ़ गया। वैश्विक बाजारों के सकारात्मक रुख से भी बाजार को मजबूती मिली। इसके अलावा सोमवार के कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे मजबूत हुआ। इससे भी बाजार धारणा को समर्थन मिला। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सोमवार को दो कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट के सिलसिले से उबर गया। दिन में कारोबार के दौरान यह 450 अंक तक ऊपर गया।

कारोबार की समाप्ति पर अंत में यह 226.47 अंक या 0.41 प्रतिशत की बढ़त के साथ 55,555.79 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 45.95 अंक या 0.28 प्रतिशत के लाभ से 16,496.45 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में एचसीएल टेक का शेयर सबसे अधिक 4.10 प्रतिशत चढ़ गया। टीसीएस, बजाज फिनसर्व, नेस्ले इंडिया, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा और कोटक बैंक के शेयर भी लाभ में रहे।

टॉप गेनर		टॉप लूजर	
एचसीएल टेक	4.10	महिन्द्रा-महिन्द्रा	-2.50
टीसीएस	2.20	बजाज ऑटो	-2.23
बजाज फिनसर्व	2.06	अल्ट्रा टेक सीमेंट	-1.88
नेस्ले	1.78	पावर ग्रिड कॉर्प	-1.57
भारती एयरटेल	1.57	आईटीसी	-1.29

टॉप गेनर		टॉप लूजर	
एचसीएल टेक	4.26	ग्रासिम	-3.14
टीसीएस	2.12	अदानी पोर्ट्स	-2.78
नेस्ले	2.02	महिन्द्रा-महिन्द्रा	-2.63
बजाज फिनसर्व	1.88	आयशर मोटर्स	-2.33
ओएनजीसी	1.59	बजाज ऑटो	-2.25

पीटीआई ग्राफिक

वहीं दूसरी ओर महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावरग्रिड, आईटीसी, एशियन पेंट्स और टाटा स्टील के शेयर 2.50 प्रतिशत तक टूट गए। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि स्मॉलकैप और मिडकैप शेयरों में भारी बिकवाली जारी है। हालांकि, आईटी शेयरों के समर्थन तथा वैश्विक बाजारों के सकारात्मक रुख के बीच मुख्य सूचकांक लाभ में रहे। नायर ने कहा कि, मौजूदा सुधार से दीर्घावधि निवेशकों को गुणवत्ता वाले शेयरों को फिर खरीदने का मौका मिलेगा। वैश्विक बाजारों के मजबूत संकेतों से बाजार को कुछ समर्थन मिला।

आईटी शेयरों में लाभ से बाजार धारणा बेहतर हुई। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप 1.55 प्रतिशत तक इस बीच अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल 2.95 प्रतिशत के उछाल से 66.66 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 17 पैसे की बढ़त के साथ 74.22 प्रति डॉलर पर पहुंच गया।

दिल्ली हवाईअड्डे के कर्मचारियों के लिए कोविड देखभाल केंद्र बनाएगी एमओयू

नई दिल्ली। दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लि. (डायल) ने दिल्ली हवाईअड्डे पर अपने कर्मचारियों तथा उनके परिजनों के लिए कोविड देखभाल केंद्र बनाने के लिए मेदांता अस्पताल के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) किया है।

कोविड देखभाल केंद्र हवाईअड्डे के टर्मिनल दो में बनाया जाएगा। जीएमआर समूह की अगुवाई वाली डायल ने कहा कि है कि कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच हमने यह कदम उठाया है। यह देखभाल केंद्र सितंबर की शुरुआत में चालू हो जाएगा।

एक बयान में कहा गया है कि इस केंद्र पर हल्के तथा मामूली संक्रमण वाले जीएमआर के कर्मचारियों या उनके परिजनों के पृथकवास की व्यवस्था होगी। उसके बाद या तो उन्हें घर भेज दिया जाएगा या आवश्यकता होने पर अस्पताल स्थानांतरित किया जाएगा।

स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग नियमों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल को समर्थन

भाषा। नई दिल्ली

बड़ी कंपनियों को छोड़कर, अधिकांश आभूषण विक्रेताओं की दुकानें सोमवार को नए स्वर्ण आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग के सरकार के नियमों के विरोध में बंद रहीं। हड़ताल आभूषण विक्रेताओं के 350 के करीब संघों के आह्वान पर हुई। अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद (जीजेसी) ने यह कहा।

आभूषण विक्रेता संगठन सरकार की हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान संख्या (एचयूआईडी) प्रणाली के खिलाफ हैं, जिसके बारे में उनका कहना है कि इसका सोने की शुद्धता से कोई लेना-देना नहीं है, यह सिर्फ एक ट्रैकिंग तंत्र है। अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद (जीजेसी) के निदेशक दिनेश जैन ने पीटीआई-भाषा से बात करते हुए कहा, एचयूआईडी प्रणाली के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। दुकानें एक दिन के लिए बंद हैं। हालांकि तमिलनाडु और केरल में ओणम त्योहार के कारण दोपहर 12.30 बजे तक दुकानें बंद रहीं। जैन ने कहा कि प्रदर्शनकारी ज्वैलर्स गोल्ड हॉलमार्किंग नियमों के खिलाफ जिला कलेक्टरों को ज्ञापन देंगे।

स्वर्ण आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग, कीमती धातु का शुद्धता प्रमाणन है। यह नियम 16 जून से चरणबद्ध तरीके से लागू हो गया है। सरकार ने पहले चरण के कार्यान्वयन के लिए 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 256 जिलों की पहचान की है। पिछले हफ्ते, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने जौहरियों के संगठनों से हड़ताल वापस लेने का आग्रह किया था, जिसमें कहा गया था कि सोने की हॉलमार्किंग का कार्यान्वयन अब तक बेहद सफल रहा है। बीआईएस देश में गोल्ड हॉलमार्किंग सिस्टम लागू कर रहा है।

विरोध करने वाले जौहरियों के निकायों के अनुसार, सोने की हॉलमार्किंग की पहले की प्रक्रिया नई एचयूआईडी प्रणाली से बेहतर थी। नई प्रणाली व्यापार करने में आसानी के सिद्धांत के खिलाफ है। ज्वैलर्स के निकायों को डर है कि सरकार नए एचयूआईडी सिस्टम के नाम पर अपलोड किए जा रहे डेटा का इस्तेमाल ज्वैलर्स पर कार्वाई करने के लिए कर सकती है।

जैन ने कहा कि एचयूआईडी प्रणाली को लागू करने में एक व्यावहारिक समस्या है। मान लीजिए कि एक थोक व्यापारी के पास 50 किलो के सोने के हालमार्किंग वाले आभूषण है। एक खुदरा विक्रेता उसके पास आता है और एक किलो आभूषण खरीदता है।

पीएलआई योजना राजस्व बढ़ाने में मदद करेगी: सूर्या रोशनी

नई दिल्ली। सूर्या रोशनी का मानना है कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों के लिए पासा पलटने वाली होगी। इससे कंपनियां अपनी सुविधाओं का विस्तार कर सकेंगी।

सूर्या रोशनी ने अपनी ताजा वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि सरकार की पीएलआई योजना के साथ अन्य पहलों मसलन मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के जरिए उपभोक्ता लाइटिंग खंड में उसका कारोबार बढ़ा है। साथ ही इन योजनाओं से उसके मुनाफे में भी वृद्धि हुई है। सूर्या रोशनी लाइटिंग और टिकाऊउपभोक्ता सामान, इस्पात की पाइप और स्ट्रिप्स के क्षेत्र में परिचालन करती है। कंपनी के प्रबंध निदेशक राजू बिस्ता ने शेयरधारकों को संबोधित करते हुए कहा कि टिकाऊ उपभोक्ता सामान क्षेत्र में कंपनी पंखे और उपकरणों का कारोबार बढ़ा रही है। इसके साथ ही कंपनी विपणन और ब्रांड निर्माण के लिए निवेश कर रही है।

एएमएनएस इंडिया की भी आरआईएनएल के लिए बोली लगाने की योजना

भाषा। नई दिल्ली

गुजरात की कंपनी एएमएनएस इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआईएनएल) के लिए बोली लगाने की तैयारी कर रही है। इससे पहले टाटा स्टील भी आरआईएनएल में रुचि दिखा चुकी है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। आरआईएनएल आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्थित विशेष इस्पात बनाने वाली कंपनी है। यह कंपनी इस्पात मंत्रालय के तहत आती है। कंपनी राज्य में 73 लाख टन के इस्पात संयंत्र का परिचालन करती है। मामले से जुड़े सूत्र ने कहा कि एएमएनएस इस विकल्प पर विचार कर रही है। इस बारे में एएमएनएस को भेजे ई-मेल का जवाब नहीं मिला। टाटा स्टील के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने हाल में कहा था कि उनकी कंपनी आरआईएनएल के अधिग्रहण की इच्छुक है। यह संयंत्र रणनीतिक रूप से पूर्वी तट पर स्थित है। इस अधिग्रहण से उसकी दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजारों में पहुंच बढ़ेगी।

मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने 27 जनवरी को आरआईएनएल में सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश के लिए सैद्धान्तिक मंजूरी दी थी। एएमएनएस ने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया था कि उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात करेंगे।

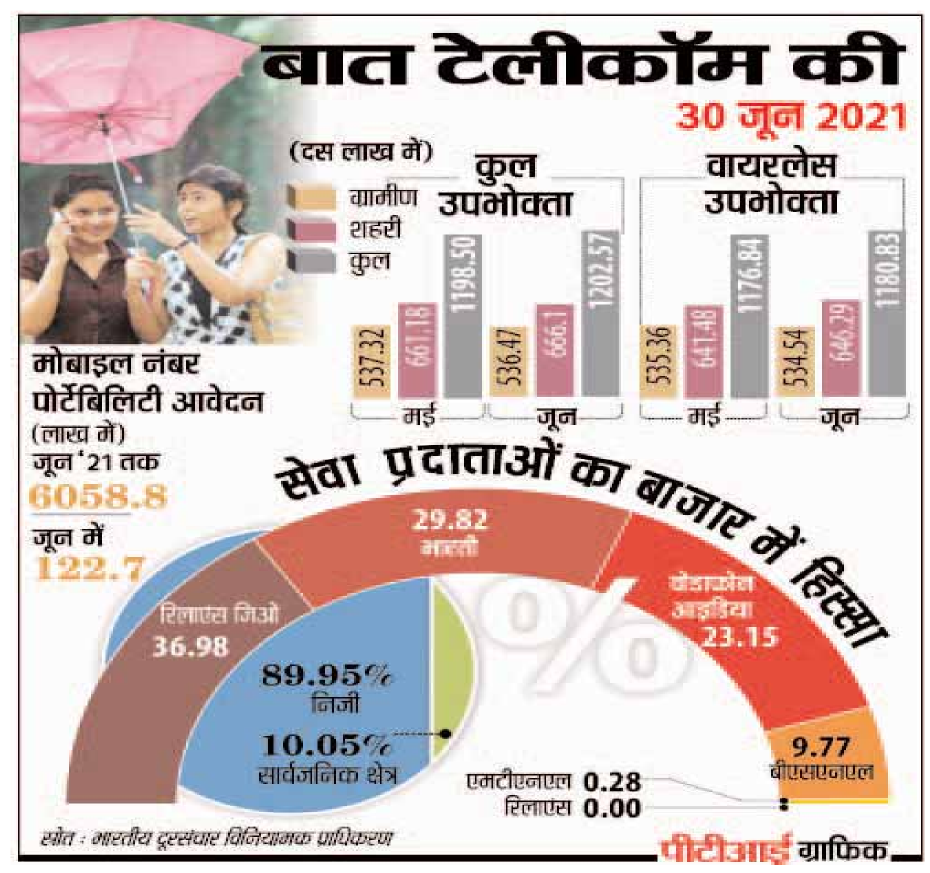

कोविड प्रतिबंधों में ढील के साथ आर्थिक गतिविधियों में सुधार हुआ मजबूत: इक्रा

भाषा। मुंबई

इक्रा रेटिंग्स ने सोमवार को कहा कि राज्यों द्वारा कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों में ढील के साथ जुलाई 2021 में आर्थिक गतिविधियों में सुधार की बुनियाद मजबूत हुई है। रेटिंग एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में कारोबारी गतिविधियों पर लगाई गई रोक को वापस लेने के बाद जुलाई 2021 में विभिन्न उच्च आवृत्ति वाले औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के संकेतकों, आवाजाही और टोल संग्रह में सुधार देखने को मिला है। इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने रिपोर्ट में कहा, विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों सहित अन्य राज्यों द्वारा प्रतिबंधों में ढील बढ़ाने के साथ जुलाई 2021 में आर्थिक सुधार की जड़ें गहरी हो गईं। सामान्य आधार प्रभाव के बावजूद 15 उच्च आवृत्ति संकेतकों में से आठ ने सालाना आधार पर जुलाई 2021 में उत्साहजनक सुधार दर्ज किया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 13 गैर-वित्तीय संकेतकों में से 10 ने जुलाई 2021 में सालाना आधार पर वृद्धि दर्ज की। हालांकि, सुधार की गति जून 2021 में देखे गए स्तरों से कम रही। जून 2021 की तुलना में जुलाई 2021 में जीएसटी ई-वे बिल, ईंधन की खपत, बिजली उत्पादन, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का उत्पादन, वाहन पंजीकरण, घरेलू यात्री यातायात आदि के सालाना प्रदर्शन में सुधार हुआ।

आयकर पोर्टल में समस्याओं को लेकर वित्त मंत्री इन्फोसिस के सीईओ से मिले

भाषा। नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आयकर विभाग के नए पोर्टल में आ रही दिक्कतों के मुद्दे को इन्फोसिस लि. के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सलिल पारेख के समक्ष उठाया। इन्फोसिस ने ही इस पोर्टल को तैयार किया है।

वित्त मंत्री ने अपने कार्यालय में इन्फोसिस के सीईओ के साथ मुलाकात के दौरान यह मुद्दा उठाया कि करीब ढाई महीने बीत जाने के बाद भी पोर्टल सुचारू तरीके से काम क्यों नहीं कर रहा है। समझा जाता है कि पारेख और उनकी टीम ने इस मुद्दे को हल करने की रूपरेखा सौंपी है। आयकर विभाग ने रविवार को एक ट्विटर पोस्ट में कहा था कि वित्त मंत्री ने पारेख को तलब किया है और उनसे समस्याओं पर चीजें स्पष्ट करने को कहा गया है। यह पोर्टल सात जून से शुरू हुआ था। वहीं 21 से 22 अगस्त देर शाम पोर्टल पहुंच से दूर था। इन्फोसिस ने कहा कि आपात रखरखाव की वजह से पोर्टल उपलब्ध नहीं हुआ। बाद में दिख गया।

यह दूसरा मौका है जबकि वित्त मंत्री ने पोर्टल के मुद्दे पर इन्फोसिस की टीम से चर्चा की है। इससे पहले 22 जून को उन्होंने इन्फोसिस के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) प्रवीन राव से इस मुद्दे पर बातचीत की थी। शुरुआत से ही पोर्टल को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। प्रयोगकर्ता लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि या तो पोर्टल नहीं मिलता है या काफी धीमी रफ्तार से काम कर रहा है। इसी के मद्देनजर आयकर विभाग ने रेमिटेंस फॉर्म को मैनुअल तरीके से दाखिल करने की अनुमति दी है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फॉर्म जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाया है। आयकर विभाग ने ट्वीट किया, वित्त मंत्रालय ने इन्फोसिस के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ सलिल पारेख को 23 अगस्त को तलब किया है। पारेख को वित्त मंत्री के समक्ष बताना होगा कि कैसे इस ई-फाइलिंग पोर्टल में समस्याएं जारी हैं। 21 अगस्त से तो यह पोर्टल उपलब्ध ही नहीं है।

इन्फोसिस को अगली पीढ़ी की आयकर दाखिल करने वाली प्रणाली विकसित करने का अनुबंध 2019 में मिला था। इसका उद्देश्य तहत रिटर्न के प्रसंस्करण की अवधि को 63 दिन से घटाकर एक दिन करना था। जून, 2021 तक सरकार ने इन्फोसिस को पोर्टल के विकास के लिए 164.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।

एलआईसी के आईपीओ का प्रबंधन करने के लिए 16 मर्चेंट बैंकर दौड़ मे

भाषा। नई दिल्ली

जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) का प्रबंधन करने की दौड़ में 16 मर्चेंट बैंकर शामिल हैं। इसे देश के इतिहास की सबसे बड़ी शेयर बिक्री कहा जा रहा है। बैंकर 24 और 25 अगस्त को निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के समक्ष अपना प्रस्तुतीकरण देंगे। दीपम के सर्कुलर के अनुसार, बीएनपी परिबा, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया और डीएसपी मेरिल लिंच (अब बोफा सिक्योरिटीज) सहित सात अंतरराष्ट्रीय बैंकर मंगलवार को प्रस्तुतीकरण देंगे। मंगलवार को जो अन्य बैंकर प्रस्तुतीकरण देंगे उनमें गोल्डमैन सैश (इंडिया) सिक्योरिटीज, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया), जेपी मॉर्गन इंडिया, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) शामिल हैं। बुधवार को नौ घरेलू बैंकर दीपम के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुतीकरण देंगे। इनमें एक्सिस कैपिटल लि., डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स, एचडीएफसी बैंक लि., आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लि., आईआईएफएल सिक्योरिटीज लि., जेएम फाइनेंशियल लि., कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लि., एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि. और यस सिक्योरिटीज इंडिया लि. शामिल हैं।

शेयर और ऋण कोषों की ओर बढ़ा निवेशकों का रुझान

भाषा। नई दिल्ली

गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (गोल्ड ईटीएफ) से निवेशकों ने जुलाई में 61 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी की है। इससे पहले लगातार सात माह तक गोल्ड ईटीएफ में निवेश का प्रवाह देखने को मिला था। इस दौरान आकर्षक रिटर्न की वजह से शेयरों तथा ऋण कोषों में निवेशकों का रुझान बढ़ा है जिसकी वजह से वे गोल्ड ईटीएफ से निकासी कर रहे हैं।

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के आंकड़ों के अनुसार, इस श्रेणी में नकारात्मक प्रवाह के बावजूद जुलाई में फोलियो की संख्या बढकर 19.13 लाख हो गई,जो इससे पिछले महीने 18.32 लाख थी। फरवरी, 2020, दिसंबर, 2020 और जुलाई, 2021 को छोड़कर अगस्त, 2019 से ईटीएफ में निवेश लगातार बढ़ रहा है। आंकड़ों के अनुसार गोल्ड ईटीएफ श्रेणी में दिसंबर, 2020 से निवेश का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है। इस साल जुलाई में गोल्ड ईटीएफ से 61.5 करोड़ रुपए की निकासी हुई। इससे पिछले महीने यानी जून में गोल्ड ईटीएफ में 360 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। मई में इस श्रेणी में 288 करोड़ रुपए का निवेश आया था। चालू साल के पहले छह माह में निवेशकों ने इस श्रेणी में 3,107 करोड़ रुपए डाले हैं। इससे पहले नवंबर, 2020 में गोल्ड ईटीएफ से 141 करोड़ रुपए तथा फरवरी, 2020 में 195 करोड़ रुपए की निकासी हुई थी।

बी737 विमान के कलपुर्जों का निर्माण करेगी महिंद्रा एरोस्ट्रक्टर्स

नई दिल्ली। विमान विनिर्माता कंपनी बोइंग ने महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर्स को अपने बी737 विमान के इनलेट आउटर बैरल कलपुर्जे के विनिर्माण और सब-असेंबली तथा उन्हें अमेरिका स्थित अपने प्रतिष्ठानों को आपूर्ति करने का अनुबंध दिया है। किसी विमान के इंजन का इनलेट डक्ट कंप्रेसर में प्रवेश करने से पहले हवा के प्रवाह को नियंत्रित करता है।महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर ने एक बयान में कहा कि नए अनुबंध के अनुरूप कलपुर्जों का उत्पादन और सब-असेंबली का काम 2023 में शुरू होगा।

पेज 1 का शेष

रेल, हाइवे, ऊर्जा...

यानी इनविट के जरिए इन राजमार्गों के लिए संसाधन जुटाए जाएंगे। अनुमानित 1.2 लाख करोड़ रुपए के मौद्रिकरण परियोजना में 400 रेलवे स्टेशनों, 90 यात्री ट्रेनों, 741 किलोमीटर लंबे कोंकण रेलवे और 15 रेलवे स्टेडियमों और कॉलोनियों का मौद्रिकरण करने की योजना है। निजी भागीदारी के जरिए इनका विकास किया जाएगा। बिजली के 28,608 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनों के मौद्रिकरण से 45,200 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है और अन्य 39,832 करोड़ रुपए छह गीगावाट की विद्युत उत्पादन संपत्तियों से आएंगे। दूरसंचार क्षेत्र में भारतनेट फाइबर के 2.86 लाख किलोमीटर और बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के 14,917 सिग्नल टावरों के मौद्रिकरण से 35,100 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसी प्रकार गोदामों और कोयला खदानों में मौद्रिकरण से 29,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। वहीं 8,154 किलोमीटर लंबे प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के मौद्रिकरण से 24,462 करोड़ रुपए और 3,930 किलोमीटर उत्पाद पाइपलाइनों के मौद्रिकरण से 22,504 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। हवाई अड्डों के मौद्रिकरण से 20,782 करोड़ रुपए और बंदरगाहों से 12,828 करोड़ रुपए मिलेंगे। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम सहित दो राष्ट्रीय स्टेडियम और बेंगलुरु एवं जीरकपुर में स्थित दो क्षेत्रीय केंद्रों के मौद्रिकरण से 11,450 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। दिल्ली में सरोजिनी नगर एवं नौरोजी नगर सहित सात आवासीय कॉलोनियों के पुनर्विकास और साथ ही घिटोरनी में 240 एकड़ भूमि पर आवासावाणिज्यिक इकाइयों के विकास से भी 15,000 करोड़ रुपए जुटाए जाने का आकलन है।

पुलिस बल में दाढ़ी रखना...

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात पारित अपने निर्णय में कहा कि 26 अक्टूबर 2020 का सर्कुलर एक कार्यकारी आदेश है, जो पुलिस बल में अनुशासन को बनाए रखने के लिए जारी किया गया है। पुलिस बल को एक अनुशासित बल होना चाहिए और एक कानून प्रवर्तन एजेंसी होने के कारण इसकी छवि भी सेक्युलर होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि अपने एसएचओ (थाना प्रभारी) की चेतावनी के बावजूद दाढ़ी न कटवा कर याची ने कदाचरण किया है। 12 अगस्त 2021 को याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने अधिकारियों को याचिकाकर्ता के खिलाफ कानून के अनुसार विभागीय जांच पूरी करने का निर्देश दिया।

अफगान संकट पर...

सरकार की ओर से होने वाली यह बैठक अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के अभियान पर केंद्रित रहने की उम्मीद है तथा इसमें वहां के हालात को लेकर सरकार के आकलन की भी जानकारी दी जा सकती है। अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के अभियान के तहत भारत सिख और हिंदू समुदाय के अफगान समेत करीब 730 लोगों को यहां ला चुका है। अफगानिस्तान से निकालकर लाए गए 146 भारतीय नागरिक कतर की राजधानी से चार अलग-अलग विमानों के जरिए सोमवार को भारत पहुंचे। इन नागरिकों को अमेरिका और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के विमान के जरिए पिछले कुछ दिन में काबुल से दोहा ले जाया गया था। भारत तीन उड़ानों के जरिए दो अफगान सांसदों समेत 392 लोगों को रविवार को देश वापस लाया। इससे पहले, 16 अगस्त को 40 से अधिक लोगों को स्वदेश लाया गया था जिनमें से ज्यादातर भारतीय दूतावास के कर्मी थे। काबुल से दूसरे विमान से 17 अगस्त को 150 लोगों को लाया गया, जिनमें भारतीय राजनयिक, अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी और कुछ अन्य भारतीय शामिल थे।

तालिबान की अमेरिका को...

शाहीन ने कहा, यह लक्ष्मण रेखा है। राष्ट्रपति बाइडन ने अपने सैन्य बलों की वापसी के लिए 31 अगस्त की तारीख तय की थी। ऐसे में, अगर वे इस तारीख को आगे बढ़ाते हैं तो इसका अर्थ होगा कि वे बिना जरूरत के देश में रुकने की अपनी अवधि में विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका और ब्रिटेन को लोगों को बाहर निकालने के लिए और वक्त चाहिए तो, इसका जवाब ना है। वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे।

गुरुग्रंथ साहिब की तीन...

जो हवाईअड्डे के करीब है। लोगों को वापस लाने वाली उड़ान की घोषणा करते हुए केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया, भारतीय वायुसेना के विमान से काबुल हवाई अड्डे से पवित्र गुरुग्रंथ साहिब की तीन प्रतियों को वापस लाया जा रहा है। उसी विमान से 46 अफगान हिन्दू और सिख भी वहां फंसे भारतीय नागरिकों के साथ लौट रहे हैं। चंडोक ने कहा, विमान में 75 लोग सवार हैं। गुरुग्रंथ साहिब की तीन प्रतियां भी भारत लाई जा रही हैं। अब भी काबुल में फंसे हुए लोगों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा करते पारवान से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक की 10 किलोमीटर की दूरी के बीच विभिन्न नाके बचाव कार्य में सबसे बड़ी बाधा हैं।

पंचतत्व में विलीन हुआ...

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से राजनाथ सिंह, उप राष्ट्रपति की ओर से स्मृति ईरानी और प्रदेश की राज्यपाल की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्प चक्र अर्पित किया। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अलीगढ़ के अतरौली स्थित लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में पहुंचे जहां कल्याण का पार्थिव शरीर रखा गया था। शाह ने उनके अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शाह ने कहा, आज मैं कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए आया हूं। कल्याण सिंह का इस दुनिया से जाना भाजपा के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा, उनके जाने के साथ ही भाजपा ने अपना एक दिग्गज और हमेशा संघर्षरत रहने वाला नेता खोया है।

सितंबर-अक्टूबर के बीच...

एनआईडीएम की रिपोर्ट में आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों के अनुमान का हवाला दिया गया है जो तीसरी लहर को लेकर तीन संभावित परिदृश्यों का सुझाव देता है। उसने कहा कि पहले परिदृश्य में तीसरी लहर अक्टूबर में चरम पर पहुंच सकती है और रोजाना 3.2 लाख मामले आ सकते हैं। दूसरे परिदृश्य में, वायरस का नया और अधिक संक्रामक स्वरूप सामने आ सकता है और तीसरी लहर सितंबर में चरम स्थित पर पहुंच सकती है तथा प्रतिदिन पांच लाख मामले आने का अंदेशा है। विशेषज्ञों ने तीसरे परिदृश्य में आशंका व्यक्त की है कि तीसरी लहर की चरम स्थिति अक्टूबर के अंत में आएगी और रोज दो लाख मामले आ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, उसने प्रस्तावित किया था कि अगर 67 फीसदी आबादी में वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता (कुछ में वायरस संक्रमण और शेष में टीकाकरण के जरिए) विकसित हो जाती है तो बड़े पैमाने पर रोग प्रतिरोधक क्षमता को हासिल करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि बच्चों के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि भारत में अबतक (अगस्त के पहले हफ्ते) तक बच्चों के लिए किसी टीके को मंजूरी नहीं दी गई है। कोरोना उन बच्चों के लिए चिंता का सबब बन सकता है जिन्हें कोई बीमारी है या उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है। मंत्रालय के कोविड टीकाकरण डेशबोर्ड के मुताबिक, बीते 2 अगस्त तक 47 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके की कम से कम एक खुराक लगा दी गई है। पंडित दीनदयाल उर्जा विश्वविद्यालय (पीडीईयू) के प्रोफेसरों एवं पूर्व छात्रों द्वारा निरमा विश्वविद्यालय के सहयोग से किए गए एक अध्ययन के मुताबिक, भारत में टीकाकरण की रफ्तार 3.2 फीसदी है और इसमें सुधार नहीं किया जाता है तो महामारी की तीसरी लहर में प्रतिदिन छह लाख मामले आ सकते हैं।

सिद्धू के सलाहकारों ...

सिद्धू के दो सलाहकारों प्यारे लाल गर्ग और मलविंदर सिंह माली की कथित टिप्पणियों को लेकर नया विवाद खड़ा हुआ। गर्ग ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह द्वारा की गई पाकिस्तान की आलोचना पर सवाल उठाया था।

बिहार समेत देशभर में...

उन्होंने कहा कि यदि पशुओं और पेड़ों की गणना की जा सकती है तो लोगों की भी गणना की जा सकती है। कुमार के साथ भाजपा और कांग्रेस सहित सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए और उन्होंने मोदी को अपनी मांग सौंपी। इस मामले पर प्रधानमंत्री के जवाब के बारे में पूछे जाने पर कुमार ने कहा कि मोदी ने इसे (जाति आधारित जनगणना को) खारिज नहीं किया और हरेक की बात सुनी। प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा नेता जनक राम ने कहा कि मोदी ने एक परिवार के संरक्षक की तरह सभी की राय सुनी। उन्होंने कहा कि हर कोई संतुष्ट है और प्रधानमंत्री का फैसला सभी को स्वीकार्य होगा। जनगणना केंद्र का विशेषाधिकार होता है और इसलिए कई पार्टियों द्वारा की गई इस मांग पर फैसला केंद्र करेगा।

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों...

पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाई और ए दोनों मारे गए। उन्होंने बताया कि शेख और मंजूर के मारे जाने से सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। कुमार ने बताया, अब्बास शेख के इशारे पर शाकिब मंजूर ने कई हत्याएं की थी। उन्होंने इलाके में आतंक मचाया हुआ था।

देश में सामान्य से कम ...

अभी भी सितंबर में आईओडी के बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने समय पर शुरुआत करने और जून के अंत तक लंबी अवधि के औसत (एलपीए) के साथ सामान्य से ऊपर करीब 110 प्रतिशत के साथ अच्छी शुरुआत की थी। लेकिन यह जून के अंत में एक रुकावट के कारण जुलाई की शुरुआत कमजोर मानसून के साथ हुई।

महत्वपूर्ण लोग ही निशाने पर

उप कप्तान रहाणे ने आलोचकों को दिया करारा जवाब

भाषा । लीड्स

भारतीय टीम के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने इंग्लैंड के खिलाफ लार्ड्स में दूसरे टेस्ट में धीमी बल्लेबाजी के लिए अपनी और चेतेश्वर पुजारा की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि वे इतना क्रिकेट खेल चुके हैं कि उन्हें पता है कि भारतीय टीम के हितों के अनुकूल क्या है। रहाणे ने सोशल मीडिया पर आलोचना पर हंसते हुए कहा कि सिर्फ महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बात की जाती है। रहाणे ने 146 गेंद में 61 जबकि पुजारा ने 206 गेंद में 45 रन की पारी खेली और अपनी साझेदारी के दौरान लगभग 50 ओवर में 100 रन जोड़े।

रहाणे ने बुधवार से यहां शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट से पूर्व कहा कि मुझे खुशी है कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि लोग महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बात करते हैं इसलिए मैं इसे लेकर अधिक चिंतित नहीं हूं। यह टीम को योगदान देने से जुड़ा है। यह पूछने पर कि क्या आलोचना उन्हें प्रेरित करती है, रहाणे ने कहा कि हर चीज मुझे प्रेरित करती है। देश के लिए खेलने से मैं प्रेरित होता हूं। मैं आलोचना को लेकर परेशान नहीं होता। पुजारा ने लार्ड्स पर खाता खोलने के लिए 35 गेंद ली लेकिन उनकी और रहाणे की धीमी बल्लेबाजी का नुकसान भारत को नहीं उठाना पड़ा और टीम 151 रन से जीत दर्ज करने में सफल रही। रहाणे ने जीत के संदर्भ में कहा कि वह जिस तरह खेले उससे संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि मेरा हमेशा से योगदान देने में विश्वास रहा है और यह योगदान संतोषजनक था। रहाणे ने कहा कि आप हमेशा अपने खेल के बारे में सोचते हो लेकिन टीम का प्रदर्शन सर्वोच्च होता है। आप अपनी पारी के बारे में सोचते हो और क्या चीज आपके अनुकूल है लेकिन अंतत: हमारा ध्यान इस पर होता है कि टीम की जरूरत क्या है। पारी के दौरान पुजारा के साथ बातचीत के बारे में पूछे जाने पर रहाणे ने कहा कि वह सिर्फ टिके रहने के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बातें सिर्फ छोटे लक्ष्यों के बारे में हो रही थी और वहां से पारी को आगे बढ़ाना था। चेतेश्वर, हम हमेशा बात करते हैं कि वह धीमा खेलता है लेकिन वह पारी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। वह 200 गेंद खेला। हमने एक दूसरे का साथ दिया। रहाणे ने कहा कि चेतेश्वर और मैं काफी समय से साथ खेल रहे हैं, हमें पता है कि दबाव से कैसे निपटना है, निश्चित परिस्थितियों का सामना कैसे करना है। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, हम उसके बारे में बातें नहीं करते। भारत की मौजूदा टीम के किसी भी खिलाड़ी को हैडिंग्ले में खेलने का अनुभव नहीं है लेकिन रहाणे ने कहा कि टीम के खिलाड़ी इससे चिंतित नहीं हैं। रहाणे ने कहा कि यह बल्लेबाज या गेंदबाज के रूप में लय हासिल करने से जुड़ा है।

उन्होंने कहा कि यह चुनौतीपूर्ण नहीं है। जब आप लय में होते हो तो इसे बरकरार रखना होता है और अपने ऊपर विश्वास रखना होता है। मुझे हैडिंग्ले में खेलने में कोई समस्या नजर नहीं आती। रहाणे ने कहा कि यह सब दिमाग में होता है और हम मानसिक रूप से मजबूत हैं। सभी खिलाड़ी अच्छी स्थिति में हैं।

मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने गेंद के अलावा बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन करते हुए नौवें विकेट के लिए उस समय 89 रन की अटूट साझेदारी की जब भारत 209 रन पर आठ विकेट गंवा चुका था। इस साझेदारी ने मैच को इंग्लैंड की जद से बाहर कर दिया।

यह पूछने पर कि क्या पुछल्ले बल्लेबाजों की बल्लेबाजी से विरोधी टीम के सलामी बल्लेबाजों पर असर पड़ा, रहाणे ने कहा कि इसका बल्लेबाजों पर असर पड़ता है। सात या आठ विकेट गिरने के बाद वे अपनी बल्लेबाजी के बारे में सोचने लगते हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने स्लिप में आभासी बल्लेबाजी का अभ्यास शुरू कर दिया था, उन्होंने वार्मअप और फुटवर्क भी शुरू कर दिया था। रहाणे ने साथ ही कहा कि शारदुल ठाकुर फिट हैं। उन्होंने कहा कि वह चयन के लिए तैयार हैं। हमें सिर्फ यह देखना होगा कि हम किसी संयोजन के साथ उतरते हैं। रोटेशन के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि हमें पिछले टेस्ट के बाद अच्छा ब्रेक मिला है इसलिए सभी तेज गेंदबाज खेलने के लिए तैयार हैं जो अच्छा संकेत है।

कंधे में दर्द के कारण वुड तीसरे टेस्ट से बाहर

लीड्स। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड कंधे की चोट के कारण भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट से बाहर हो गए जिससे पहले से परेशानी का सामना कर रही मेजबान टीम को एक और झटका लगा। लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट में क्षेत्ररक्षण के दौरान वुड के कंधे में चोट लग गई थी। भारतीय टीम ने इस मैच को 151 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त कायम कर ली है। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) से जारी बयान के मुताबिक, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड दाहिने कंधे में दर्द के कारण भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि वुड लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट के चौथे दिन चोटिल हो गए और बुधवार से एमराल्ड हेडिंग्ले में खेलने के लिए फिट नहीं होंगे। वह लीड्स में टीम के साथ बने रहेंगे। वह इंग्लैंड की चिकित्सा टीम की निगरानी में अपना रिहैबिलिटेशन जारी रखेंगे। इस 31 वर्षीय खिलाड़ी की फिटनेस का आकलन टेस्ट मैच के आखिर में किया जाएगा। चोटिल सीनियर तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड पहले ही श्रृंखला से बाहर हो चुके हैं। टीम में तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर भी चोटिल हैं, जबकि हरफनमौला बेन स्टोक्स ने मानसिक कारणों से खेल से अनिश्चितकालीन ब्रेक लिया है।

भारतीय पैरा खिलाड़ियों की नजरें अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर

- टोक्यो पैरालंपिक खेल आज से
- भारत का 54 सदस्यीय दल भाग लेगा

भाषा । टोक्यो

ओलंपिक में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद भारत की नजरें मंगलवार से यहां शुरू हो रहे पैरालंपिक खेलों में भी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर टिकी हैं और उम्मीद है कि 54 खिलाड़ियों का दल देश को इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पहली बार दोहरे अंक में पदक दिला सकता है।

रियो 2016 पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता स्टार भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झझारिया और ऊंची कूद के स्टार मरियप्पन थंगावेलू भारत के अब तक के सबसे बड़े दल की अगुआई करेंगे।

भारत को इन खेलों में पांच स्वर्ण पदक सहित कम से कम 15 पदक की उम्मीद है। कोविड-19 महामारी के कारण पैरालंपिक का आयोजन कड़े सुरक्षा और स्वास्थ्य नियमों के बीच हो रहा है। भारत पैरालंपिक में नौ खेलों में हिस्सा लेगा। महामारी के कारण कुछ देशों ने हालांकि पैरालंपिक से हटने का फैसला किया। भारतीय खिलाड़ियों से अभूतपूर्व सफलता की उम्मीद करना बेमानी नहीं होगा, क्योंकि विश्व रैंकिंग में कम से कम चार भारतीय नंबर एक पर काबिज हैं जबकि छह खिलाड़ियों की विश्व रैंकिंग दूसरी है। इसके अलावा लगभग 10 खिलाड़ियों की विश्व रैंकिंग तीन है।

भारत ने 1972 में पहली बार पैरालंपिक में हिस्सा लिया था और तब से इन खेलों में कुल 12 पदक जीत चुका है। अगर भारत उम्मीद के मुताबिक सफलता हासिल करता है तो इस बार पदक तालिका में शीर्ष 25 में जगह बना सकता है। भारत 2016 रियो पैरालंपिक में दो स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक के साथ 43वें स्थान पर रहा था। सरकार ने पैरा खिलाड़ियों को भरपूर सुविधाएं दी हैं और कई खिलाड़ी देश के विभिन्न हिस्सों में भारतीय खेल प्राधिकरण की सुविधाओं में अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि पैरा खिलाड़ी आठ अगस्त को संपन्न हुए ओलंपिक की सफलता को आगे बढ़ा पाएंगे। भारत ने ओलंपिक में एक स्वर्ण और दो रजत सहित कुल सात पदक जीते थे।

बचपन में करंट लगने के कारण अपना बायां हाथ गंवाने वाले झझारिया 40 साल की उम्र में स्वर्ण पदक की हैट्रिक के मजबूत दावेदार हैं। वह एफ-46 वर्ग में 2004 और

टोक्यो पैरालंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे: दीपा

नई दिल्ली। भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) की प्रमुख दीपा मलिक को उम्मीद है कि देश के पैरा खिलाड़ी मंगलवार से शुरू हो रहे टोक्यो खेलों में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचेंगे। भारत इन खेलों में अपना अब तक का सबसे बड़ा दल उतार रहा है। देश के 54 खिलाड़ी नौ खेलों में चुनौती पेश करेंगे, जिसमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कैनोइंग, निशानेबाजी, तैराकी, पावरलिफ्टिंग, टेबल टेनिस और ताइक्वांडो शामिल हैं। यह पूछने पर कि क्या उन्हें अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद है, दीपा ने कहा, बेशक, मुझे बहुत अधिक उम्मीदें हैं। इस साल भारत अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इतिहास रचेंगे। उन्होंने कहा कि यह दल पिछले दल से तीन गुना बड़ा है, 2016-2020 के बीच चार से पांच साल में हमने चार और खेलों में क्वालीफाई किया है। मलिक ने वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि महामारी के कारण दो साल प्रभावित हुए लेकिन इसके बावजूद क्वालीफाई करने वाले खिलाड़ियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है।

चोटिल बजरंग विश्व चैंपियनशिप से बाहर

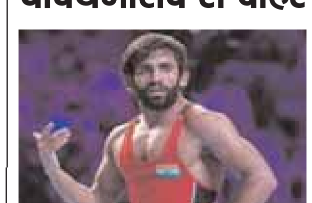

भाषा । नई दिल्ली

ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया आगामी कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि टोक्यो खेलों से पहले दाएं घुटने में लगी चोट (लिगामेंट टियर) के उपचार के लिए उन्हें छह हफ्ते के रिहैबिलिटेशन की सलाह दी गई है। विश्व चैंपियनशिप का आयोजन नॉर्वे के ओस्लो में दो से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा और रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम पूरा होने तक बजरंग ट्रेनिंग शुरू नहीं कर पाएंगे। ओलंपिक से पहले जून में रूस में लगी चोट की गंभीरता को जानने के लिए हाल में बजरंग ने एमआरआई कराया था और मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के खेल मेडिसिन केंद्र के प्रमुख डॉ. दिनशॉ परदीवाला से सलाह ली थी। बजरंग ने बताया कि लिगामेंट में चोट है और डॉ. दिनशॉ ने मुझे छह हफ्ते के रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम से गुजरने को कहा है। मैं विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा।

शैली सिंह मेरा रिकार्ड तोड़ती है तो खुशी होगी: अंजू बॉबी

भाषा । नई दिल्ली

अंजू बॉबी जार्ज ने जब पहली बार शैली सिंह को देखा तो वह छोटी, दुबली पतली लड़की थी जो अपने साथ की शीर्ष तीन एथलीटों में भी शामिल नहीं थी लेकिन लंबी कूद की इस प्रसिद्ध एथलीट ने उसे कोचिंग देना का फैसला किया क्योंकि उन्हें उसमें अपने जैसी खिलाड़ी नजर आई जो कभी हार नहीं मानती।

उस समय शैली 13 साल की थी और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लंबी कूद में पांचवें स्थान पर रही थी। अब वह 17 साल की है उन्होंने अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर बड़े मंच पर अपनी जीवंत उपस्थिति दर्ज करा दी है। वह रविवार को नैरोबी में महिलाओं की लंबी कूद में मात्र एक सेंटीमीटर के अंतर से स्वर्ण पदक से चूक गई थी। झांसी में जन्मी शैली को उनकी मां ने पाल पोसकर बड़ा किया। वह ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा और 400 मीटर की धाविका हिमा दास की श्रेणी में शामिल होने से चूक गई जिन्होंने इस प्रतियोगिता में क्रमश: 2016 और 2018 में स्वर्ण पदक जीते थे। शैली को हालांकि भारतीय एथलेटिक्स का अगला बड़ा सितारा माना जा रहा है। अंजू ने कहा कि निश्चित तौर पर उसका शरीर और मांसपेशियां लंबी कूद के अनुकूल हैं और जब मैंने उसका दृढ़ संकल्प देखा तो मुझे लग गया था कि वह लंबी राह तय करेगी।

विश्व चैंपियनशिप 2003 में कांस्य पदक जीतने वाली अंजू ने कहा कि बाद में मैंने पाया कि वह बहुत जल्दी सीखती है। हमेशा सुधार का प्रयास करती है और कभी हार नहीं मानती। संक्षेप में कहूं तो वह काफी हद तक मेरे जैसे है।

गौरव सैनी एशियाई जूनियर मुक्केबाजी के फाइनल में

भाषा । नई दिल्ली

गौरव सैनी (70 किग्रा) ने दुबई में चल रही एशियाई जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है जबकि तीन अन्य भारतीय मुक्केबाज सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रहे।

सैनी ने किर्गीस्तान के जाकिरोव मुखामादाजीज को रविवार की रात को हुए मुकाबले में 4-1 से हराया। यह प्रतियोगिता पहली बार युवा और जूनियर मुक्केबाजों (पुरुष और महिला वर्ग दोनों में) के लिए एक साथ आयोजित की जा रही है। सैनी के अलावा आशीष (54 किग्रा), अंशुल (57 किग्रा) और भरत जून (81 किग्रा से अधिक) ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आशीष ने ताजिकिस्तान के रहमनोव जाफर को 5-0 से शिकस्त दी जबकि अंशुल ने मंसूर खालिद को हराया।

लेवांटे ने रीयल मैड्रिड को बराबरी पर रोका

स्पेनिश फुटबॉल लीग

एपी । मैड्रिड

मौजूदा चैंपियन एटलेटिको मैड्रिड ने अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हुए स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा में एल्ची को 1-0 से हराया लेकिन रीयल मैड्रिड को लेवांटे से 3-3 गोल से ड्रा खेलना पड़ा। लेवांटे को लगभग आखिरी 10 मिनट अपने मुख्य गोलकीपर के बिना खेलने पड़े, लेकिन उसने रीयल मैड्रिड को इसका फायदा नहीं उठाने दिया।

दूसरी तरफ एटलेटिको इस सत्र में अपने पहले दोनों मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई। लेवांटे के गोलकीपर आइतोर फर्नांडिस को 87वें मिनट में लाल कार्ड दिखाया गया। उनकी जगह डिफेंडर रूबेन वेजो ने गोलकीपर की भूमिका निभाई क्योंकि उनकी टीम पहले ही पांच स्थानापन्न खिलाड़ियों को उतार चुकी थी। रीयल मैड्रिड की तरफ से गेरेथ बेल ने पांचवें मिनट में पहला गोल किया लेकिन मध्यांतर के बाद दो अवसरों पर वह पीछे चल रहा था। ऐसे में विनीसियस जूनियर ने 73वें और 85वें मिनट में गोल करके टीम को एक अंक दिलाया। लेवांटे की तरफ से रोजर मार्टी (46वें), जोस कंपाना (57वें) और रोबर पियरे (79वें मिनट) ने गोल किए। लुई सुआरेज की अनुपस्थिति में एंजेल कोरिया ने फिर से एटलेटिको की जीत में अहम भूमिका निभाई। कोरिया ने पहले हाफ में गोल दागा जो आखिर में निर्णायक साबित हुआ। यह उनका दो मैचों में तीसरा गोल है।

चेल्सी और टोटैनहैम जीते

लंदन। दुनिया के दो सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकरों रोमेलु लुकाकु और हैरी केन ने कुछ समय तक बाहर रहने के बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में फिर से वापसी की। लुकाकु अपना प्रभाव छोड़ने में भी सफल रहे। बेल्जियम के इस अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ने दो साल बाद ईपीएल के शीर्ष डिवीजन में वापसी की है। उन्होंने 15वें मिनट में ही गोल दागा जिससे चेल्सी ने आर्सनल को 2-0 गोल से हराया। चेल्सी की तरफ से दूसरा गोल रीस जेम्स ने 35वें मिनट में किया। टोटैनहैम के स्ट्राइकर केन पिछले सत्र के आखिरी दिन के बाद प्रीमियर लीग में नहीं दिखे थे। उनकी मैनचेस्टर सिटी से जुड़ने की खबरें थी लेकिन वह टोटैनहैम में ही बने रहे। इंग्लैंड के कप्तान केन को वॉलवरहैम्पटन के खिलाफ 71वें मिनट में स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में उतारा गया और उन्होंने गोल करने का आसान मौका भी गंवाया। टोटैनहैम हालांकि डेली अल्ली के नौवें मिनट में पेनल्टी पर किए गए गोल से यह मैच 1-0 से जीता।

एक अन्य मैच में मैनचेस्टर यूनाईटेड को साउथम्पटन के खिलाफ 1-1 से ड्रा खेलना पड़ा। फ्रेड के आत्मघाती गोल से साउथम्पटन ने 30वें मिनट में बढ़त बना दी थी। मैसन ग्रीनवुड ने 55वें मिनटमें यूनाईटेड को बराबरी दिलाई।

डूरंड कप पांच सितंबर से, 16 टीमें लेंगी भाग

कोलकाता। इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) की पांच और आई-लीग की तीन फ्रेंचाइजी टीमें प्रतिष्ठित डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने वाली 16 टीमों में शामिल है जिसका आयोजन यहां पांच सितंबर से तीन अक्टूबर तक किया जाएगा।

कई वर्षों तक दिल्ली में आयोजित होने वाला यह टूर्नामेंट 2019 में कोलकाता में खेला गया था। अब इसके 130वें सत्र का आयोजन भी इसी शहर में होगा। भारतीय सेना द्वारा पारंपरिक रूप से आयोजित होने वाली यह प्रतियोगिता दुनिया की तीसरा सबसे पुरानी और एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। इस साल भी टूर्नामेंट की मेजबानी पश्चिम बंगाल सरकार संयुक्त रूप से कर रही है। एफसी गोवा और बेंगलुरु एफसी जैसी आईएसएल (शीर्ष घरेलू लीग) की शीर्ष टीमों के अलावा केरल ब्लास्टर्स, जमशेदपुर एफसी और हैदराबाद एफसी इस टूर्नामेंट का हिस्सा होंगे।

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the General Public that Mrs. Geeta Grewal is the owner and in possession of Entire First Floor without roof rights built on Property bearing No.432, Block-B-1, (commonalty known as B-1/432), measuring 133 sq. yds., situated at Janakpuri, New Delhi " Said Property" by virtue of Sale Deed dated 08.07.2021 duly regd. as Doc. No. 12158, Book No.1, Vol. No. 6391, page 66-74, on 08.07.2021, All persons are hereby informed that above mentioned owner intend to take loan from our client i.e. IDFC FIRST BANK LIMITED by mortgaging the said property to our client, if anybody has any objection/s upon said property /its ownership & Title/ its Sale and Mortgage, kindly inform the undersigned in writing on the below mentioned address within 10 days of the present.

Kumar & Associates (Advocates & Consultants)
200, IInd Floor, 23, Shivaji Marg, Moti Nagar, N. Delhi-15
Ph : 011-41112527-28 kumarassociates.advocate@gmail.com

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my clients Mrs. JASVINDER KAUR W/o Sh. Kashmir Singh and her husband Sh. KASHMIR SINGH R/o 3072/Q-17, Gali No.10, Ranjit Nagar, New Delhi have debarred and disowned their son GURSIMRAN SINGH from their family and all moveable and immoveable properties, because of his irresponsible conduct, misbehave and quarelling nature. Now my above named clients and their family would have no concern with their above named son in any manner and they do not want to allow him to reside in their home. If any person deals with the said Gursimran Singh any way, he/she would do so at his own risk and my clients Mr. Jasvinder Kaur and Kashmir Singh will not be responsible for his any act or liabilty.

(SHAILESH GUPTA) Advocate
4/30, West Patel Nagar, New Delhi-110008

Public Notice

It is hereby informed to the general public that I, Meena Aggarwal D/o Ram Murti Devi R/o X-051 DLF Capital Greens, Moti Nagar, New Delhi-110015, have lost the Original Provisional Allotment Letter and Original Payment Receipts issued by Jaiprakash Associates Limited in respect of Unit bearing No. PCH00H0117 in County Homes-1 project, situated at Jaypee Greens Sports City on 19.6.2019. Anyone finding the said documents is requested to kindly return the same to me or to the company.
Name: Meena Aggarwal,
Address: X-051, DLF Capital Greens, Moti Nagar, New Delhi-110015,
Phone No. 9810501072,
Email: a_ankur@hotmail.com

PUBLIC NOTICE

Know all men through these present that my client Sh.Sandeep Dewan S/o Late Sh. N.K. Dewan R/o D-69, Ground Floor, Panchsheel Enclave, New Delhi-110017 is desirous of purchasing the front terrace of property bearing no. D-69, Panchsheel Enclave, New Delhi from Sh.Vikramjeet Singh s/o Late Major General Ram Singh through his attorney Sh.Kapil Dev S/o Late Sh.Kasturi Lal R/o D-42, South Extension-II, New Delhi appointed vide General Power of Attorney dated 29.11.1996 duly registered as document no. 17756 in Addl. Book No. IV, Volume No.856, on pages 178 to 179, on 29.11.1996, in the office of the sub-registrar, New Delhi.
Any person(s) having any objection in respect of the above stated property or part thereof by way of sale/purchase, exchange, mortgage, charge, gift, maintenance, inheritance, possession, lease, tenancy, sub-tenancy, lien, license, hypothecation, transfer of title or beneficial interest under any trust right of prescription or pre-emptioner under any Agreement or other disposition or under any decree, order or whatsoever may contact the undersigned within 15 days from the publishing of this notice.

GAURAV BHARDWAJ (Advocate)
B-16, Lower Ground Floor, Panchsheel Enclave, New Delhi-110017

PREM NATH CREDIT & INVESTMENTS CORPORATION LIMITED
CIN U65993DL1994PLC057025
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT (REGIONAL DIRECTOR)
NORTHERN REGION, NEW DELHI
In the matter of the Companies Act, 2013, Section 14 of Companies Act, 2013 and rule 41(5)(a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
In the matter of Prem Nath Credit & Investments Corporation Limited having Registered Office at 8A /12 Ground Floor W.E.A. Karol Bagh, New Delhi 110 005

NOTICE

Notice is hereby given to the General Public that the Company intending to make an application to the Central Government (Power delegated to Regional Director), Northern Region, New Delhi, under Section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid Rule and is desirous of converting into Private limited Company in terms of Special Resolution passed at the 01/2021-22 Extra Ordinary General Meeting of the Company held on August 12, 2021 to enable the Company to give effect to such conversion.
Any person whose interest is likely to be effected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections stating the nature of his interest and grounds of opposition to the concerned Regional Director, Northern Region, New Delhi at B-2 wing, 2nd floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi – 110 003 within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its registered office situated at 8A /12 GROUND FLOOR W.E.A. KAROL BAGH, NEW DELHI-110 005.

For and on behalf of the Applicant
Sd/-
Rakesh Kumar Anand
Director
DIN 01177103
Date: August 22, 2021
Place: New Delhi

बिक्री सूचना

निम्नलिखित आस्ति अधोवर्णित मामले में, न्यायालय के आदेशों के अनुसार, बकाया राशि की वसूली के लिए "जैसा है जहां है आधार" तथा "जैसा है जो है आधार" पर नीलामी के माध्यम से बेची जाएगी :-

वाद विवरण	आस्ति विवरण	सुरक्षित मूल्य	ईएमडी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाम आशुतोष वशिष्ठ वाद सं. - सीएस (सीओएमएम) सं. 613/19	वाहन नंबर - यूपी14डीएच3223, मेक तथा माडल - ह्युंडई मोटर्स लिमिटेड आई10 मैग्ना, 1.1 विनिर्माण वर्ष - 2017	2,60,000/-	26,000/-

नीलामी की तिथि एवं समय : 08 सितम्बर, 2021 पूर्वा. 11 बजे से अप. 2 बजे तक
नीलामी का स्थान : https://auctions.cardekho.com/
ईएमडी : ईएमडी राशि का डीडी/पीओ आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के पक्ष में दिल्ली में देय बनाया जाना है।
प्रबंधक :- श्री अविनाश श्रीवास्तव (8953652366)/श्री जितेन्द्र कुमार (73049 14763)

बिक्री की शर्तें

उक्त आस्ति का यहां ऊपर विनिर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार वर्णित किया गया है, जो तथापि, उक्त विवरण में किसी त्रुटि, मिथ्याकथन अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। अतएव इच्छुक प्रतिभागी/प्रतिभागियों से उनके अपने हित में अनुरोध है कि वे बोली देने से पहले उक्त आस्ति और उससे संबंधित अन्य विवरण के बारे में अपनी संतुष्टि कर लें। सभी बोलीदाताओं को ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने हेतु ईएमडी राशि का मूल डीडी/पीओ स्व-सत्यापित केवाईसी प्रमाणों के साथ 6 सितम्बर, 2021 को अथवा पहले जमा करना होगा।

इच्छुक बोलीदाता उक्त दृष्टिबंधित वाहन के विस्तृत विवरण तथा निरीक्षण के लिए हमें कॉल कर सकते हैं।

बिक्री सूचना

निम्नलिखित आस्ति अधोवर्णित मामले में, न्यायालय के आदेशों के अनुसार, बकाया राशि की वसूली के लिए "जैसा है जहां है आधार" तथा "जैसा है जो है आधार" पर नीलामी के माध्यम से बेची जाएगी :-

वाद विवरण	आस्ति विवरण	सुरक्षित मूल्य	ईएमडी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाम मुनीर खान वाद सं. - 229/2020	वाहन नंबर - यूपी16एएच0220, मेक तथा माडल - फोर्ड इंडिया लिमिटेड, इन्डेवलर एक्सएलटी, विनिर्माण वर्ष - 2011	1,00,000/-	10,000/-

नीलामी की तिथि एवं समय : 08 सितम्बर, 2021 (11AM से 2PM)
नीलामी का स्थान : जेसीएस फाइनैंशियल सर्विसेज ऐंड पार्किंग सिक्योरिटी, प्लॉट नंबर 112, ओल्ड रायपुर रोड, पाकरी, निकट किशन नगर, कानपुर नगर, पिन 209304, उत्तर प्रदेश
सम्पर्क व्यक्ति :- श्री अविनाश श्रीवास्तव (8953652366)/श्री जितेन्द्र कुमार (73049 14763)
ईएमडी : ईएमडी राशि का डीडी/पीओ आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के पक्ष में दिल्ली में देय बनाया जाना है।

वाद विवरण	आस्ति विवरण	सुरक्षित मूल्य	ईएमडी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाम राहुल यादव वाद सं. - 222/2020	वाहन नंबर - यूपी14ईटी0642, मेक तथा माडल - टाटा एस, विनिर्माण वर्ष - 2014	40,000/-	4,000/-

नीलामी की तिथि एवं समय : 08 सितम्बर, 2021 (11AM से 2PM)
नीलामी का स्थान : ए.एन. मोटर्स, 14केएम स्टोन, आगरा-मथुरा रोड, रूनक्ता, आगरा-282007
सम्पर्क व्यक्ति :- श्री विजय शर्मा (9372730494)/श्री जितेन्द्र कुमार (73049 14763)
ईएमडी : ईएमडी राशि का डीडी/पीओ आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के पक्ष में दिल्ली में देय बनाया जाना है।

बिक्री की शर्तें

उक्त आस्ति का यहां ऊपर विनिर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार वर्णित किया गया है, जो तथापि, उक्त विवरण में किसी त्रुटि, मिथ्याकथन अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। अतएव इच्छुक प्रतिभागी/प्रतिभागियों से उनके अपने हित में अनुरोध है कि वे बोली देने से पहले उक्त आस्ति और उससे संबंधित अन्य विवरण के बारे में अपनी संतुष्टि कर लें।
सभी बोलीदाताओं को नीलामी में भाग लेने के लिए ईएमडी राशि के मूल डीडी/पीओ तथा मूल केवाईसी प्रमाणों के साथ साइट पर आना होगा।
सफल अनुमोदित बोलीदाता को बिक्री राशि (ईएमडी राशि घटाकर) पे ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से नीलामी की तिथि से 5 दिन के भीतर जमा करनी होगी। यदि आप शेष राशि 5 दिन के भीतर जमा करने में असफल रहते हैं, तो आपकी ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
इच्छुक बोलीदाता उक्त दृष्टिबंधित वाहन के विस्तृत विवरण तथा निरीक्षण के लिए आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, शाल टावर, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005 पधार सकते हैं।

काबुल हवाईअड्डे पर गोलीबारी में अफगान सैनिक की मौत

● पंजशीर के करीब जमा हुए तालिबान लड़ाके

एपी। काबुल

अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़ने के लिए मची अफरातफरी के बीच काबुल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के एक द्वार के पास सोमवार तड़के गोलीबारी में कम से कम एक अफगान सैनिक की मौत हो गई। जर्मनी के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

हवाईअड्डे पर गोलीबारी के बीच तालिबान ने अपने लड़ाकों को उत्तरी क्षेत्र में भेजा है जहां पर उसे सशस्त्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। तालिबान ने कहा कि उसने तीन जिलों पर फिर से कब्जा कर लिया है जिसे एक दिन पहले उसके विरोधियों ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। इसके साथ ही पंजशीर को भी तालिबानी लड़ाकों ने घेर लिया है। काबुल हवाईअड्डे के एक द्वार के पास गोलीबारी हुई जहां एक दिन पहले भगदड़ में सात लोगों की मौत हो गई थी। किन परिस्थितियों में गोलीबारी हुई यह स्पष्ट नहीं है। जर्मन सेना ने ट्वीट करके बताया कि सोमवार को गोलीबारी में अफगानिस्तान के एक सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए हैं। बाद में जर्मन सेना ने स्पष्ट किया कि वह हवाईअड्डे की सुरक्षा में जुटी अफगान सेना के सदस्यों का हवाला दे रही थी। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने समर्पण कर दिया। तालिबान के कठोर शासन के लौटने के डर से हजारों अफगान नागरिक देश छोड़कर निलकने का प्रयास कर रहे हैं जिससे काबुल हवाई अड्डे पर अफरातफरी मची है। कुछ अफगान सैनिक लोगों को निकालने के अभियान में पश्चिमी देशों के सैनिकों की मदद कर रहे हैं।अफगानिस्तान में अस्पतालों का संचालन करने वाले इतालवी मानवीय सेवा संगठन इमरजेंसी ने कहा कि उसने हवाईअड्डे पर गोलीबारी में घायल हुए छह मरीजों का इलाज किया और किसी की भी स्थिति गंभीर नहीं है। अमेरिकी सेना और नाटो ने गोलीबारी की घटना के बारे में अभी कुछ नहीं कहा है। तालिबान ने भी घटना के बारे में टिप्पणी नहीं की है।तालिबान ने अफरातफरी भरे बचाव अभियान के लिए अमेरिकी सेना को दोष दिया है और कहा है कि अफगान लोगों को उससे डरने की जरूरत नहीं हैं। हालांकि हवाईअड्डे के आसपास एकत्र भीड़ को काबू में करने के लिए तालिबान के लड़ाकों ने हवा में गोली चलाई और लोगों पर लाठियां चलाईं।

काबुल हवाई अड्डे के जांच स्थल पर भीड़ को रोकने का प्रयास करते यूएस मरीन

सोमवार तड़के डेल्टा एयरलाइन का विमान दुबई में उतरा और बाद में कतर में अलउदेद एयरबेस के लिए उड़ान भरी जहां निकाले गए लोगों की भीड़ जमा है। काबुल से लोगों को निकालने के लिए सैन्य विमानों का परिचालन जारी है। अमेरिका ने 14 अगस्त के बाद से सैन्य और अन्य विमानों से 30,000 से ज्यादा लोगों को निकाला है। अब भी हजारों लोग काबुल से निकलने का इंतजार कर रहे हैं जिसमें अमेरिका और दूसरे देशों के लोग तथा अफगान नागरिक हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने रविवार को कहा कि वह लोगों को निकालने के अभियान को 31 अगस्त से आगे बढ़ाने से इनकार नहीं करेंगे। इसी तारीख तक अमेरिकी सैन्य बलों की अफगानिस्तान से पूर्ण वापसी होनी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अभियान को आगे बढ़ाने के लिए बाइडन से आग्रह करेंगे। तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने स्काई न्यूज के साथ साक्षात्कार में कहा कि 31 अगस्त रेड लाइन है और अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी की समय सीमा बढ़ाना उकसावे का कदम होगा।

काबुल हवाईअड्डे पर इस्लामिक स्टेट से संबंधित स्थानीय संगठनों द्वारा हमले का भी खतरा है। इस बीच काबुल से 120 किमी दूर उत्तर में बगलान प्रांत में स्वयं को जन विद्रोह से जुड़ा बताने वाले लड़ाकों ने हिंदुकुश में अंदराब घाटी में तीन जिलों पर कब्जा करने का दावा किया। लेकिन तालिबान ने सोमवार को दावा किया कि उसने इन जिलों पर फिर से कब्जा कर लिया है। तालिबान के प्रवक्ता जबील्ला मुजाहिद ने कहा कि उन्होंने पंजशीर प्रांत को घेरना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से पंजशीर इकलौता ऐसा प्रांत है जहां तालिबान कब्जा नहीं कर सका है। अफगानिस्तान के उप राष्ट्रपति रहे अमरूल्ला सालेह ने ट्विटर पर लिखा कि तालिबान लड़ाके प्रांत के आसपास एकत्रित हो गए हैं। वर्ष 2001 में तालिबान को हटाने के लिए अमेरिका का साथ देने वाले नार्दर्न अलायंस संगठन के दिवंगत कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने कहा कि उसके लड़ाके भी पंजशीर में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ताकत से प्रांत पर कब्जा करने के किसी भी प्रतिरोध का उनके लड़ाके मुकाबला करेंगे लेकिन तालिबान के साथ वार्ता का रास्ता खुला है। तालिबान के प्रवक्ता मुजाहिद ने कहा कि तालिबान की योजना पंजशीर के लोगों से बात करने की है। उन्होंने कहा, अभी तक तो वहां लड़ाई नहीं हो रही। हम पंजशीर के लिए शांतिपूर्ण समाधान खोजना चाहते हैं।

तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान को आर्थिक मदद देने का चीन ने दिया संकेत

● चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, अफगान संकट के लिए अमेरिका मुख्य गुनहगार है, वह ऐसे हाल में छोड़कर नहीं जा सकता

बीजिंग (भाषा)। चीन ने सोमवार को संकेत दिया कि वह तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान को वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा। तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद काबुल को विभिन्न देशों द्वारा वित्तीय मदद रोके जाने के बीच चीन ने कहा कि वह युद्धग्रस्त देश की मदद करने में सकारात्मक भूमिका निभाएगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अफगान संकट के लिए मुख्य गुनहगार है और अमेरिका, अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए कुछ किए बिना ऐसे हाल में छोड़कर नहीं जा सकता। निर्वासन में रह रहे, अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक के प्रमुख ने कहा है कि वित्तीय मदद के लिए अमेरिकी मदद रूकने के कारण तालिबान चीन और पाकिस्तान का रुख करेगा। इस बयान के बारे में पूछे जाने पर वेनबिन ने कहा, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि अफगान मुद्दे के लिए अमेरिका मुख्य गुनहगार और सबसे बड़ा बाह्य कारक है। वह बिना कुछ किए (देश को) गड़बड़ी में धकेलकर इस तरह नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, हमें आशा है कि अमेरिका मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण के अपने वचन को निभाएगा और प्रतिबद्धताओं से मुंह नहीं मोड़ेगा। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर में पिछले सप्ताह कहा गया था कि अफगानिस्तान में अभियान खत्म होने के बावजूद अफगान सेंट्रल बैंक से जुड़े अरबों डॉलर रकम पर अमेरिका का नियंत्रण है। जर्मनी ने भी कहा है कि तालिबान के सत्ता पर काबिज होने और शरिया कानून लागू किए जाने पर वह वित्तीय मदद नहीं देगा। यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने कहा है कि जब तक अधिकारी हालात के बारे में स्पष्टीकरण नहीं देंगे अफगानिस्तान को भुगतान नहीं होगा। वेनबिन ने कहा कि चीन हमेशा सभी अफगान लोगों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाता रहा है और अफगानिस्तान को सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करता रहा है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि देश में अराजकता और जंग का जल्द अंत होगा तथा वह जल्द से जल्द वित्तीय व्यवस्था को फिर से शुरू कर सकता है। चीन क्षमता निर्माण, शांति, पुनर्निर्माण और लोगों की आजीविका स्थिति में सुधार के लिए भी देश की मदद करने में सकारात्मक भूमिका निभाएगा।

अफगानिस्तान से बलों की वापसी का फैसला तार्किक और उचित था: बाइडन

भाषा। वाशिंगटन

अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां पैदा हुए संकट के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने युद्धग्रस्त देश से अपने बलों की वापसी के कदम को सही ठहराते हुए कहा कि इतिहास में यह कदम तार्किक और उचित निर्णय के रूप के दर्ज किया जाएगा।

अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की वापसी के फैसले के कारण बाइडन प्रशासन की आलोचना हो रही है, क्योंकि बलों के लौटने के कारण तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, जिसके कारण देश में अराजकता फैल गई है। बाइडन ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, मुझे लगता है कि इतिहास के पन्नों में इस फैसले को तार्किक और उचित निर्णय के रूप में दर्ज किया जाएगा। इससे पहले, भारतीय मूल की अमेरिकी नेता निकी हेली ने अमेरिका सरकार की निंदा करते हुए कहा कि अमेरिका ने तालिबान के सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया और अफगानिस्तान में अपने सहयोगियों को छोड़ दिया। हेली ने सीबीएस न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा, वे तालिबान से वार्ता नहीं कर रहे। उन्होंने तालिबान के समक्ष पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने बगराम वायुसेना अड्डे को सौंप दिया, जो नाटो का बड़ा केंद्र था। उन्होंने 85 अरब डॉलर के उपकरण और हथियार भी सौंप दिए। उन्होंने कहा, उन्होंने अमेरिकी लोगों का समर्पण कर दिया और उन्होंने अमेरिकी लोगों की वापसी से पहले अमेरिकी बलों को वापस बुला लिया। उन्होंने विदेशों में तैनात मेरे पति जैसे लोगों को सुरक्षित रखने वाले अफगान साथियों को छोड़ दिया। कोई बातचीत नहीं हुई। यह पूरी तरह आत्मसमर्पण था और शर्मनाक नाकामी है। इस बीच, बाइडन ने कहा कि तालिबान को एक मूलभूत फैसला करना होगा। उन्होंने कहा, क्या तालिबान एकजुट होने की कोशिश और अफगान लोगों का कल्याण करेगा, जो किसी समूह ने अभी तक नहीं किया है? बाइडन ने कहा, यदि वह ऐसा करता है, तो उसे आर्थिक सहायता, व्यापार समेत अतिरिक्त मदद चाहिए होगी। उन्होंने कहा, तालिबान ने ऐसा कहा है। हम देखेंगे कि वह वास्तव में ऐसा करता है या नहीं। वे अन्य देशों की मान्यता चाहते हैं। उन्होंने हमें और अन्य देशों से कहा है कि वे नहीं चाहते कि हम अपनी राजनयिक मौजूदगी पूरी तरह समाप्त करें। फिलहाल ए केवल बातें हैं। बाइडन ने कहा कि उनकी प्राथमिकता अफगानिस्तान से जल्द से जल्द और सुरक्षित तरीके से अमेरिकी नागरिकों को बाहर निकालना है।

क्विक न्यूज

ब्रिटेन ने अमेरिका से काबुल से लोगों को निकालने की समयसीमा को आगे बढ़ाने का आग्रह किया

लंदन। ब्रिटेन ने अमेरिका से गुजारिश की है कि वह काबुल से लोगों को निकालने के अभियान की समयसीमा को 31 अगस्त से आगे बढ़ाए क्योंकि बिना अमेरिका के किसी भी देश के पास अफगानिस्तान से भाग रहे लोगों की मदद करने वाले अभियान को रोकने के अलावा कोई विकल्प नही होगा। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन मंगलवार को ब्रिटेन द्वारा बुलाई गई समूह (जी) सात के नेताओं की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन पर दबाव डाल सकते है। ब्रिटेन में कुछ सैन्य अधिकारियों का मानना है कि अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद ब्रिटेन को अपने सैनिकों को काबुल हवाई अड्डे पर तैनात रखना चाहिए ताकि लोगों को निकालने के अभियान को जारी रखा जा सके। सशस्त्र बल मंत्री जेम्स हेप्पी ने सोमवार को कहा कि अमेरिका की मदद के बिना वहां से लोगो को नही निकाला जा सकता है, और यह कठोर वास्तविकता है। उन्होने कहा कि अमेरिका को अफगानिस्तान में रुकने के लिए राजी किया जा सकता है या नही, इस पर जी-7 की बैठक में प्रधानमंत्री बात करेंगे। उन्होने यह भी कहा कि तालिबान के साथ समझौते को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। बाइडन ने लोगों को हवाई मार्ग से निकालने के अभियान को 31 अगस्त की तारीख से बढ़ाने से इनकार नही किया है, लेकिन उम्मीद जताई है कि ऐसा करने की जरूरत नही पड़ेगी। गौरतलब है कि 31 अगस्त तक अमेरिका अपने सभी सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लेगा, जहां अब तालिबान ने कब्जा कर लिया है।

अफगानिस्तान में सूखे और सर्दी के आगमन के चलते मानवीय स्थिति बदतर होगी: यूनिसेफ

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की बच्चों से संबंधित एजेंसी यूनिसेफ ने आशंका जताई है कि अफगानिस्तान में भीषण सूखे, सर्दी के आगमन और कोरोना वायरस महामारी के चलते मानवीय स्थिति बदतर हो सकती है। यूनिसेफ ने कहा कि अफगानिस्तान मे पहले ही एक करोड़ बच्चे मानवीय सहायता पर निर्भर है और इस साल लगभग 10 लाख बच्चों के जानलेवा कुपोषण से ग्रस्त होने की आशंका है। लगभग 42 लाख बच्चे स्कूल छोड़ चुके है, जिनमें 22 लाख लड़कियां है। अफगानिस्तान एक गरीब देश है, जो अंतरराष्ट्रीय मदद पर निर्भर है। वहां इस महीने की शुरुआत मे तालिबान के नियंत्रण से पहले भी यही स्थिति थी। यूनिसेफ की निदेशक हेनरिटा फोर ने सोमवार को एक बयान में कहा कि यह एक चिंताजनक वास्तविकता है,जिसका अफगान बच्चे सामना कर रहे है और मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम व सरकार मे बदलाव से परे, यह वास्तविकता ऐसी ही रहेगी। उन्होने कहा कि एजेंसी अफगानिस्तान मे अपनी मौजूदगी को लेकर प्रतिबद्ध है और अपने अभियानों को बढ़ा रही है। यूनिसेफ उन इलाकों में मदद पहुंचाने की उम्मीद करता है, जहां मौजूदा युद्ध के कारण पहुंचना मुश्किल है।

दक्षिणपूर्व एशिया एवं हिंद प्रशांत क्षेत्र दुनिया का भविष्य तय करेंगे: कमला हैरिस

सिंगापुर। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग के साथ मुलाकात के बाद अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सोमवार को कहा कि उनका मानना है कि दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र दुनिया का भविष्य तय करेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अमेरिका की साझेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से वह इस क्षेत्र की यात्रा पर है। ली के साथ यहां संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में हैरिस ने कहा कि अमेरिका ने सिंगापर एवं दक्षिणपूर्व एशिया के साथ जो समझौते किए है वह दुनियाभर मे उसकी ताकत एवं स्थाई संबंधो का सबूत है। उन्होने कहा कि ए केवल ऐसी प्राथमिकताएं नही है जिनका संबंध अमेरिका की सुरक्षा एवं आर्थिक हितो से है बल्कि उनका संबंध उन चुनौतियों से है जिनसे दुनिया जूझ रही है जैसे भावी महामारियां और ऐसे में इन देशों के साथ मिलकर अनुसंधान करने एवं उन्हें (महामारियो को) रोकने के लिए क्या कर सकते है। हैरिस ने कहा, यह एक ऐसा संबंध है जो, हमारे सामने जो चुनौतियां और मौके है, उन दोनों के संदर्भ मे साझे दृष्टिकोण पर आधारित है... यह हमारी परस्पर प्रतिबद्धता, जिज्ञासा और दिलचस्पी के संबंध में भविष्य को लेकर है। उपराष्ट्रपति रविवार को यहां पहुंची और सिंगापुर के राष्ट्रपति महल इस्ताना मे आज उनका औपचारिक स्वागत किया गया। हैरिस की सिंगापुर यात्रा दक्षिण पूर्व एशिया में बाइडन प्रशासन की आक्रामक कूटनीति का हिस्सा है क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जो इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामक कार्वाई के बीच अमेरिका की भावी समृद्धि एवं सुरक्षा के लिए अहम है।

उम्मीद है कि अफगानिस्तान फिर से आतंकवाद का केंद्र नहीं बनेगा: लूंग

सिंगापुर। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने सोमवार को कहा कि अफगानिस्तान आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण युद्धक्षेत्र है और उम्मीद जताई कि तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद देश आतंकवाद का केंद्र नही बनेगा। लूंग ने यहां अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 20 साल पहले इस क्षेत्र मे अमेरिका के हस्तक्षेप ने आतंकवादी समूहो को अफगानिस्तान को सुरक्षित ठिकाने के रूप मे इस्तेमाल करने से रोक दिया है। उन्होंने कहा, इसके लिए सिंगापुर आभारी है। हमें उम्मीद है कि अफगानिस्तान फिर से आतंकवाद का केंद्र नही बनेगा।

वावेरली में भारी बारिश के बाद बह गई कार एक जगह कुछ इस तरह से अटकी हुई

तालिबान ने टीटीपी को अपनी भूमि का उपयोग नहीं करने देने का आश्वासन दिया : पाकिस्तान

भाषा। इस्लामाबाद

शेख राशिद अहमद ने सोमवार को कहा कि अफगान तालिबान ने सरकार को आश्वासन दिया है कि वह उसके खिलाफ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकवादियों को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा। उनका यह बयान उन खबरों के बीच आया है जिनमें कहा गया है कि तालिबान का काबुल पर कब्जा होने के बाद अफगानिस्तान में कई कट्टर टीटीपी आतंकवादियों को छोड़ा गया है।टीटीपी को आमतौर पर पाकिस्तानी तालिबान के रूप में जाना जाता है और अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा के पास स्थित यह प्रतिबंधित आतंकवादी समूह है। उसने पाकिस्तान में कई बड़े आतंकी हमले किए हैं और आरोप है कि वह ऐसे आतंकवादी हमलों के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करता रहा है।अहमद ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने उन खबरों पर गौर किया है कि अफगान तालिबान ने कुछ टीटीपी आतंकवादियों को रिहा कर दिया है जिसमें उसका प्रमुख कमांडर मौलवी फकीर मोहम्मद शामिल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मुद्दे पर तालिबान के साथ पूर्ण संपर्क में है।उन्होंने कहा, "संबंधित (अफगान) अधिकारियों से कहा गया है कि वे ऐसे लोगों को नियंत्रित करें जो पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहे हैं। अफगान तालिबान ने (हमें) आश्वासन दिया है कि टीटीपी द्वारा किसी भी स्थिति में अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनकी टिप्पणी उस मीडिया रिपोर्ट के बीच आई है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने टीटीपी से जुड़े" सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों की एक सूची अफगान तालिबान को सौंपी है, जो अब भी अफगानिस्तान में सक्रिय हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार, हाल ही में काबुल पर नियंत्रण करने के बाद अफगान तालिबान नेतृत्व को यह सूची सौंपी गई।

अफगानिस्तान से ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकता अमेरिका : चीन

बीजिंग। अफगानिस्तान को लेकर चीन ने एक बार भी अमेरिका की कटु आलोचना करते हुए कहा कि वह युद्ध से जर्जर देश से इस तरह मुंह नहीं मोड़ सकता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने सोमवार को कहा, अमेरिका इस सबकी जड़ है और अफगानिस्तान मामले में सबसे बड़ा बाहरी कारक है। उन्होंने कहा, वह ऐसे (अपनी जिम्मेदारियों से) नहीं भाग सकता। उन्होंने अमेरिका से स्थिरता बनाए रखने, अफरा-तफरी मचने से रोकने और अफगानिस्तान के पुन:निर्माण में मदद करने को कहा। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा, मैं आशा करता हूं कि अमेरिका अपनी कथनी करनी में फर्क नहीं करेगा, अफगानिस्तान पर अपनी जिम्मेदारी समझेगा और विकास, पुन:निर्माण तथा मानवीय सहायता के संदर्भ में अफगानिस्तान के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को निभाएगा।

बाइडन के विशेष दूत ने उत्तर कोरिया से वार्ता पुनः आरंभ करने की इच्छा जताई

एपी। सियोल

उत्तर कोरिया के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के विशेष दूत सुंग किम ने सोमवार को कहा कि वह अपने उत्तर कोरियाई समकक्ष के साथ कहीं भी और किसी भी समय वार्ता के लिए तैयार है।किम ने उत्तर कोरिया के साथ रुकी हुई परमाणु वार्ता को लेकर दक्षिण कोरिया के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान यह बात कही। किम ऐसे समय पर दक्षिण कोरिया आए हैं, जब उत्तर कोरिया के साथ वार्ता जल्द बहाल होने की उम्मीद कम हो रही है और अमेरिका एवं दक्षिण कोरिया के बीच जारी सैन्य अभ्यास के कारण तनाव पैदा हो गया है। उत्तर कोरिया ने इस सैन्य अभ्यास को आक्रमण का अभ्यास बताया है और जवाबी कार्वाई की धमकी दी है।दक्षिण कोरिया के वरिष्ठ राजनयिक नोह क्यू-डुक के साथ बैठक के बाद किम ने दोहराया कि बाइडन का उत्तर कोरिया के खिलाफ कोई शत्रुतापूर्ण इरादा नहीं है और संयुक्त अभ्यास नियमित एवं रक्षात्मक प्रकृति का है। किम और नोह ने संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने वायरस रोधी संसाधनों, स्वच्छता और स्वच्छ जल मुहैया कराने में उत्तर कोरिया के साथ मानवीय सहयोग करने समेत कूटनीति के संभावित तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने किसी विशेष योजना की घोषणा नहीं की। किम रूस के उप विदेश मंत्री इगोर मोरगुलोव से भी मुलाकात करेंगे। मोरगुलोव भी इस समय सियोल में हैं। किम ने कहा, मैं अपने उत्तर कोरियाई समकक्ष के साथ कहीं भी और किसी भी समय मिलने के लिए तैयार हूं। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच वार्ता उस समय बाधित हो गई थी, जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच 2019 में शिखर वार्ता हुई थी। शिखर वार्ता में अमेरिका ने उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमताओं में आंशिक कमी के बदले व्यापक स्तर पर आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाने की उसकी मांग खारिज कर दी थी।

हमास के साथ तनाव के मद्देनजर मिस्र ने बंद की गाजा की ओर जाने वाली सीमा

एपी। काहिरा

मिस्र ने उग्रवादी संगठन हमास के साथ तनाव के मद्देनजर गाजा पट्टी की ओर जाने वाली अपनी मुख्य सीमा को बंद कर दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस साल की शुरुआत से ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी कार्यदिवस के दौरान राफा क्रॉसिंग को बंद किया गया हो। मिस्र ने मई में इजराइल और हमास के बीच 11 दिनों तक चले युद्ध के दौरान इस सीमा को खुला रखा था। मिस्र के अधिकारियों के अनुसार, गाजा पट्टी की ओर जाने वाली सीमा को बंद करना इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम लागू कराने के काहिरा के प्रयासों का ही एक हिस्सा है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह सीमा कब तक बंद रहेगी। मिस्र के एक अधिकारी ने कहा कि गाजा की ओर जाने वाली सीमा को बंद करने का उद्देश्य हमास पर दबाव बनाना है। इजराइल के साथ जारी हमास की अप्रत्यक्ष बातचीत के सही दिशा में आगे नहीं बढ़ने से मिस्र नाराज है। इसके अलावा फलस्तीनी गुटों से बातचीत करने की भी कोशिश की जा रही है। इजराइल-मिस्र की नाकेबंदी के मद्देनजर हमास ने शनिवार को एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया, जिसके दौरान हिंसा भड़क उठी। बड़ी संख्या में फलस्तीनी नागरिकों ने इजराइल की सीमा के नजदीक पहुंचकर प्रदर्शन किया। इजराइली सैनिकों की ओर से की गई गोलीबारी में कम से कम 24 फलस्तीनी नागरिक घायल हो गए, जिसमें से दो की हालत गंभीर बनी हुई है। गौरतलब है कि मिस्र कई वर्षों से इजराइल और हमास के बीच एक प्रमुख मध्यस्थ रहा है। मिस्र के खुफिया विभाग के प्रमुख अब्बास कामेल ने इजराइली प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट के साथ संघर्ष विराम समझौते पर चर्चा करने के लिए पिछले सप्ताह ही इजराइल का दौरा किया था।

सीरिया, इराक में लाखों लोगों के सामने जल संकट: सहायता समूह

बेरूत। अंतरराष्ट्रीय सहायता समूहों ने सोमवार को चेतावनी दी कि बढ़ते तापमान, बारिश की कमी और सूखे के कारण जल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बीच सीरिया और इराक में लाखों लोग पानी, बिजली और भोजन तक पहुंच समाप्त होने के खतरे का सामना कर रहे हैं। समूहों ने कहा कि वर्षों के संघर्ष और कुप्रबंधन से जूझ रहे दोनों पड़ोसी देशों को पानी की गंभीर कमी से निपटने के लिए त्वरित कार्वाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सूखा के कारण बिजली आपूर्ति भी बाधित हो रही है, क्योंकि कम जल स्तर बांधों को प्रभावित करता है और फिर इससे स्वास्थ्य सुविधाओं सहित आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रभावित होता है। दोनों देशों में 1.2 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हैं। इनमें सीरिया के 50 लाख लोग शामिल हैं जो फरात नदी पर सीधे निर्भर हैं। इराक में फरात नदी और टाइग्रिस नदी से मिलने वाले जल तक पहुंच कम होने और सूखे के कारण कम से कम 70 लाख लोगों को खतरा है। समूहों ने कहा कि लगभग 400 वर्ग किलोमीटर (154 वर्ग मील) कृषि भूमि सूखे का सामना कर रही है। करीब 30 लाख लोगों को बिजली की आपूर्ति करने वाले उत्तरी सीरिया के दो बांध बंद होने के कगार पर है। चेतावनी देने वाले सहायता समूहों में शामिल नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल के क्षेत्रीय निदेशक कार्स्टन हैनसेन ने कहा कि सैकड़ों-हजारों इराकी अब भी विस्थापित हैं और सीरिया में कई अपना जीवन बचाने के लिए अब भी पलायन कर रहे हैं, ऐसे में जल संकट जल्द ही अभूतपूर्व तबाही बन जाएगा, जिससे विस्थापन और बढ़ेगा।

सफलता के लिए क्रैश कोर्स

प्रशांत शर्मा का कहना है कि एनईईटी क्रैश कोर्स आपको पाठ्यक्रम के समस्त विषयों को कम समावधि में कवर करने में सक्षम बनाता है और आपको ज्यादा आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में भाग लेने में मदद करता है

क्रैश कोर्स बहुत मददगार होते हैं। ऐसे कई छात्र हैं जिन्होंने क्रैश कोर्स में दाखिला लेने के बाद डेढ़ महीने के भीतर अपने अंकों में 30 प्रतिशत या 40 प्रतिशत का सुधार किया है।

अब, आप सोच सकते हैं कि छात्र कैसे परीक्षा के अंतिम कुछ महीनों में छात्रों में उल्लेखनीय सुधार कर लेते हैं?

क्योंकि जैसे-जैसे परीक्षा नजदीक आती है, छात्र अधिक एकाग्र और समर्पित होते जाते हैं। नीट उम्मीदवारों के लिए यह कठिन समय है क्योंकि परीक्षा नजदीक आ रही है। हालांकि तैयारी पूरी हो चुकी है और कई बार रिवीजन किया जा चुका है, फिर भी अधिकांश छात्र तनाव महसूस कर सकते हैं। यह तैयारी के दौरान कुछ विषयों को भूलने संबंधी उनके डर के कारण हो सकता है या यहां तक कि अगर उन्होंने अनुभाग पूरा कर लिया है, तो कुछ अनुभागों के प्रति उनमें स्पष्टता की कमी के कारण हो सकता है।

कारण जो भी हो, क्रैश कोर्स इस पहलू में छात्रों की मदद कर सकता है। न केवल उन छात्रों के लिए जिन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और रिवीजन की तलाश कर रहे हैं, बल्कि क्रैश कोर्स उन छात्रों की भी मदद करता है जिन्होंने अभी तक परीक्षा में क्वालीफाइंग अंक हासिल करने के लिए अपनी तैयारी शुरू नहीं की है।

क्रैश कोर्स उस सामान्य कोर्स से बिल्कुल अलग है जो महीनों या सालों तक चलता है। क्रैश कोर्स आमतौर पर लगभग चार महीने तक चलता है और कार्यकाल में संस्थान-दर-संस्थान भिन्न होता है। क्रैश कोर्स का सटीक अर्थ कोर्स को जल्दी से पूरा करने हेतु निर्देश का संक्षिप्त क्रम है।

उदाहरण के लिए, क्रैश कोर्स आपको दो साल के कोर्स को कुछ महीनों में पूरा करने में मदद कर सकता है। नीट क्रैश कोर्स आपको कुछ महीनों में पूरे सिलेबस को पूरा करने में मदद करता है।

क्या क्रैश कोर्स में शामिल होना उपयोगी है?

मूल्य की गणना आपको इससे प्राप्त लाभ के आधार पर की जाएगी। क्रैश कोर्स आपको पूरे एनईईटी पाठ्यक्रम की मुख्य अवधारणाओं को जल्दी से कवर करने में सक्षम बनाता है और आपको अधिक आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में भाग लेने में मदद करता है। क्रैश कोर्स उन छात्रों के लिए बेहद मददगार है, जिन्हें लगता है कि रिवीजन अनिवार्य है। यह आपको कम समय में सभी महत्वपूर्ण विषयों को सुधारने में मदद करता है। क्रैश कोर्स के दौरान, छात्रों को पाठ्यक्रम के संक्षिप्त संस्करण, अध्ययन सामग्री, प्रमुख अवधारणाएं और पूरे पाठ्यक्रम को कवर करने वाले मैराथन अध्याय प्रदान किए जाएंगे। कुछ बेहतरीन एनईईटी क्रैश कोर्स प्रशिक्षण संस्थान छात्रों को प्रश्न जल्दी हल करने के लिए टिप्स, ट्रिक्स और बेहतरीन शॉर्ट कट भी देते हैं।

> बोर्ड परीक्षाओं के विपरीत, नीट परीक्षा के अधिकांश प्रश्न उपयोग आधारित होते हैं और इसलिए छात्रों को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अलग दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। क्रैश कोर्स छात्रों को पर्याप्त अभ्यास और मॉक टेस्ट प्रदान करेगा और उन्हें अपने कौशल का मूल्यांकन करने में मदद करेगा

लाभ :

- **आपको ज्यादा अंक प्राप्त करने में मदद करता है**

बोर्ड परीक्षाओं के विपरीत, नीट परीक्षा के अधिकांश प्रश्न उपयोग आधारित होते हैं और इसलिए छात्रों को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अलग दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। क्रैश कोर्स छात्रों को पर्याप्त अभ्यास और मॉक टेस्ट प्रदान करेगा और उन्हें अपने कौशल का मूल्यांकन करने में मदद करेगा। यह अभ्यास छात्रों को अवसर देता है कि वे प्रश्नों को हल करने के सर्वोत्तम दृष्टिकोण को समझें और उनसे परिचित हों। यह आपको उन विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को समझने में भी मदद करता है जो एनईईटी परीक्षा, परीक्षा पैटर्न और उन क्षेत्रों में दिखाई दे सकते हैं जहां आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

- **समय बचाता है**

बोर्ड परीक्षा पास करना बहुत जरूरी है। यदि आप बोर्ड के लिए अधिक समय आवंटित करते हैं, तो आपके पास परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा रह सकता है। ऐसे में क्रैश कोर्स आपको प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए लंबी अवधि की कोचिंग में साल बर्बाद करने से बचने में मदद करेगा। नीट क्रैश कोर्स आपको कम समयावधि में सिलेबस के सभी विषयों को कवर करने में सक्षम बनाता है और आपको अधिक आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल होने में मदद करता है।

- **सभी महत्वपूर्ण विषय पढ़ाए जाते हैं**

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने नीट की तैयारी पर कितना समय बिताया है या आपने कितने विषयों को कवर किया है। लेकिन, महत्वपूर्ण विषयों पर आप जो समय बिताते हैं वह वास्तव में बहुत मायने रखता है। आपको सिलेबस को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए और उन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वपूर्ण विषयों को सूचीबद्ध करना चाहिए। क्रैश कोर्स संस्थानों के ट्यूटर्स को उन विषयों पर पूरी जानकारी होगी कि किन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और किन विषयों को छोड़ना चाहिए। तदनुसार, वे प्रश्नों का शीघ्र और सही उत्तर देने के लिए टिप्स और शॉर्टकट प्रदान करके आपकी तैयारी में आपका मार्गदर्शन करेंगे।

संक्षेप में, अधिकांश शीर्ष संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले क्रैश कोर्स सिलेबस में एनईईटी सिलेबस के सभी विषयों का रिवीजन, दैनिक या साप्ताहिक मॉक टेस्ट, समूचे सिलेबस की समीक्षा और संदेह समाधान सत्र शामिल हैं। कुल मिलाकर, क्रैश कोर्स आपको

सिलेबस में शामिल सभी विषयों को सीखने में मदद करता है और आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद करता है।

- लेखक नीट फिजिक्स कोटा के निदेशक हैं ।

व्यवहारगत योग्यताएं सीखना जरूरी

पीयूष नांगरू
सह-संस्थापक-सीओओ, सनस्टोन इडूवर्सिटी

पीयूष नांगरू का कहना है कि नवागंतुक अब अनुभवी पेशेवरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह स्थिति केवल शिक्षा पर आधारित नहीं, अवसरों की आक्रामक तैयारी पर जोर देती है

इस सारी अराजकता में, एक निश्चितता यह है कि कोविड तेजी से कामकाजी दुनिया को नया आकार दे रहा है। भारत में हर साल औसतन 3.5 लाख छात्र बी-स्कूलों से स्नातक होते हैं। 2020 में महामारी की शुरुआत, वेतन में कटौती और नौकरी छूटने से, नए प्रतिस्पर्धी अब रोजगार बाजार में अनुभवी पेशेवरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह न केवल व्यावसायिक शिक्षा, बल्कि गहरे आत्मसात की गयी व्यवहारगत योग्यताओं पर आधारित नौकरी के अवसरों हेतु आक्रामक तैयारी करने, पर जोर देता है।

अच्छी खबर यह है कि जहां स्नातकों के लिए प्रतिस्पर्धा अधिक है, वहीं 2020 में देखी गई कम रोजगार दर की तुलना में इस वर्ष अवसरों में भी लगातार वृद्धि हुई है। ये संख्या बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि कंपनियां ठप्प सी हो गयी नियुक्ति गतिविधियों को दुबारा शुरू करने की योजना बना रही हैं। हालांकि, व्यावसायिक स्नातकों को काम पर रखने के प्रति एक स्थिर झुकाव है जो सैद्धांतिक शिक्षा के माध्यम से नहीं बल्कि अवधारणाओं, व्यवहारिक योग्यताओं, संचार, समस्या-समाधान और डिजिटल अनुकूलन क्षमता के व्यावहारिक अनुप्रयोग में माहिर हैं।

कंपनियों के लिए, बड़े नियुक्तिकारी जनादेश और कम बजट का मतलब हो सकता है कि नवागंतुकों के प्रति उनकी धारणा को जल्दी से बदलाव करना पड़े। लेकिन उनकी चिंता जस की तस बनी हुई है। क्या ये नए स्नातक उन योग्यताओं में सक्षम हैं जिनकी उद्योग अब मांग कर रहा है?

योग्यताओं को निखारना संस्थानों की जिम्मेदारी है। वे निम्नलिखित सिद्धांतों को अपना करके ऐसा कर सकते हैं।

उच्च शिक्षा में जवाबदेही : प्रबंधन के क्षेत्र में, प्लेसमेंट हर उस स्नातक के लिए एक शो-स्टॉपर है जो कॉर्पोरेट जगत में प्रवेश करना चाहता है। बी स्कूल इस काम को, कॉरपोरेट्स के साथ संबंध बनाने के साथ-साथ, अपने छात्रों की योग्यताओं व उपलब्धियों की विश्वसनीयता बनाने पर तीव्र ध्यान देकर व छात्रों के प्लेसमेंट के प्रति जवाबदेह बनकर, बढ़ा सकते हैं। यह छात्र के अपने कार्यस्थल पर आने के पहले दिन से ही ज्यादा कॉर्पोरेट-छात्र संपर्क को बढ़ावा देगा।

व्यावहारिक शिक्षा : पाठ्यक्रम संरचना को प्रौद्योगिकी द्वारा बताए गए शिक्षण के अधिक व्यावहारिक तरीके प्रोत्साहित करने चाहिए। महामारी के दौरान प्रौद्योगिकी पर हमारी निर्भरता और डिजिटल साक्षरता की सख्त जरूरत सामने आई थी। इससे सीखते हुए, प्रबंधन पाठ्यक्रम को डिजिटल माध्यमों की सहजता और उपयोग का प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है। यह संगठनों में तकनीक से संबंधित परिवर्तनों के मद्देनजर छात्रों को अधिक जागरुक होने में भी मदद करेगा।

अनुरूप पाठ्यक्रम : बी स्कूलों को एक विशिष्ट पाठ्यक्रम संरचना का प्रचार करने के लिए एक सर्वानुकूल दृष्टिकोण से बदलाव करने की आवश्यकता है जो डोमेन-विशिष्ट और भूमिका-विशिष्ट अवधारणाओं को प्राथमिकता देता है। यह पाठ्यक्रम प्रौद्योगिकी पर आधारित हो जो प्रत्येक छात्र को अनुकूलित शिक्षण के जरिए प्रदान हो। इसके माध्यम से, छात्र अपनी क्षमताओं और कमजोरियों से वाकिफ हो जाते हैं और उन्हें वास्तविक दुनिया में अपने शिक्षण को लागू करने का मौका मिलता है ताकि वे खुद देख सकें कि क्या कारगर है और क्या नहीं।

इस तरह का अनुरूप शिक्षण रूझान छात्रों में पेशेवर प्रगति लाने में सहायता प्रदान करता है और उद्योग की मांगों और व्यवहारगत योग्यताओं के बीच की खाई को पाटता है।

इस दृष्टिकोण के साथ, गेम-चेंजिंग स्किल्स और गिग-इकोनॉमी की शुरुआत होने से, एचआर दूरस्थ पदों के लिए सहज नियुक्ति कार्य करने में अग्रणी हो सकते हैं और कॉरपोरेट्स कम लागत के साथ, विशेष रूप से बुनियादी संरचना मोर्चे पर कामयाब हो सकते हैं। काम के भविष्य और दूरस्थ कामकाज की दिशा में इस सुचारु परिवर्तन के लिए, कॉरपोरेट्स को भी विश्वास की छलांग लगाने और उद्योग के लिए तैयार पेशेवरों के रूप में नए लोग तलाशने की जरूरत है। सही व्यवहारगत योग्यताओं के साथ चुनौतियों का सामना करने हेतु तैयार स्नातकों का प्रतिभा भंडार प्रदान करने का यह काम बड़े पैमाने पर बी-स्कूलों के नेतृत्व में किया जाएगा।

राह दिखाता है एमबीबीएस

विशु त्रिपाठी का कहना है कि दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो छात्रों के लिए एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए आदर्श माने जाते हैं

भारत में हर मेडिकल उम्मीदवार भारत में प्रवेश लेना चाहता है, लेकिन सीटें सीमित हैं। भारत में मेडिकल कॉलेजों में केवल 84,000 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं और 14 लाख छात्र नीट परीक्षा में भाग लेते हैं। इससे मेडिकल छात्रों के लिए प्रवेश लेना कठिन हो जाता है और उस स्थिति में, वे विदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई करने का फैसला करते हैं।

यह मेडिकल छात्रों के लिए एक बेहतर विकल्प माना जाता है। सस्ती फीस के अलावा, सरकार और शीर्ष चिकित्सा विश्वविद्यालय, वैश्विक काम करने के अवसर, छात्र बिना किसी दान के आसानी से प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। भारत के विपरीत, विदेशी चिकित्सा विश्वविद्यालयों में पर्याप्त चिकित्सा सीटें हैं। यह अंतरराष्ट्रीय छात्रों से आवेदन स्वीकार करते हैं।

महामारी के दौरान इस पेशे की काफी मांग हो जाती है। सभी ने महसूस किया कि चिकित्सा विज्ञान वो क्षेत्र है जिसकी कोविड-19 के दौरान बहुत ज्यादा मांग है। भारत में निजी मेडिकल कॉलेजों की महंगी ट्यूशन फीस के कारण कई छात्र मेडिकल कोर्स करने से पीछे हट जाते हैं। दूसरी ओर, छात्र छात्रावास और मेस शुल्क, सहित या रहित, 12 से 25 लाख रुपये के बीच विदेश में अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरा कर सकते हैं।

दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो भारतीय छात्रों के लिए विदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई करने हेतु आदर्श माने जाते हैं। उनमें से कई देशों ने आर एंड डी के लिए शिक्षा प्रणाली में काफी निवेश किया है। इसके कारण चिकित्सा शिक्षा काफी सस्ती है।

भारत बनाम विदेश में एमबीबीएस की अवधि

देशों के बीच एमबीबीएस अध्ययन की अवधि भिन्न होती है। छात्र भारत में सिर्फ पांच साल और पांच महीने में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। जिसमें कि प्रशिक्षण या इंटर्नशिप अवधि (12 महीने) शामिल होती है। दूसरी ओर, रूस, चीन या यूक्रेन जैसे देश अनुभवी पेशेवरों के अधीन इंटर्नशिप सहित छह साल (लगभग) की अवधि प्रदान करते हैं।

भारत बनाम विदेश में एमबीबीएस का अध्ययन करने के प्रमुख लाभ

सस्ती फीस : भारत में एमबीबीएस फीस 40 से 50 लाख रूपए (निजी मेडिकल कॉलेज) से शुरू होती है। इसकी तुलना में यूक्रेन जैसे विकसित देशों में एमबीबीएस की फीस 14 से 25 लाख रुपये के बीच है।

- **विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा :** ऐसा नहीं कि भारत में छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए सभी कॉलेजों के अपने अस्पताल हैं। दूसरी ओर, अनुभवी चिकित्सा पेशेवरों के अधीन उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय के अस्पताल में प्रशिक्षण मिलेगा।
- **शीर्ष रैंकिंग वाले मेडिकल कॉलेज :** भारत के अधिकांश कॉलेजों की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग सूची में निम्न रैंकिंग है। दूसरी ओर, 30 रूसी चिकित्सा विश्वविद्यालय दुनिया के शीर्ष 100 चिकित्सा विश्वविद्यालयों में सूचीबद्ध हैं।

छात्र विदेश में प्रवेश कैसे ले सकते हैं?

जब मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने की बात आती है तो यह सब नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर निर्भर करता है। उसके बाद अगला कदम यह है कि नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में आपकी कितनी अच्छी रैंक है। अंत में, काऊंसलिंग और फिर बाकी प्रवेश प्रक्रिया। कॉलेज अपनी कट-ऑफसूची निर्धारित करते हैं और केवल उन्हीं छात्रों का चयन करते हैं जो उन मानदंडों के अंतर्गत आते हैं।

दूसरी ओर, नीट रैंक, विदेश में एमसीआई या एनएमसी द्वारा अनुमोदित चिकित्सा विश्वविद्यालयों में एमबीबीएस प्रवेश में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। भारत के बाहर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए कोई पूर्वनिर्धारित कटऑफ नहीं होगी। उम्मीदवारों को सिर्फ अपनी पात्रता साबित करने की जरूरत है, बस।

एक मिथक है जिसे हर छात्र ने सुना होगा कि विदेश में एमबीबीएस के लिए वही छात्र आवेदन करते हैं जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं। यह बात पूरी तरह से निराधार है। 550 से अधिक स्कोर करने वाले छात्र विदेशों में शीर्ष मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश हेतु आवेदन कर रहे हैं। इसका कारण यह कि प्रतिस्पर्धा उच्च स्तरीय है।

यूक्रेन, रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश और जॉर्जिया जैसे देशों के कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है। केवल शर्त यह है कि आप पात्रता पूरी करें और केवल नीट परीक्षा पास करें। अधिकांश लोकप्रिय विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और उस देश की स्थानीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है। मेडिकल डिग्री भारत व अन्य देशों में भी मान्य है। भारत में प्रैक्टिस करने के लिए छात्रों को विदेश में एमबीबीएस के बाद एफएमजीई परीक्षा पास करनी होती है।

- लेखक एफिनिटी एजूकेशन के सीईओ और संस्थापक हैं।

अधिक अवसरों के लिए सीखें स्पेनिश

भारत और अन्य देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक संबंधों से, अंग्रेजी के अलावा विदेशी भाषाओं के प्रति झुकाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस बीच, स्पेनिश ने, जो दुनिया में मंदारिन के बाद दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, हाल के दिनों में भी बड़े पैमाने पर प्रमुखता प्राप्त की है।

जैसे-जैसे दुनिया दिन-ब-दिन ज्यादा जुड़ती और निर्भर होती जा रही है, भाषा सीखने के लाभ आज पहले से कहीं अधिक हैं। विदेशी भाषा की लगातार बढ़ती मांग ने अपने करियर को आवश्यक बढ़ावा देने के लिए भाषा का चुनाव करने वाले छात्रों की संख्या में भारी वृद्धि की है।

हालांकि भारत में ऐसे कई संस्थान हैं जो सर्वश्रेष्ठ स्पेनिश शिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, मगर हम स्पैनिश झुकाव के लिए सर्वोत्तम पांच संस्थानों को सूचीबद्ध करके आपकी पसंद को थोड़ा आसान बनाना चाहते हैं। यदि आप इसमें से किसी में करियर बनाने की इच्छा रखते हैं, तो आप निश्चित रूप से इन पाठ्यक्रमों पर विचार करना चाहेंगे।

हेनरी हार्विन : जो लोग स्पेनिश सीखकर अपने करियर में अतिरिक्त सितारे जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भारत की प्रमुख एड-टेक कंपनी हेनरी हार्विन, जो कि कुणाल गुप्ता द्वारा स्थापित है, द्वारा पेश किया जाने वाला यह स्पेनिश प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सबसे व्यवहारिक विकल्प है। हेनरी हार्विन द्वारा स्पेनिश भाषा प्रशिक्षण का उद्देश्य उम्मीदवारों के पारस्परिक कौशल को बढ़ाना है। इसे इंटरमीडिएट स्तर पर स्पेनिश भाषा के उत्कृष्ट ज्ञान के साथ शिक्षार्थियों को परिचित कराने के लिए सोच-समझकर तैयार किया गया है।

इस प्रशिक्षण सत्र को छह स्तरों में बांटा गया है - ए1-ए2, बी1-बी2 और सी1-सी2। इस कोर्स को सबसे सम्मानित तथा 15 वर्षों का कार्य अनुभव रखने वाले उद्योग विशेषज्ञों द्वारा पूरा कराया जाता है जिनको स्पेनिश में लंबे भाषणों को संयोजित करने और वितरित करने का कौशल प्राप्त हैं। इस पाठ्यक्रम के सफल समापन से आप स्पेनिश भाषा प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं जिसके बाद नियमित बूटकैंप और इंटर्नशिप के अवसर मिलते हैं।

कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट : कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत स्पैनिश लर्निंग कोर्स आम यूरोपीय फ्रेम वर्क (सीईएफ) का अनुसरण करता है जो स्पैनिश को ए 1, ए 2, बी 1, बी 2, सी 1 और सी 2 सहित छह स्तरों में विभाजित करता है। सभी छह स्तर छात्रों को भाषा की प्रत्येक बारीक अवधारणा में प्रशिक्षित करते हैं, बुनियादी रोजमर्रा के भावों से लेकर अपने विचारों को धाराप्रवाह और सहज रूप से व्यक्त करने तक।

संस्थान एफआईडीईएससीयू का एक संबद्ध केंद्र है और डी आई ई (इंटरनेशनल ऑफ स्पेन का डिप्लोमा) के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह सर्टीफिकेशन छात्रों को अपने ज्ञान का परीक्षण करने और अपने स्पेनिश बोलने के कौशल को प्रभावी ढंग से धारदार करने का अवसर देता है।

इंस्टीट्यूटो हिस्पेनिया : 1997 में स्थापित, इंस्टीट्यूटो हिस्पेनिया दिल्ली के सबसे पुराने स्पेनिश संस्थानों में से एक है, जो छात्रों को उच्च स्पेनिश भाषा योग्यता प्राप्त करने हेतु एक असाधारण और उच्च गुणवत्ता वाली कक्षा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है।

इंस्टीट्यूटो हिस्पेनिया के पूरे कोर्स को तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिन्हें आगे हिस्पैनिक ऊनो (।1) से लेकर हिस्पैनिक ओचो (ब1) तक, कुल 8 स्तरों में विभाजित किया गया है। देशी और अनुभवी प्रशिक्षक, पूर्णतया सुव्यवस्थित कक्षाएं, विशेष अध्ययन सामग्री, प्रभावी शिक्षण पद्धति, अनुकूल वातावरण और कुछ प्रमुख कारक जो आसानी से कोर्स को महत्वपूर्ण साबित करते हैं।

इंस्टीट्यूटो सर्वेन्टेस: स्पेन सरकार से संबद्ध, इंस्टीट्यूटो सर्वेन्टेस स्पेनिश सीखने का एक और लोकप्रिय संस्थान है। इंस्टीट्यूटो सर्वेन्टेस द्वारा प्रस्तुत यह कोर्स केवल भाषा सीखने से कहीं बढ़कर है, यह स्पेनिश-भाषी संस्कृतियों की विस्तृत श्रृंखला का अनुभव करने और उनसे परिचित होने का अवसर है।

संस्थान का अपना सिलेबस है जो विविध स्पेनिश भाषी समुदायों में पाई जाने वाली विविधता का सम्मान करते हुए सार्वभौमिक, अच्छी तरह से बोली जाने वाली स्पेनिश के शिक्षण के लिए उपयुक्त नींव स्थापित करता है।

लेंग्वेज नेक्स्ट : लेंग्वेज नेक्स्ट एक विदेशी भाषा संस्थान है जो छात्रों को उनके भाषाई स्तर की परवाह किए बिना स्पेनिश भाषा का प्रशिक्षण प्रदान करता है। कोर्स का उद्देश्य एक पेशेवर और मैत्रीपूर्ण वातावरण में अंतर-सांस्कृतिक शिक्षा, व्यक्तिगत स्तर परध्यान देकर, और गतिशील शिक्षण विधियों के माध्यम से द्वितीय भाषा निर्देश और हिस्पैनिक संस्कृति की गहरी समझ के रूप में उच्च गुणवत्ता और प्रभावी सत्र प्रदान करना है।